CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. VIII, Fourth Session, 2010/1932 (Saka)
No. 19, Tuesday, April 20, 2010/ Chaitra 30, 1932 (Saka)

SUBJECTS	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No. 341 to 344	2-37
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 345 to 360	38-80
Unstarred Question Nos. 3875 to 4104	81-578

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 519-530

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
6th Report 531

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
3rd and 4th Reports 531

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
2nd and 3rd Reports 531

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
4th to 6th Reports 532

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
219th and 220th Reports 532

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
154th and 155th Reports 533

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 2989, DATED 08.12.2009 REGARDING 'DECONTROL OF SUGAR SECTOR' ALONGWITH GIVING REASONS FOR DELAY
Prof. K.V. Thomas 534

STATEMENT UNDER RULE 199
Personal explanation by a Member in regard to resignation from the office of Minister of State in the Ministry of External Affairs
Dr. Shashi Tharoor 535-537

SUBMISSION BY MEMBER

Need to address the problems being faced by victims affected due to natural calamities in Bihar 543-546

FELICITATIONS TO HON. DEPUTY SPEAKER ON HIS BIRTHDAY 557

MATTERS UNDER RULE 377 558-573

(i) Need to announce a special rehabilitation scheme for the people whose land is being acquired for the development of National Highway in Kerala.

Shri K.C. Venugopal 558

(ii) Need to make Yamuna river pollution free.

Shri Jai Prakash Agarwal 559

(iii) Need to open a new Railway Station at Maharajanagar on Tirunelveli-Tiruchendur Section in Tamil Nadu.

Shri S.S. Ramasubbu 560

(iv) Need to accord approval to the proposal of Governemnt of Rajasthan to introduce metro train in Jaipur.

Shri Mahesh Joshi 561

(v) Need to resotre Athoor Anicut Channel in Athoor village of Dindigul district, Tamil Nadu.

Shri N.S.V. Chitthan 562

(vi) Need to direct Bhakra Beas Management Board to release water to Rajasthan.

Shrimati Chandresh Kumari 563

(vii) Need for central assistance to construct another Legislative Assembly of Uttrakhand at Gairsain.

Shri Satpal Maharaj 564

(viii) Need to maintain only one toll plaza in Dindori Parliamentary Constituency, Maharashtra and stop collecting toll tax in tribal areas.

Shri Harishchandra Chavan 565

(ix) Need to undertake developmental works in tribal areas and allot forest land to Adivasis in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat.

Shri Mansukhbhai D. Vasava 565

(x) Need to provide adequate medical facilities to rural expectant mothers under National Rural Helath Mission in the country.

Shrimati Sushila Saroj 566

(xi) Need to constuct a permanent bridge on river Ghaghra at Kamhariya Ghat in Sant Kabir Nagar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Bhishma Shankar *alias* Kushal Tiwari 567

(xii) Need to consult local M.Ps. in construction of roads and bridges under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

Shri Sushil Kumar Singh 568

(xiii) Need for early revival of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, Haldia Division, West Bengal.

Shri Suvendu Adhikari 569

(xiv) Need to include differently abled persons in the ambit of Right to Education Act.

Shri D. Venugopal 570

(xv) Need to expedite the implementation of welfare programmes for minorities including the proposals of the Ranganath Mishra Commission.

Shri Mohammed E.T. Basheer 571

(xvi) Need to mitigate the problems of villages residing along border in Balurghat Parliamentary Constituency, West Bengal.

Shri Prasanta Kumar Majumdar 572

(xvii) Need to amend Securitisation Act, 2002 providing for relief and exemption to the Rubber Plantation sector from attachment of collateral in the event of non-payment of farm loan.

Shri Jose K. Mani 573

DEMAND FOR GRANT(GENERAL)- 2010-11 574

Ministry of External Affairs

Dr. Murli Manohar Joshi 575-587

Shri Deepender Singh Hooda 588-597

Shri Mulayam Singh Yadav 596-601

Shri Vijay Bahadur Singh 602-606

Shri Sudip Bandyopadhyay 607-612

Shri Pinaki Misra 613-618

Shri Chandrakant Khaire 619-621

Shri A. Sampath 622-626

Yogi Aditya Nath 627-631

Shri Adhir Chowdhury	632-636
Dr. Prasanna Kumar Patasani	637-639
Shri Nama Nageswara Rao	640-644
Shri Abdul Rahman	645-648
Shri C. Sivasami	649-652
Shri J.M. Aaron Rashid	653
Shri Prabodh Panda	654-656
Dr. Rattan Singh Ajnala	657
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	658-661
Shri Madhu Goud Yakshi	662-665
Dr. Mirza Mehboob Beg	666-668
Shri Mohammed E.T. Basheer	669-671
Shri M.I. Shanavas	672-674
Shri Prasanta Kumar Majumdar	675-676
Shri Asaduddin Owaisi	677-680
Dr. Thokchom Meinya	681-682
Shri Arjun Ram Meghwal	683-684
Shri Shailendra Kumar	685-686
Shri Jagdambika Pal	687-688
Shri S.M. Krishna	689-696
Demand for Grant – Voted	697

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	699
Member-wise Index to Unstarred Questions	700-703

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	704
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	705

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY-GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, April 20, 2010/ Chaitra 30, 1932 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

(Q. No. 341)

MADAM SPEAKER : Q. No.341, Shri Lalchand Kataria.

श्री लालचन्द कटारिया : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो जवाब दिया है, उस संबंध में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों से राजमार्गों के नये प्रस्ताव आते हैं, मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं, तो उनके नौ प्रस्ताव आपके विभाग में विचाराधीन हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उन नये राजमार्गों की घोषणा कब तक करेंगे?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ): अध्यक्ष महोदया, नये नैशनल हाईवेज की स्वीकृति के लिए कुछ नियम और आधार हैं। अभी यह तय किया गया है कि दस हजार किलोमीटर के सैद्धांतिक रूप से नये नैशनल हाईवेज की घोषणा की जायेगी। बहुत सारे प्रस्ताव, लगभग 50 हजार किलोमीटर के प्रस्ताव अभी केन्द्र के पास विभिन्न राज्यों से आये हैं और इन पर अभी विचार किया जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से यह तय किया जायेगा कि कौन से मार्ग हैं, जिनका प्रस्ताव भेजा है, उनको नैशनल हाईवेज में कन्वर्ट किया जाये। हमें उम्मीद है कि अगले तीन महीनों में हम इसे तय कर पायेंगे।

श्री लालचन्द कटारिया : आदरणीय अध्यक्षा जी, क्या केन्द्र सरकार टू लेन को अपग्रेड कर टोल वसूलने वाली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और उसके तहत सड़क निर्माण का मामला है, उसे आप दो लेन की न करके चार लेन की करे, जिससे आम जनता को सुविधा रहे और जो टोल वसूला जाता है, उससे जनता को राहत मिले, इस बारे में आपका क्या कहना है?

श्री कमल नाथ: मैडम, टू लेन और चार लेन का फैसला ट्रैफिक के आधार पर होता है कि उस सड़क पर कितना ट्रैफिक है और आगे आने वाले समय में ट्रैफिक प्रोजेक्शन क्या है? जहां पन्द्रह हजार या सोलह हजार पीसीयू से ज्यादा होता है, तो वहां चार लेन की बात की जाती है। जहां तक टोल की बात है, इसमें सड़कें टोल पर भी बनायी जाती हैं और एन्यूटी पर भी बनायी जाती है। इसके साथ-साथ यह भी निर्भर करता है कि उस पर क्या ट्रैफिक है?

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कई प्रोजैक्ट्स इस वक्त समय से पीछे चल रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि एक महीने से लेकर तीन-चार वर्ष पीछे तक कई प्रोजैक्ट्स इस समय चल रहे हैं। मुझे यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि बीओटी टोल के माध्यम से आप प्रोजैक्ट्स को कांट्रेक्ट पर देना चाहते हैं। उसकी बीडिंग बीओटी टोल के माध्यम से होती है, तो ज्यादा कांट्रेक्टर्स नहीं आते। विशेष रूप से उन स्ट्रेचेस पर जहां पर हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक नहीं है।

वह नेचुरल कि बीओटी या एनुइटी बेसिस पर आपको देना पड़ता है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि कई ऐसी रोड्स हैं, कई ऐसे स्ट्रेचेज हैं जहां लोग बीओटी टोल के माध्यम से लेने को तैयार नहीं हैं, बीओटी एनुइटी के माध्यम से भी लेने को तैयार नहीं हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपके सामने होता है सीसीईए के एप्रूवल लेने के बाद आप उसे दे सकते हैं। क्या आप इस संबंध में विचार कर रहे हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स समय से पूरे हो जाएं यदि कोई बीओटी टोल या बीओटी एनुइटी के माध्यम से लेने को तैयार नहीं है तो सीसीईए का एप्रूवल लेकर उन सारी सड़कों को बनाएंगे? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने आपको सुझाया था कि मल्टी कंसेशन पर एग्रीमेंट का क्लॉज-29 है, उस क्लॉज को लेकर आपने भी आपत्ति व्यक्त की थी और एनएचएआई ने भी अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। क्या क्लॉज-29 को आप उस एग्रीमेंट से डिलीट कर रहे हैं? मुझे क्लॉज-29 के बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि श्री बी.के. चतुर्वेदी की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी थी, उसने भी यह रिकमेंड किया है कि इस क्लॉज के कारण प्राब्लम्स आ रही हैं, इसे डिलीट किया जाए। मैं आपसे इन विषयों पर जानकारी चाहूंगा।

श्री कमल नाथ : महोदया, माननीय सदस्य की बात सही है कि पहले टोल पर बिडिंग मंगाई जाती है। हमारा लक्ष्य है कि लगभग 60 प्रतिशत बीओटी टोल पर हो, 25 प्रतिशत एनुइटी पर हो और 15 प्रतिशत ईपीसी पर हो। जब टोल पर बिड मंगाई जाती है और बिड नहीं आती है, कई ऐसे उदाहरण हैं कि बहुत सी जगहों पर एक भी बिड नहीं आई, तब हम उसे एनुइटी में कंवर्ट करते हैं। माननीय सदस्य की यह बात भी सही है कि कभी एनुइटी में भी बिड नहीं आती है, तब हमें उसे ईपीसी पर ट्रांसफर करना पड़ता है। यह बात सही है कि इस प्रक्रिया में काफी समय निकल जाता है। पहले तीन-चार या पांच महीने बिड मंगाने में लगते हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन होता है, उसके बाद प्राइस बिड होती है, फिर उसकी एनुइटी वाली प्रोशेस शुरू की जाती है। अगर उसमें सफलता न मिले तब हम ईपीसी पर जाते हैं। ऐसे उदाहरण जहां एनुइटी के लिए बिड नहीं आई हैं, हैं जरूर, लेकिन कम हैं। इसका एक कारण है कि जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, एनुइटी प्रोजेक्ट कॉस्ट पर फिक्स की जाती है और जहां हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट में यह एहसास हो कि वह सही नहीं है तो हमारी एनुइटी में भी बिड नहीं आती है। इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं ताकि हमारी कोई बिड फेल न हो।

जहां तक क्लॉज-29 की बात है, मुझे याद नहीं है कि इसमें क्या प्रावधान है। I will inform the hon. Member

MADAM SPEAKER: Sure, you should inform him later.

श्री रामकिशुन : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एक निश्चित सीमा के तहत कराया जाना है, उन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण अभी तक क्यों पूरा नहीं हो सका है? मेरे क्षेत्र से एनएच-2 से राजा जमनिया होते हुए गाजीपुर, गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग चार वर्षों से लगातार निर्माण कार्य हो रहा है, लेकिन एक तरफ सड़क बन रही है और दूसरी तरफ वह राष्ट्रीय राजमार्ग खराब होता जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराकर उस राष्ट्रीय राजमार्ग को तत्काल पूरा कराने का काम करेंगे।

कुँवर आर.पी.एन.सिंह : महोदया, माननीय सदस्य ने नेशनल हाइवे-2 की बात की, उसको अभी हमने टू-लेन या फोर-लेन के एनएचडीपी प्रोग्राम में नहीं लिया है। नेशनल हाइवे-2 पर हम मेंटिनेंस का काम करते हैं, रिपेयर का काम करते हैं। ...(व्यवधान) मेंटिनेंस में अगर किसी पर्टीकुलर स्ट्रेच में माननीय सदस्य को लग रहा है कि काम ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें लिखित में उसकी जानकारी दें, हम उसे तत्काल दिखवा कर उस पर अच्छा काम कराने की व्यवस्था करेंगे।

श्री विजय बहुगुणा : अध्यक्ष महोदया, जो हिल्स स्टेट्स हैं हिमालय घाटी में, वहां का विकास बहुत हद तक पर्यटन और जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्भर करता है। इन राज्यों में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और उसे सुदृढ़ करने के लिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हिमालय हाईवे का प्रस्ताव किसी वक्त सरकार के पास विचाराधीन था, क्या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है?

श्री कमलनाथ: अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में बहुत सी हिल्स स्टेट्स हैं। वहां पर अलग-अलग योजनाओं में एनएचडीपी के तहत प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। जिन राज्यों में कोई नेशनल हाईवे नहीं है, इन हिल्स स्टेट्स की मदद सीआरएफ के माध्यम से भी हम करते हैं। जो हिल्स स्टेट्स हैं, हम प्रयास करते हैं कि उन्हें प्राथमिकता दी जाए और विभिन्न सेक्शन्स में इनके लिए योजनाएं बनाई जाएं।

SHRI C. SIVASAMI : Madam, in my Tirupur Parliamentary Constituency, the NH-47 from Chengapalli to Walayer is about to be upgraded as a six-lane track. While taking the private lands for the construction of the road, and while fixing the rates to the private lands, it is found that the land value is very much below the market value. Hence, the farmers are severely affected. So, while taking the private agriculture lands for the road development works, would the hon. Minister come forward to give the market value for the private agriculture lands?

SHRI KAMAL NATH: Madam, the acquisition is done under the NH Act and generally we are using the State Government officials as the Settlement Officers.

It is the State Government who is designated as the Settlement Officer, who executes the process of acquisition of land. Should there be any specific case where there is under valuation of land, uptill now there are very few cases which have come to my notice – where there is a belief that there is under valuation of land, hon. Member may write to me, and I would take this up with the NHAI, who would then take it up with the Settlement Officer.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Roads are declared as National Highways long back, a decade back – like NH-60 and NH-60A. But no improvement has been done on these roads which were declared as National Highways long back. I would like to know from the hon. Minister whether the widening and strengthening and making it from one lane to two lane,whether the Government would sanction those roads, which were declared as the National Highways for widening and strengthening of those roads and also rebuilding of the bridges which were in a very dilapidated condition.

SHRI KAMAL NATH: Road can only be widened, if the right of way land acquisition is there… . … (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Land is available. … (*Interruptions*) Permission is not required.

SHRI KAMAL NATH: I must seek the hon. Member's assistance in this that one of the States which is the slowest in land acquisition is West Bengal.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am referring to the National Highway where acquisition is not required at all. … (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : They can only abuse Kumari Mamata Banerjee. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Give the hon. Minister time to answer.

---

* Not recorded

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : You are not doing anything to strengthen the widening of the roads. … (*Interruptions*) I am talking of NH-60 and NH-60A. … (*Interruptions*)

SHRI KAMAL NATH: I will be happy to share with the hon. Member and also seek his assistance that one of the slowest progress in any of the States in National Highways construction is West Bengal. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

SHRI KAMAL NATH: I am seeking your help.

MADAM SPEAKER: Let the hon. Minister finish his reply.

… (*Interruptions*)

MADAM SPAKER: Let him complete his answer.

… (*Interruptions*)

SHRI KAMAL NATH: I was only seeking the help of the hon. Member. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All right. Is that all?

SHRI KAMAL NATH: Madam, I am only seeking the help of the hon. Member. I will be happy to share with him the progress of roads in West Bengal. … (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : My question is specific and I expect the reply should also be specific. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Thank you very much hon. Minister.

Let us move on to the next question. Q. No. 342.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let us have some order in the House.

… (*Interruptions*)

* Not recorded

(Q. No. 342)

श्रीमती उषा वर्मा : अध्यक्ष महोदया, नकली शराब और अन्य अवैध धंधे क्षेत्रीय पुलिस की सांठ-गांठ से होते हैं। क्षेत्रीय पुलिस को सारी जानकारी होती है कि अवैध धंधे कहां-कहां होते हैं। अगर वे लोग अपना अवैध धंधा बंद भी करना चाहते हैं, चूंकि पुलिस वालों का महीना बंधा होता है, इसलिए वे अवैध कार्य करने वाले लोगों को प्रेरित करती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ऐसी घटना की जानकारी मिलने पर क्या कभी पुलिस के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं और हम सब लोग जानते हैं कि एंट्री-8, लिस्ट-II के अंदर इनटोक्सीकेटिंग लीकर्स हैं, वे प्योरली स्टेट्स सब्जेक्ट हैं। बल्कि लॉ एंड पब्लिक आर्डर भी स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए राज्य सरकारों को इसे और मजबूती से चैक करना चाहिए।

श्रीमती उषा वर्मा : अध्यक्ष महोदया, नकली शराब और दूसरे अवैध धंधे अधिकतर गरीब और बेरोजगार लोग ही करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या कभी सरकार ने ऐसे लोगों को चिह्नित करके उन्हें कोई अन्य रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई है?

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से मिनिस्टरी आफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस तरह के कार्य करने के लिए एनजीओज़ को प्रेरित करती है। एक स्कीम है फार प्रिवेंशन आफ एल्कोहलिज्म एंड सब्सटांस (ड्रग) एब्यूज, इसके साथ इंटिग्रेटिड रिहेब्लीटेशन सैंटर्स फार एडिक्ट्स, इन दोनों स्कीम्स के माध्यम से केंद्र सरकार अलग-अलग एनजीओज़ को जागरुकता फैलाने के लिए मदद करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या और सदन को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2009-10 में लगभग 262 आईआरसीए के सैंटर्स थे और लगभग 22.79 करोड़ रुपया इसके लिए वितरित भी किया गया है।

श्री नीरज शेखर : महोदया, आप कह रहे हैं कि यह स्टेट का मैटर है। लेकिन केंद्र सरकार कम से कम ऐसे कानून बना सकती है, जिससे कि इसे रोका जा सके। कुछ कड़े कानून सरकार को बनाने चाहिए। आपने जैसा उत्तर दिया है, उसके अनुसार जहरीली शराब और अवैध शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है, जिससे कि इस पर रोक लग सके? मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि जहरीली शराब पीकर गरीब व्यक्ति मारे जाते हैं। क्या ऐसे लोगों के परिवार वालों को किसी प्रकार का अनुदान देने का विचार केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय रखता है?

श्री अजय माकन : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य और सदन को बताना चाहता हूं कि एक्साइज एक्ट के तहत और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत राज्य सरकारें कार्यवाही करती हैं। जब इस प्रकार की मृत्यु होती है, तो भी राज्य सरकारें कार्यवाही करती हैं।

एक्साइज एक्ट के तहत वर्ष 2008 में 1,25,085 लोगों के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई हुई। प्रोहिबिशन एक्ट में वर्ष 2008 में 1,94,171 लोगों के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई हुई और इस तरह से कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकारें एग्रेसिवली एक्शन लेती है, हिस्सा लेती हैं तो वे कंट्रोल भी कर पाते हैं।

श्री शरीफ़ुद्दीन शारिक : अध्यक्ष महोदया, सवाल में कहा गया है कि गरीब लोग शराब पीते हैं और यह भी कहा गया कि मरने पर मुआवजा दिया जाए। मैं नहीं समझता हूं कि कोई शराब पिए और खुद मरने की तमन्ना करे। सरकार की क्या स्ट्रेटजी है कि उसे मुआवजा दे? मैं यह कहूंगा कि जो शराब पिए और शराब से मरे, हिन्दुस्तान की परंपरा को खराब करे उसे सख्त से सख्त सजा मरने के बाद भी देनी चाहिए।

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शराब से मृत्यु होती है। माननीय मंत्री जी यह बताएं कि आखिरकार मृत्यु शराब से होती है या उसके अंदर खराब शराब से होती है? शराब पीने में अमीर और गरीब का सवाल नहीं है। शराब तो सभी लोग पीते हैं, बहुत से वर्ग के लोग पीते हैं लेकिन सबसे ज्यादा गरीब लोगों की मृत्यु होती है। सूचना यही मिलती है कि मजदूर मर गए। मैं पूछना चाहता हूं कि असली शराब पीने से मृत्यु होती है या खराब शराब पीने से होती है? मैं विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है और इसके प्रयोग से गरीबों की भी मृत्यु हो रही है। इसके साथ सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड शराब के माध्यम से अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो वह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं समझता हूं कि जो जानें जा रही हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है और शराब से जो पैसा कमाया जा रहा है, मंत्री जी इन सबके बारे में कुछ कहेंगे।

श्री अजय माकन: अध्यक्ष महोदया, मृत्यु और ऐसे इंसीडेंट्स कन्ट्री लिकर में तब होते हैं जब ईथाईल एल्कोहल की जगह मेथनॉल की तादाद ज्यादा हो जाती है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, माननीय सदस्य ने सही बताया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन महीने के अंदर लगभग 88 लोगों की मृत्यु अलग-अलग स्थानों पर हुई है। 4 अप्रैल को वाराणसी और भदोही डिस्ट्रिक्ट में 23 लोग, 26 फरवरी को गाजियाबाद और बुलंदशहर में 49 लोग और 16 फरवरी को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में 16 लोग मरे। उत्तर प्रदेश में काफी तादाद में लोगों की मृत्यु स्पुरियस लिकर से हो रही है, यह बात सही है।

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, झारखंड और बिहार में लोग मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांति बनाएं। प्रश्न काल चल रहा है।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अध्यक्ष महोदया, जहरीली शराब आम तौर पर खुलेआम गांवों में बिकती है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत न हो। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक जहरीली शराब बेचने वालों के मन में भय पैदा नहीं होगा। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार राज्यों को यह निर्देश देगी कि वे अपने प्रशासन को सख्त निर्देश दें कि उन पर सख्त निगरानी रखी जाए और उनसे निपटने के लिए जहरीली शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए कानून में संशोधन किए जाने की जरूरत है।

श्री अजय माकन: माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि जब तक स्थानीय पुलिस इस चीज के लिए पूरी तरह से आगे बढ़कर कार्य न करे, इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि वह उन पर इसे अच्छे तरीके से लागू करें। जैसा मैंने कहा कि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर राज्य सरकार के पास है, इसके माध्यम से लोकल पुलिस को और अच्छी भूमिका निभानी चाहिए। हम समय-समय पर राज्य सरकार को बार-बार एडवाइज देते रहते हैं कि किस प्रकार से इसे रोका जाए। इससे पहले भी एडवाइज दी गई है, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम और राज्य सरकारों को एडवाइज देंगे।

(Q. No. 343)

श्री बृजभूषण शरण सिंह : अध्यक्ष महोदया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम किस तरह से कोलेप्स कर चुका है, इसके बारे में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। कल माननीय राजनाथ सिंह जी ने पीडीएस सिस्टम का एक नमूना रखने का काम किया था। कांग्रेस के एक बहुत सम्मानित नेता कई बार बयान दे चुके हैं कि जो पैसा दिल्ली से गरीबों के लिए भेजते हैं वह गरीबों के पास नहीं पहुंचता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोटेदार का कमीशन मिट्टी के तेल, चीनी, राशन पर रोजगार करने के लिए पर्याप्त है? दूसरी तरफ जिला पूर्ति अधिकारी, परगना मजिस्ट्रेट, सप्लाई इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर गोदाम प्रभारी कोटा सस्पेंड और बहाली के नाम पर 50,000 रुपए की उगाही कर रहे हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। हाउस में कई बार चर्चा हुई है कि हमारा सिस्टम फेल हो चुका है और इसके कारण गरीबों का हक उन तक नहीं पहुंचता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे कौन ठीक करेगा? इसे रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई उपाय या ठोस नीति बनाने का फैसला किया है या भगवान के भरोसे छोड़ दिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): अध्यक्ष महोदया, हमने भगवान भरोसे नहीं छोड़ा है। सदन में सवाल उठाया गया है कि राज्य सरकारों को जो कोटा देते हैं, वह कहां तक लिफ्ट करते हैं? यह बात सही है और मैंने आंकड़े दिए हैं कि जो टोटल एलोकेशन राज्य सरकार का होता है, इसमें 70-80 परसेंट और कई जगह 90 परसेंट तक राज्य सरकारों की लिफ्टिंग होती है। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अलग है और भारत सरकार की जिम्मेदारी अलग है। भारत सरकार की जिम्मेदारी किसानों से खरीदना, राज्य सरकारों को उसके कार्यों के मुताबिक एलोकेशन करना है। एक बार राज्य सरकार को एलोकेट करने के बाद कमीशन क्या रखना चाहिए, कितनी दुकान रखनी चाहिए, दुकान पर निगरानी कैसी रखनी चाहिए, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये पूरे अधिकार और जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यहां से माल कैसे जाएगा और राज्य सरकार को कैसे देंगे, इस पर हमारा पूरा ध्यान है। माननीय सदस्य ने यहां जो एक समस्या खड़ी बताई है कि कुछ राज्यों में ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है। इस बारे में सदन में इससे पहले भी बातें कही गई हैं। इसलिए राज्य सरकार के कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के लोगों को जगह-जगह पर बुलाकर उनकी कांफ्रैन्स लेकर उन्हें आठ-नौ प्वाइंट का एक प्रोग्राम देकर, उन्हें सलाह देना, उनके ऊपर निगरानी रखना, इस पर हम लोगों ने कई बार ध्यान दिया है। मगर एलोकेशन का उठान करना और उसे लोगों तक पहुंचाने की अल्टीमेटली पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमैन्ट की है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं बाअदब मंत्री से कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न माफिया अधिकारियों से मिलकर सारे काड्र्स ले लेते हैं और उसे उठाते नहीं हैं, वे उसे केवल कागज में उठा लेते हैं और कागज में ही बेच देते हैं। जहां तक खरीद का सवाल है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कहीं भी गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। वहां गेहूं की खरीद का एक भी सैन्टर नहीं चल रहा है। ...(व्यवधान) मैं इस पर लम्बी बहस में नहीं जाना चाहता हूं, मैं माननीय मंत्री जी से...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिये।।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : हुजूर, ये लोग प्रश्न पूछने दें, तभी तो पूछें, सब लोग जानते हैं कि मिट्टी का तेल डीजल बन रहा है, जिसके कारण आज छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ियां तक खराब हो जाती हैं। जब हम लोग कम्पनी में जाते हैं तो कहते हैं कि आपका डीजल खराब है। मेरा कहना यह है कि हम गरीबों के नाम पर सब्सिडी मिट्टी का तेल, चावल और गेहूं के रूप में भेजते हैं। ऐसे परिवारों को चिह्नित करके जिन्हें इसका लाभ मिलता है और मार्केट रेट से सब्सिडी रेट का जो अंतर मूल्य है, क्या इसे निकालकर आप सीधे लाभार्थी परिवारों के खाते में डालने का विचार कर रहे हैं, ताकि इस सिस्टम की यह खराबी दूर हो जाए या इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे? क्या आप इस सिस्टम पर विचार करेंगे? लाभार्थी को सीधे पैसे के रूप में उस परिवार को दे दिये जाएं, क्या आप इस बात पर विचार करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री शरद पवार : मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास भेजने के लिए तैयार हैं तो राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम मेरे मंत्रालय की तरफ से हो जायेगा। जहां तक डायरेक्ट उनके खाते में पैसे देने का सवाल है, इस बारे में अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है। आज तक सभी राज्यों की एक ही डिमांड है कि हमें डायरेक्ट मैटिरियल की सप्लाई कीजिए और नीचे की सप्लाई हम करेंगे। इसलिए मैटिरियल की सप्लाई करने की जिम्मेदारी लेकर भारत सरकार वहां तक सीमित काम करती आई है।

श्री निनोंग ईरींग : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे अरूणाचल प्रदेश में पीडीएस के होलसेलर्स कौन तय करता है? क्या इन्हें केन्द्र सरकार तय करती है या वहां की राज्य सरकार तय करती है? जहां तक मेरे प्रश्न का सवाल है, उसमें मुख्य प्रश्न यह था कि वहां अभी कई सालों से नॉन-पेमेन्टस नहीं हुआ है, उसके कारण से उन दूर-दराज इलाकों में अभी तक फूड ग्रेन्स नहीं पहुंच पा रहा है। माननीय मंत्री जी कृपया इसका जवाब दें। मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूं, परंतु सदन में यदि वह जानकारी दें तो बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सांसद महोदय, आप भविष्य में अपना प्रश्न अपनी सीट से पूछें।

श्री शरद पवार : मेरा पहला जवाब देना आधा रहा। जहां तक उत्तर प्रदेश में खरीद की बात है,

उत्तर प्रदेश में खरीद के सेंटर चालू हैं और वहां कुछ माल खरीदा है। ट्रांसपोर्ट के बारे में अरूणाचल प्रदेश की एक बात यहां कही गयी है। यह बात सच है कि अरूणाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के बारे में राज्य सरकार ने भारत सरकार के सामने क्लेम किया और भारत सरकार ने इसकी जांच करने के बाद इसे पूरी तरह से गहराई से देखा और यह पूरा का पूरा क्लेम भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि वहां स्थिति ऐसी है कि गुवाहटी से ईटानगर ले जाते हैं और ईटानगर से बाकी जगहों पर अनाज पहुंचाने का काम करते हैं। गुवाहटी से ईटानगर ले जाने की पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और ट्रांसपोटर्स की मदद लेकर वे अपना माल भेजते हैं। वर्ष 2001-02 में जो एमाउन्ट क्लेम किया गया था, वह एग्जक्टली फिगर मेरे पास नहीं है, मगर कुछ 16 या 18 करोड़ रूपए का था। वर्ष 2002-03 में वह 64 करोड़ रूपए हो गया, वर्ष 2003-04 में 410 करोड़ रूपए हो गए और वर्ष 2004-05 में 338 करोड़ रूपए हो गए हैं। मेरा ध्यान आकर्षित किया गया कि जहां 15 करोड़ रूपए का साल का बिल था, वहां दूसरे साल 400 करोड़ रूपए का बिल आया है तो इसमें कुछ न कुछ जांच करने की आवश्यकता है। वह जांच वहां शुरू की गयी है और जब तक यह जांच पूरी नहीं होती तब तक यह पूरा पेमेंट हम नहीं करेंगे, इस तरह की एक भूमिका भारत सरकार ने ली है। मगर वहां अनाज की सप्लाई हो जाए, इस बारे में हमन ध्यान दिया है। वहां भारत सरकार के छह नये डिपो खुले हैं। आम जनता को इसकी कीमत नहीं देनी पड़ेगी, इस पर हमारा पूरा ध्यान है।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : महोदया, कल सदन में हमारे आदरणीय नेता श्री राजनाथ सिंह जी ने बताया था कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में अनाज कैसे सड़ रहा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में अनाज की स्टोरेज पद्धति किस प्रकार से होती है? जो अनाज पहले आता है, उसे नीचे रखते हैं और जो उसके बाद आता है, it should be taken away in the same manner. जो अनाज पहले आता है, उसे पहले लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से जो अनाज बाद में आता है, उसे ही उठाया जाता है और जो अनाज सबसे पहले आता है, वह वहीं पड़ा रहता है और वह सड़ जाता है। वह गरीब आदमी के पास नहीं पहुंचता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि स्टोरेज पद्धति के बारे में सरकार का क्या रवैया और प्रोसीजर है?

श्री शरद पवार : महोदया, यह सवाल इस बारे में है कि अरूणाचल स्टेट को अनाज पहुंचता है या नहीं पहुंचा है। माननीय सदस्य ने यहां जो सवाल उठाया है, इसके लिए मुझे अलग नोटिस की आवश्यकता है। जब मुझे पता लगा कि सम्माननीय राजनाथ सिंह जी स्वयं वहां गये, उन्होंने स्वयं जांच की और सदन के

सामने कुछ बातें कहीं, तब मैंने भी इसकी जांच करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को उस जगह पर भेजा था। उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास आयी है। इसमें मैं एक बात साफ करना चाहता हूं कि जो माल वहां खराब हुआ या जो माल सड़ा हुआ था, वह भारत सरकार या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नहीं था। वह माल हरियाणा गवर्नमेंट के फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का था। मगर चाहे वह माल हरियाणा सरकार का हो या भारत सरकार का हो, वहां ठीक तरह से माल को नहीं रखना, यह बात गलत है। इसके लिए उन्हें जो कुछ भी आवश्यक सूचना देने की जरूरत है, इस तरह की सूचना हरियाणा सरकार को इसके पहले भी दी थी और अभी भी दी है।

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, इसमें मेरा नाम आया है इसलिए मैं इस पर बोलना चाहूंगा।

SHRI T.R. BAALU : Madam Speaker, to check the prices of food grains and to control them, the Government of Tamil Nadu is following the Universal Public Distribution System. Our requirement per month of rice is 3,17,000 tonnes whereas we are getting only 2,96,000 tonnes from the Common Pool.

But at the same time, I reliably understand that some of the States are not lifting the allocated quantity from godowns. In view of this situation, will the Central Government come forward to reallocate it to the needy States so that their requirement is fulfilled?

As far as wheat is concerned, Tamil Nadu is getting 10,000 tonnes on an ad-hoc basis. I understand that our godowns are flooded with wheat and yesterday some of our friends made a complaint that it is getting rotten. In view of this, will the Central Government come forward to allocate 10,000 tonnes of wheat to Tamil Nadu on a regular basis?

SHRI SHARAD PAWAR: Madam, it is a general question, but still I have no hesitation to reply.

Firstly, if there is a proposal from the Government of Tamil Nadu for additional allocation of wheat, whatever quantity they will ask, we will sanction and supply. There is no question of giving or supplying 10,000 or 20,000 or 30,000 tonnes. Whatever is their requirement, if I get a communication from the

Government of Tamil Nadu, that will be immediately approved and the material will be sent.

SHRI T.R. BAALU : What about rice?

SHRI SHARAD PAWAR: You asked about wheat. The question was specific about wheat and my commitment is for wheat.

SHRI T.R. BAALU : My first question was about rice only. Will the unutilized quantity of rice be reallocated to the needy States?

SHRI SHARAD PAWAR: We have to assess the overall stock position and overall procurement. Let me tell you frankly – and I would like to take the House into confidence – that the Khariff season which used to produce maximum quantity of rice in this country failed. More than 300 districts of our country were suffering from drought and that is why, this year in Khariff, there was a shortfall in rice production. But we tried our best to compensate the shortfall or bridge this gap during the Rabi season. Fortunately the farming community of this country has accepted that challenge and they have produced more wheat and rice. That is why, comparatively the rice position has improved. But I will assess the entire situation, I will see the stock position and then definitely I will consider the request of my hon. friend from Tamil Nadu.

The second issue which he raised was about the Universal Public Distribution System. In fact, I have made the position absolutely clear on a number of occasions in this House that the Government has taken a conscious decision towards Targeted Public Distribution System and that has been implemented for the last 10 years. It is not new. We always get one complaint from many hon. Members and that is about the BPL Card holders. It is said that the number of BPL Card holders that is accepted by the Government of India is incorrect and is much less than the actual number. The Cabinet has recently taken a decision and authorized the Planning commission that they should go into the matter in detail and submit their report within one month. So, whatever revised

report we will get from the Planning Commission about the number of BPL Card holders, that will be accepted and implemented.

श्री रमाशंकर राजभर : माननीय अध्यक्ष जी, राशन कार्ड पर चीनी, तेल, नमक, गेहूँ और चावल बँटता है। गेहूँ और चावल गाँवों में पैदा होता है और गाँवों से उठाकर हम उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर लाकर स्टोर करते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि इससे जो कैरिज बढ़ता है, जो स्टोरेज बढ़ता है और जो किसानों का पैदा किया हुआ सामान सड़ता है, उसके लिए क्या ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर इसको स्टोरेज कराने की व्यवस्था करने का कोई विचार है?

श्री शरद पवार : कृषि मंत्रालय की गांवों में भंडार खोलने की एक योजना है। राज्य सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ लेने के लिए जो प्रपोज़ल आते हैं, उनके लिए राज्य सरकार को पैसा देते हैं। जहां तक भंडारों की स्थिति का सवाल है, इन पर बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। हमारे देश में वेयरहाउसिंग और गोदामों की जितनी मात्रा में आवश्यकता है, उतनी उनकी उपलब्धता नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाने का निर्णय लिया है।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, आपने कृपा की है। आपका धन्यवाद।

महोदया, हम माननीय मंत्री जी की व्यथा को समझते हैं, क्योंकि विभाग के अलावा इनकी और भी भारी-भारी जिम्मेदारी है, जिसकी चर्चा विगत दो दिनों से चल रही है।

महोदया, माननीय मंत्री जी ने गरीबों के लिए लाल कार्ड, पीला कार्ड और सफेद कार्ड के तहत दो और तीन रूपये प्रति किलो पर चावल और गेहूं देने की बात कही थी। बिहार में सत्ताधारी हमारे साथी बुरा नहीं मानेंगे, पूरे बिहार में लाल और पीला कार्ड लेकर लोग भटक रहे हैं, करीब आठ सौ आदमी भूख से मर गए हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लाल और पीला कार्डधारी के लिए बिहार सरकार द्वारा कितना उठाव किया गया है? वहां के उपमुख्यमंत्री का बयान आया कि चीनी की किल्लत इसलिए है, क्योंकि आपने बिहार के लिए चीनी का कोटा साउथ की मिलों से तय किया हुआ है। वहां से ढो कर लाने का खर्च कौन वहन करेगा? यह भी अखबार में बात आयी थी। आप पर विश्वास किया जाए या उनकी बात पर विश्वास किया जाए।

महोदया, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम बिहारी लोग दिल्ली में आकर बदल जाते हैं, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी तक बीपीएल कार्डधारियों का निर्धारण पूरे देश और बिहार में नहीं हुआ है। इसके कारण कैरोसिन तेल और अन्य खाद्य पदार्थ आप जो भेजते हैं, उन सब में मिलावट हो जाती है। राज्य सरकार का अपने बचाव में यह बयान आता है कि दिल्ली से एलोकेशन नहीं मिल रहा है, भेदभाव हो रहा है। मेरा प्रश्न यही है कि बिहार सरकार द्वारा लाल और पीले कार्डधारकों के तहत खाद्य पदार्थों का कितना उठाव किया गया है? लोग भूख से मर रहे हैं, आप इस बारे में स्पष्ट उत्तर दीजिए।

श्री शरद पवार : महोदया, बिहार सरकार को अन्य राज्यों की ही तरह एलोकेशन किया जाता है। यह बीपीएल, एपीएल और अन्त्योदय कार्ड धारकों के लिए किया जाता है। वर्ष 2007-08 में बिहार सरकार के लिए 27,68,000 टन सैंक्शन किया गया था, लेकिन इसमें से बिहार सरकार ने 16,25,000 टन का उठाव किया था। वर्ष 2008-09 में 29,58,000 टन का एलोकेशन किया गया था, लेकिन 15,29,000 टन का उठाव किया गया था। वर्ष 2009-10 में 34,37,000 का एलोकेशन किया गया था, लेकिन 20,51,000 टन का उठाव किया गया। बिहार सरकार की तरफ से भारत सरकार के पास एक सुझाव आया है कि वहां गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की आबादी और भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई संख्या में फर्क है। उन्होंने हमें लिखित में इन्फार्म किया है कि उन्होंने घर-घर जाकर सर्वे किया है और उनका कहना है कि इस फिगर में बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि योजना आयोग के सामने यह सभी बातें रखी गई हैं और योजना आयोग को यह सूचना दी गई है कि एक महीने में सभी राज्यों के बारे में हमें रिपोर्ट दीजिए, जिसके मुताबिक भारत सरकार हर राज्य को एलोकेशन कर सके।

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन दो केन्द्रों पर, हरियाणा में जाकर मैंने एफसीआई गोडाउन के गेहूं का सेम्पल लिया था, उसे आपको और पूरे सदन को मैंने दिखाया था। आपका कहना यह है कि उसे हरियाणा गवर्नमेंट ने परचेस करके पूरा स्टॉक कर रखा था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में कौन-कौन से ऐसे एफसीआई के गोडाउंस हैं, जहां पर सेंट्रल पूल का भी गेहूं रखा हुआ है, साथ-साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परचेस किया हुआ अथवा किसी भी प्रकार से रखा गया हो?

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब मैंने वहां के कर्मचारियों से जानकारी हासिल की तो मुझे बताया गया कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही सेंट्रल पूल का यहां गेहूं रखा गया है। यह बात हमारी समझ के परे हैं कि वहां पर सेंट्रल पूल का गेहूं और हरियाणा स्टेट का भी गेहूं रखा है। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि यह केवल एक-दो गोडाउंस

की बात नहीं है - चाहे वह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा हो। एफसीआई के गोडाउंस में गेहूं सड़ रहे हैं और सन् 2008 से सड़ रहे हैं। कृपया आप इसका संज्ञान लेने का कष्ट करें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हों, उन्हें पनीश करने की व्यवस्था होनी चाहिए और पीडीएस सिस्टम के गेहूं को जिस तरीके से मिला कर राज्यों को भेजा जा रहा है, मैं इस संबंध में आपको कई उदाहरण भी दे सकता हूं। मैं खेड़ी गांव में हरियाणा में गया था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजनाथ सिंह : वहां मुझे एक महिला ने बताया कि जो गेहूं पीडीएस सिस्टम से मिला हुआ है, वह इतना सड़ा हुआ है कि यदि उस आटे की हम रोटी बनाना चाहें तो उसकी रोटी नहीं बन सकती। उस आटे से बदबू आती है, कृपया आप उसका संज्ञान लें और इस दिशा में कार्यवाही करें।

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदया, बात यह है कि कौन से गोडाउन में भारत सरकार का एफसीआई का माल है और कौन से में हरियाणा सरकार का है, इसकी इन्फोरमेशन अभी मेरे पास नहीं है। मगर मैं जरूर यह इन्फोरमेशन कलेक्ट करूंगा और माननीय सदस्य को दूंगा। माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही है कि अन्य कुछ जगहों पर भी इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां सुधार करने की आवश्यकता है, मैं उनसे इसकी इन्फोरमेशन मांगूंगा और उसमें सुधार भी करूंगा तथा सख्ती से कार्यवाही भी करूंगा।...(व्यवधान)

(Q. No. 344)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : अध्यक्ष महोदया, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। कृषि को जब उद्योग का दर्जा दिया जाएगा, तब देश में लोगों का विकास होगा। कृषि फसलों की तरह उत्पादन पद्धति और बाजारी अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि बागवानी खेती बढ़ाने के लिए, हालांकि बीज सिंचाई सुविधाएं आदि के लिए सस्ते ब्याज पर बैंकों से धन मुहैया कराने का सरकार का कोई इरादा है, इनके बारे सरकार ने क्या सोचा है?

श्री शरद पवार: बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने होर्टीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना पहले से की हुई थी और नेशनल होर्टीकल्चर बोर्ड के माध्यम से किसानों को इसमें मदद करने का कार्यक्रम पूरे देश में आज भी चालू है। नेशनल होर्टीकल्चर मिशन नाम का एक नया कार्यक्रम भारत सरकार ने हाथ में लिया और इसमें अभी तक 4228 करोड़ रुपए सन् 2005 से 2009 तक रिलीज किए गए और सन् 2009-10 को 725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में होर्टीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की स्कीम को अमल कर रहे हैं। और उसका सभी की तरफ से अच्छा रेस्पांस मिला है। इसके साथ-साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिली स्टेट्स के लिए एक और अलग स्कीम इसी तरह की बनाई गई है, जिसके माध्यम से वहां भी मदद की जाती है। मदद करने का जो तरीका है, वह दो-तीन किस्म का है। एक तो हम फायनेंश्यल सपोर्ट करते हैं, दूसरा नर्सरी के लिए अच्छा प्लांटिंग मटीरियल मिलना चाहिए, तो इसके लिए अच्छी नर्सरी निकालने के लिए कोई कोशिश करता है, तो उसे भी हम मदद करते हैं और तीसरे प्रकार की सहायता के अन्तर्गत जब माल तैयार होगा, तो उसके लिए मंडी बनाने की आवश्यकता होती है, फिर चाहे गांव की मंडी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट की मंडी हो, चाहे रीजनल मंडी हो या टर्मिनल मार्केट हो, उसके लिए भी फायनेंश्यल सपोर्ट भारत सरकार की तरफ से किया जाता है।

इसके साथ-साथ स्टोरेज की व्यवस्था करने के लिए, यदि कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता हो, तो सब्सिडी देकर, कोल्ड स्टोरेज बनाने का कार्यक्रम इसमें लिया गया है। इसके लिए किसानों की तरफ से ठीक प्रकार का समर्थन मिल रहा है।

महोदया, मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हिन्दुस्तान, आज फल और सब्जियों के उत्पादन के बारे में दुनिया में दो नंबर पर पहुंच गया है। इसमें हॉर्टीकल्चर मिशन का बहुत योगदान है।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनउपजाऊ और परती जमीनों के विकास के बारे में भारत सरकार ने गुजरात के मुख्य मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसने देशभर में जो परती भूमि उपलब्ध है, उसके उपयोग के बारे में सुझाव दिए थे, लेकिन अब तक इस समिति की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। इस समिति ने सुझाव दिया था कि भारत सरकार को परती भूमि के विकास के लिए बड़े पैमाने पर प्राईवेट-पब्लिक साझेदारी बनाकर, कार्य प्रारम्भ करना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

SHRI SHARAD PAWAR: Regarding the first question, I will require a separate notice for that because the question was regarding utilization of waste land. That was not the main Question. Regarding exports, एक्सपोर्ट की पूरी जिम्मेदारी एपीडा की है, यह काम उसी के माध्यम से होता है कि which is under the control of the Commerce Ministry. There are a number of Schemes in the Commerce Ministry. Through APEDA they are supporting the exports of various items of the agricultural produce to the farmers.

DR. M. THAMBIDURAI : Madam Speaker, the hon. Minister has said that to increase the income of the farmers, the Government is promoting horticulture cultivation and establishment of agro-based industries. Hosur in Tamil Nadu is famous for cut flower cultivation but the farmers of that area are suffering as they are not able to get sufficient fertilizers and also due to high prices of fertilizers. Therefore, I would like to know from the Minister whether the Government will come forward to give sufficient fertilizers to the farmers at concessional rate. Instead of sorting out the problem, our hon. Fertilizer Minister has gone to Maldives on a holiday trip. Our farmers are suffering a lot. The hon. Fertilizer Minister is not coming to the House and also is not trying to solve this problem. Therefore, I would like to know from the Agriculture Minister whether he would come forward to solve the problem of agricultural farmers by way of giving sufficient fertilizers at concessional rate.

SHRI SHARAD PAWAR: In the Horticulture Mission, the Government of India is supporting the farmers not only in horticultural fruits but even in floriculture. So, if any specific proposal about the development or expansion of that area under floriculture, definitely I will be happy to consider it.

The second issue which he has raised is about the supply of fertilizers and the price of fertilizers. I have not got any detailed information about that. That particular subject is dealt by the Ministry of Chemicals and Fertilizer. If there is a specific requirement of fertilizer, I have no hesitation to convey it to the concerned Ministry, and some cooperative plan to supply sufficient fertilizer in that area can be made.

About the price of fertilizers, the price has been fixed, and that is uniform for the whole country.

MADAM SPEAKER: Shri Shivaji Adhalrao Patil. You have a very little time.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI : Our experience in contract farming by multinationals and corporate houses in my Constituency, particularly in Puna District, is very good.

MADAM SPEAKER: Be quick. You just have one minute.

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI :Yeah. I would like to ask the hon. Minister whether the Government has any scheme or the Government would like to come out with any scheme, which will help and offer farmers crop insurance schemes, particularly on potatoes and onions.

SHRI SHARAD PAWAR: There is a separate insurance for agricultural produce. One has to see what items have exactly been selected by the insurance companies. But if any specific support is required to that particular area, I would be happy to give full support and expand the programme.

MADAM SPEAKER: Thank you.

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2118/15/10)

THE MINISTER OF MINES AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI B.K. HANDIQUE): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the National Aluminium Company Limited and the Ministry of Mines for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2119/15/10)

(2) Memorandum of Understanding between the Hindustan Copper Limited and the Ministry of Mines for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2120/15/10)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI DINSHA PATEL): I beg to lay on the Table:–

(1) A copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2121/15/10)

(2) A copy of the Statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Annual Report and Audited Accounts of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the years 2007-2008 and 2008-2009 within the stipulated period of nine months after the close of the respective accounting years.

(Placed in Library, See No. LT 2122/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): I beg to lay on the Table a copy of the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Amendment Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 207(E) in Gazette of India dated the 23rd march, 2010 under sub-section (4) of Section 18 of the Citizenship Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 2123/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI AJAY MAKEN): I beg to lay on the Table a copy of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 278(E) in Gazette of India dated the 1st April, 2010 under sub-section (2) of Section 11 of the Lotteries (Regulation) Act, 1998.

(Placed in Library, See No. LT 2124/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to lay on the Table:–

(1) A copy of the Notification No. G.S.R. 70(E)/Ess. Com./Sugarcane (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 10th February, 2010, fixing the price of sugar, mentioned therein, as the fare and remunerative price in respect of the State mentioned in the Notification for the sugar year 2009-2010 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodites Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 2125/15/10)

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Karnataka Meat and Poultry Marketing Corporation Limited, Bangalore, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Karnataka Meat and Poultry Marketing Corporation Limited, Bangalore, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 2126/15/10)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Punjab Agro Industries Corporation Limited, Chandigarh, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Punjab Agro Industries Corporation Limited, Chandigarh, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 2127/15/10)

(c) (i) Review by the Government of the working of the Goa Meat Complex Limited, Panjim, for the year 2007-2008.

(ii) Annual Report of the Goa Meat Complex Limited, Panjim, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 2128/15/10)

(d) (i) Review by the Government of the working of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Chandigarh, for the year 2008-2009.

(ii) Annual Report of the Haryana Agro Industries Corporation Limited, Chandigarh, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (b) to (d) of (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 2129/15/10)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Food Corporation of India, New Delhi, for the year 2006-2007, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Food Corporation of India, New Delhi, for the year 2006-2007.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 2130/15/10)

(6) A copy of the Insecticides (Amendment) Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 174(E) in Gazette of India dated the 5th March, 2010, under sub-section (3) of Section 36 of the Insecticides Act, 1968.

(Placed in Library, See No. LT 2131/15/10)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Cooperative Training, New Delhi, for the year 2008-2009.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council for Cooperative Training, New Delhi, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Cooperative Training, New Delhi, for the year 2008-2009.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 2132/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (KUNWAR R.P.N. SINGH): I beg to lay on the Table:–

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 10 of the National Highways Act, 1956 :-

(i) S.O. 534(E) published in Gazette of India dated the 4th March, 2010, authorising the Special Land Acquisition Officer, National Highway Zone, Bangalore, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 13 (Chitradurga-Shiomoga Section) in the State of Karnataka.

(ii) S.O. 480(E) published in Gazette of India dated the 25th February, 2010, authorising the Officers, mentioned therein, as the competent authority to acquire land for building, maintenance and operation of National Highway No. 8 in the State of Rajasthan.

(iii) S.O. 218(E) published in Gazette of India dated the 29th January, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 86 Ext. (Bhopal-Sanchi Section) in the State of Madhya Pradesh.

(iv) S.O. 281(E) published in Gazette of India dated the 8th February, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 525(E) dated the 9th April, 2007.

(v) S.O. 276(E) published in Gazette of India dated the 8th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Khalghat-M.P/Maharashtra Border Section) in the State of Madhya Pradesh.

(vi) S.O. 311(E) published in Gazette of India dated the 10th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 26(B) (in the State of Maharashtra.

(vii) S.O. 312(E) published in Gazette of India dated the 10th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway Nos. 26(B) and 69(A) (in the State of Madhya Pradesh.

(viii) S.O. 321(E) published in Gazette of India dated the 10th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12A in the State of Madhya Pradesh.

(ix) S.O. 372(E) published in Gazette of India dated the 16th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 3 (Khalghat-M.P/Maharashtra Border Section) in the State of Madhya Pradesh.

(x) S.O. 420(E) published in Gazette of India dated the 18th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 7 (Lakhanadon-Seoni Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xi) S.O. 3046(E) published in Gazette of India dated the 30th November, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 3 (including construction of bypass) (Indore-Khalghat Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xii) S.O. 3197(E) published in Gazette of India dated the 14th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 12 (Jabalpur-Rajmarg Crossing Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xiii) S.O. 3199(E) published in Gazette of India dated the 14th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 in the State of Madhya Pradesh.

(xiv) S.O. 3221(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 in the State of Madhya Pradesh.

(xv) S.O. 39(E) to S.O. 41(E) published in Gazette of India dated the 8th January, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 69 in the State of Madhya Pradesh.

(xvi) S.O. 3227(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 in the State of Madhya Pradesh.

(xvii) S.O. 3202(E) published in Gazette of India dated the 14th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 59 in the State of Madhya Pradesh.

(xviii) S.O. 130(E) published in Gazette of India dated the 20th January, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 26 (Jhansi-Lakhanadon Section) in the State of Madhya Pradesh.

(xix) S.O. 3107(E) published in Gazette of India dated the 4th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Tumkur-Harihar Section) in the State of Karnataka.

(xx) S.O. 3108(E) published in Gazette of India dated the 4th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Tumkur-Harihar Haveri Section) in the State of Karnataka.

(xxi) S.O. 369(E) published in Gazette of India dated the 16th February, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2457(E) dated the 24th September, 2009.

(xxii) S.O. 368(E) published in Gazette of India dated the 16th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 in the State of Karnataka.

(xxiii) S.O. 278(E) published in Gazette of India dated the 8th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Nelamangala-Tumkur Section) in the State of Karnataka.

(xxiv) S.O. 384(E) published in Gazette of India dated the 16th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Dharwad-Belgaum Section) in the State of Karnataka.

(xxv) S.O. 3295(E) published in Gazette of India dated the 24th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4A (Karnataka/Goa Boundary) in the State of Karnataka.

(xxvi) S.O. 277(E) published in Gazette of India dated the 8th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Bangalore-Nelamangala Section) in the State of Karnataka.

(xxvii) S.O. 3246(E) published in Gazette of India dated the 18th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 4 (Bangalore-Nelamangala Section) in the State of Karnataka.

(xxviii) S.O. 280(E) published in Gazette of India dated the 8th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 37 in the State of Assam.

(xxix) S.O. 607(E) and S.O. 608(E) published in Gazette of India dated the 17th March, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 154 in the State of Assam.

(xxx) S.O. 202(E) published in Gazette of India dated the 29th January, 2010, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 3198(E) dated the 14th December, 2009.

(xxxi) S.O. 2810(E) published in Gazette of India dated the 3rd November, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Delhi-Agra Section) in the National Capital Territory of Delhi.

(xxxii) S.O. 3127(E) published in Gazette of India dated the 7th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Muzaffarnagar-Haridwar Section) in the State of Uttarakhand.

(xxxiii) S.O. 139(E) published in Gazette of India dated the 20th January, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1466(E) dated the 29th August, 2007.

(xxxiv) S.O. 168(E) published in Gazette of India dated the 22nd January, 2010, containing corrigendum to the Notification No. S.O. 3127(E) dated the 7th December, 2009.

(xxxv) S.O. 366(E) published in Gazette of India dated the 16th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Delhi-Agra Section) in the National Capital Territory of Delhi.

(xxxvi) S.O. 3128(E) published in Gazette of India dated the 7th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Muzaffarnagar-Haridwar Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xxxvii) S.O. 3129(E) published in Gazette of India dated the 7th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Muzaffarnagar-Haridwar Section) in the State of Uttarakhand.

(xxxviii) S.O. 3130(E) published in Gazette of India dated the 7th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 72 (Haridwar-Dehradun Section) in the State of Uttarakhand.

(xxxix) S.O. 3173(E) and S.O. 3174(E) published in Gazette of India dated the 10th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 24 (Delhi-Meerut Expressway) in the States of Delhi and Uttar Pradesh.

(xl) S.O. 3215(E) published in Gazette of India dated the 15th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance,

management and operation of National Highway No. 24 (Lucknow-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xli) S.O. 219(E) published in Gazette of India dated the 29th January, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 58 (Meerut-Muzaffarnagar Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xlii) S.O. 118(E) published in Gazette of India dated the 20th January, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Delhi-Agra Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xliii) S.O. 167(E) published in Gazette of India dated the 22nd January, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 (Jhansi-Khajuraho Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xliv) S.O. 381(E) published in Gazette of India dated the 16th February, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 2570(E) dated the 9th October, 2009.

(xlv) S.O. 401(E) published in Gazette of India dated the 17th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24 (Bareilly-Sitapur Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xlvi) S.O. 81(E) published in Gazette of India dated the 13th January, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Delhi Agra Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xlvii) S.O. 406(E) published in Gazette of India dated the 17th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 75 (Jhansi-Khajuraho Section) in the State of Uttar Pradesh.

(xlviii) S.O. 122(E) published in Gazette of India dated the 20th January, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 71A (Rohtak-Panipat Section) in the State of Haryana.

(xlix) S.O. 2522(E) published in Gazette of India dated the 1st October, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 2 (Faridabad Section) in the State of Haryana.

(l) S.O. 284(E) published in Gazette of India dated the 8th February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 10 (Rohtak-Hissar Section) in the State of Haryana.

(li) S.O. 183(E) published in Gazette of India dated the 25th January, 2010, making certain amendments in the Notification No. S.O. 860(E) dated the 7th June, 2006 and S.O. 1960(E) dated 14th November, 2006.

(lii) S.O. 439(E) to S.O. 447(E) published in Gazette of India dated the 23rd February, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of different stretches of National Highway No. 1 (Panipat-Jalandhar Section) in the State of Punjab.

(liii) S.O. 216(E) published in Gazette of India dated the 29th January, 2010, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 73 (Yamunanagar-Panchkula Section) in the State of Haryana.

(liv) S.O. 3114(E) published in Gazette of India dated the 4th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 21 (Kurali-Kiratpur Section) in the State of Punjab.

(lv) S.O. 3201(E) published in Gazette of India dated the 14th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Pathankot-Amritsar Section) in the State of Punjab.

(lvi) S.O. 3195(E) published in Gazette of India dated the 14th December, 2009, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 15 (Pathankot-Amritsar Section) in the State of Punjab.

(Placed in Library, See No. LT 2133/15/10)

12.01 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
6th Report

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I beg to present the Sixth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

———

12.01½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
3rd and 4th Reports

SHRI YASHWANT SINHA (HAZARIBAGH): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on External Affairs:-

(1) 3rd Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of Overseas Indian Affairs for the year 2010-2011.

(2) 4th Report (15th Lok Sabha) on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2010-2011.

———————

12.02 hrs.

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES
2nd and 3rd Reports

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): महोदया, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

1. जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन।
2. नदियों को आपस में जोड़े जाने के संबंध में ग्यारहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

———————

12.02½ hrs.

COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
4th to 6th Reports

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।
2. जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
3. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
219th and 220th Reports

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): महोदया, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2010-11 (मांग संख्या 104) के बारे में 219वां प्रतिवेदन।
2. युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2010-11 (मांग संख्या 105) के बारे में 220वां प्रतिवेदन।

12.03½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 144th and 145th Reports

SHRI MADAN LAL SHARMA (JAMMU): I beg to lay the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

(1) One Hundred Fifty-fourth Report on Demands for Grants (2010-2011) of the Ministry of Tourism.

(2) One Hundred Fifty-fifth Report on Demands for Grants (2010-2011) of the Ministry of Road Transport and Highways.

12.04 hrs.

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 2989, DATED 08.12.2009 REGARDING 'DECONTROL OF SUGAR SECTOR' ALONGWITH GIVING REASONS FOR DELAY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): I beg to make a statement correcting the reply to the Lok Sabha Unstarred Question No.2989 answered on 08.12.2009 regarding 'Decontrol of Sugar Sector' as follows:-

Part of the Question answered	For	Read
(a)	At present, there is no proposal under consideration of the Government to decontrol order.	At present, there is no proposal under consideration of the Government to decontrol sugar.

The error in the above mentioned question's reply was noticed on 08.12.2009 by the Department. A notice dated 14.12.2009 from myself was sent to the Secretary-General, Lok Sabha, for making a correcting statement in this regard. However, the correcting statement could not be made in the last Winter Session.

Now, a statement will be made in the Lok Sabha on any convenient day of the Budget Session of the Parliament.

(Placed in Library, See No. LT 2134/15/10)

12.05 hrs.

STATEMENT UNDER RULE 199

Personal explanation by a Member in regard to resignation from the office of Minister of State in the Ministry of External Affairs.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam Speaker, I rise to explain to you and to Members of this august House my resignation from the Union Council of Ministers.

As a loyal public servant, I am conscious that the controversy over my role in the IPL issue was distracting Parliament from far more important business.

As I explained in my statement to the Lok Sabha on Friday—which I attempted to deliver it in the Lok Sabha on Friday--and reiterated to the Prime Minister on Sunday, my conscience is clear and I know that I have done nothing improper or unethical, let alone illegal. Nonetheless, in view of the ongoing political controversy, I have no desire to be an embarrassment to the Government and believe that my departure at this stage will allow the Prime Minister and his Cabinet colleagues to focus on the great challenges facing our nation. Such a step is in the highest moral traditions of our democratic system and in keeping with the standards that I am sure we would all wish to uphold in our nation's public life.

I welcome the fact that this august House, of which the voters of Thiruvananthapuram have made me a proud Member, has now moved on from the disruption we witnessed on Friday to address the important issues which await its consideration, and to take the crucial decisions needed to promote the well-being of the wonderful people of our great country.

Madam Speaker, I am new to Indian politics but I have a long record of public service, unblemished by the slightest taint of financial irregularity. I am deeply wounded by the fanciful and malicious charges that have been made against me and I have requested the Prime Minister to have these charges against

me thoroughly investigated. I have led a life of personal integrity and probity and it is important to me that my name is cleared.

Madam Speaker, I returned to India after long years of international service because I had always cherished the desire to make a difference in my own country. Growing up in India and then looking at it from abroad, I could see how much there is to be proud of in our land, and how much the Indian people deserve the best efforts of all who aspire to lead our great democracy. I returned to India because I believe in an India of honesty and hard work, not of corruption and crookedness. I believe in an India of openness and straightforwardness, not of hypocrisy and double-dealing. I believe in an India where opportunities are available to all and not just to a chosen few. I believe in an India of pluralism and diversity, not of religious bigotry and caste politics. I believe in an India that is secure in itself and confident of its place in the world, an India that is a proud example of tolerance, freedom and hope for the downtrodden. That India will only be built by the sincere efforts of all of us in this august House and outside it.

This is the vision with which the voters of Thiruvananthapuram sent me to sit in your midst. I am proud to represent the capital of Kerala, a State that in so many ways is a trailblazer for India's progress, though in other respects it seems to have been left behind in the race for 21st century development. The Keralite ethos, with its cultural unity amidst religious diversity, its high educational standards and respect for democracy, its commitment to the empowerment of women and the well-being of the poor, embodies the best of India. As our great poet Vallathol wrote, *"Bharatam ennu ketala, abhimaana-pooritham aavanum, antarangam; Keralam ennu ketalo, thilakkanam choara nammuke njerambagalil."* (When you hear the name of India, your heart must swell with pride; when you hear the name of Kerala, the blood must throb in your veins.) Madam Speaker, my heart swells with pride for India, and Keralite blood throbs in my veins.

I should like to reiterate that it has been a great privilege for me to serve the Indian National Congress Party and the Government of India. I shall always be grateful to the Honourable Prime Minister, Dr Manmohan Singh, and the Chairperson of the United Progressive Alliance and the leader of my party, Smt. Sonia Gandhi, for the opportunity they have given me to be of service to the country. They have been two of the finest of that select band of great men and women who have dedicated their lives for the service of the people of our nation.

I have great confidence that under their leadership, the country is in good hands and the Indian people can look forward to increasing security and prosperity in a troubled world. I should like to reiterate that it has been a great privilege for me to serve my Party and to have served the Government.

Today marks a new beginning for me and I am heartened by the love, friendship and loyalty I have received from countless numbers of well-wishers, in Thiruvananthapuram, across my home State of Kerala and throughout our great country. I am grateful for their support and encouragement and I am determined to continue to do my best for India and for the ideals that brought me back here.

Thank you, Madam Speaker.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय अध्यक्ष महोदया, पिछले दो वर्षों से देश के भीतर डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, जापानी बुखार और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों के टीकों की किल्लत पैदा हो गयी है, जो हमारी सरकारी कम्पनियां को पूर्व मंत्री द्वारा बंद कराने से हुई। इस कारण देश के लाखों गरीब बच्चों ने टीके के अभाव में दम तोड़ दिया। भारत सरकार ने इसकी जांच करवाई, जिसमें पाया गया कि जिन टीका बनाने वाली सरकारी कम्पनियों को बंद किया गया, उनकी गुणवत्ता, उनके मानक में कोई दोष नहीं था, बल्कि प्राइवेट कम्पनियों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी कम्पनियां बंद की गयीं। श्री जावेद अख्तर जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, उन्होंने जांच में यह बात सही पायी कि प्राइवेट कम्पनियां जो देश के बाहर टीके का 500 करोड़ रुपये का निर्यात करती हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए हमारे देश की सरकारी कम्पनियां जो टीके बनाने का काम करती थीं, उन्हें बंद करने का काम किया गया जिससे कहीं न कहीं इस दवा और कारोबार में बड़े घोटाले की बू आती है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पूरे विवरण की, पूरी घटना की जांच करायी जाये और जिस प्रकार से सरकारी कम्पनियों को बंद करने का एक हवाला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा धौंस जमाकर दिया गया कि भारत सरकार की जो सरकारी कम्पनियां टीके की दवा बना रही हैं, वे अच्छी नहीं हैं बल्कि प्राइवेट कम्पनियां जो दवा बना रही हैं, वे अच्छी है। जब दोनों की जांच करायी गयी, तो प्राइवेट कम्पनियां जो दवा बना रही हैं, उसके भी वही मानक थे, जो सरकारी कम्पनियां के टीके बनाने के थे। यह लोकमत का अविलम्बनीय विषय है। देश के लाखों बच्चे टीकों के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और सरकार उनकी महंगी दवाएं प्राइवेट कम्पनियों से खरीद रही है। वे दवाएं गरीब लोगों को महंगे दर पर मिल रही हैं। यह गंभीर मामला है इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस गंभीर मसले की जांच एक जांच समिति बनाकर की जाये और उन लोगों के खिलाफ जांच करायी जाये, जिनका योगदान सरकारी कम्पनियों को बंद कराने में रहा और जिन्होंने एक साजिश के तहत सरकारी कम्पनियों को बंद करने और निजी कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का गरीबों से जुड़ा हुआ मसला है।

यह लाखों बच्चों के जीवन का सवाल है। इस पर सरकार तत्काल जवाब दे और जांच कराने की मांग करता हूं। मैं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग करता हूं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदया, मैं इसी से संबंधित एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप स्वयं को इससे सम्बद्ध कर लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब उनकी बात सुनिए। आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Thank you Madam Speaker for allowing me to speak on a very important issue. The PSU bosses are now no more under CVC scanner. The Central Government has recently issued an ordinance that all complaints of corruption and financial bungling against the heads and functional directors of Central Public Sector Undertakings as well as financial institutions will now be dealt with by a Committee of bureaucrats instead of the CVC as mandated under the CVC Act. This is directly a violation of law governing the CVC whose jurisdiction includes Members of All India Service serving in connection with the affairs of the Union and Group-A officers of the Central Government, officers of the Banks above Scale-V in public sector banks like the Reserve Bank of India, NABARD, SIDBI and Chief Executives on the Boards of Public Sector Undertakings. The Commission has power to order the investigation by the CBI if it finds substance in a complaint by preliminary scrutiny.

The change has been sneaked by issuing an order on 11th March. In one go, about one thousand top officials of 240 Central Public Sector Undertakings and 40 Banks, insurance companies and financial institutions have been taken out of the purview of the CVC. This is a very grave matter. The order will have an immediate bearing on the Chief Executives of the companies like Air India, ONGC, GAIL, SAIL, BSNL, MTNL, IOC, BHEL etc. as well as the banks and financial institutions like State Bank of India, Reserve Bank of India, LIC, NABARD etc.

Now, if a whistleblower writes to the CVC against a Chairman of a bank or Financial Director of a PSU, it would not be able to deal with the complaints. Instead, the group of IAS officers will deal with such complaints. Under the DPE Order, a three-stage procedure has been set up for handling the complaints against

the top bosses. The first stage is that if there is no substance in the complaint, the group will close it. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : Thank you so much. Please conclude.

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI : Madam, this is a very serious matter.

MADAM SPEAKER : Yes, I know. But then, you must observe the time limit.

DR. KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI : Madam, I request the Government that the sanctity of the CVC should be established. Thank you, Madam.

MADAM SPEAKER : Thank you. Shri Anto Antony to speak now.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Respected Madam Speaker. I take this opportunity to invite your kind attention to the pathetic condition of the Indian travelers who are stranded in European airports due to the recent volcanic outbreak. The volcanic eruption at Eyjafyallajokaul Glacier in Iceland since 14th of this month has made air traffic impossible in the European countries. The European Aviation Agency – EuroControl indicates that no landings or takeoffs are possible for civilian aircraft in most of the Northern and Central European countries due to the ash spewed out by the volcano. The volcanologists predict that the ash may cause problems to the air traffic for as much as six months.

Madam, Europe is experiencing its greater disruption in air travel since September 11. In terms of closure of airports, this is worse than September 11. Over 70,000 flights are cancelled in and out of Europe so far. As per the current indication, the European airports may remain closed for another one more week. Many of the Indian nationals are stranded in European airports with limited option. Many of them need to travel by ferry from one European country to another; but it requires a Schengen visa. Ten industrialists from my constituency are stranded in Glasgow airport while traveling after attending a conference organized by the Scottish Tourism. Due to the absence of Schengen visa, they cannot move out of the airport.

The Government may give necessary direction to our Missions in the European countries to intervene in this matter and necessary assistance may be

provided to those who are stranded in various airports of European countries to come back to India urgently. Thank you, Madam.

MADAM SPEAKER: Shri Rajaiah Siricilla - Not present.

Shri Bishnu Pada Ray - Not present.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। भारत की कुल दरियाई सीमा 5700 किलोमीटर के आगे गुजरात 1663 किलोमीटर दरियाई सीमा वाला प्रदेश है। देश के कुल बंदरगाहों में से कंडला जैसे 40 छोटे-बड़े बंदरगाहों से विश्व भर में आयात-निर्यात गुजरात के पश्चिमी दरियाई सीमाओं से होता है। अलंग जैसे विश्व विख्यात बंदरगाह में जहाज तोड़ने का व्यवसाय होता है. गुजरात के साहसिक जहाजी उद्योगपति एवम् साहसी नाविकों द्वारा विश्व के बंदरगाहों तक माल-सामान का आवागमन हो रहा है।

इस व्यवसाय को आज सोमालियाई दरियाई लुटेरों ने खतरे में डाल दिया है। समुद्र में आतंक का साम्राज्य कायम कर चुके सोमालियाई दरियाई लुटेरों ने 129 भारतीय नाविकों एवम् आठ नौकाओं का अपहरण किया है। उनमें से तीन नौकाएं मुक्त कर दी हैं, क्योंकि उनमें कोई ठोस चीज दरियाई लुटेरों को नजर नहीं आई। खास कर दरियाई लुटेरे स्टीमर एवम् बड़े जहाजों को निशाना बनाते रहते हैं। पहली बार उन्होंने छोटी नौकाओं का अपहरण किया है, क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल लूट में किया जाता है। विश्व अन्न कार्यक्रम के तह अनाज का 90 प्रपतिशत दरियाई मार्ग से आता है। जिसे लूटे जाने से अनाज के दाम भी बढ़ गए हैं। सोमालियाई लुटेरे नौका एवम् नाविकों को बंदी बनाकर एवज में अवैध वसूली करते हैं और अपनी शर्तें मनवाते हैं।

इस आतंक से निपटने हेतु विविध देशों ने मिलकर (Combined Task Force-150) एडन के आखात में मरीन सिक्योरिटी पेट्रोल एरिया (MIPA) की रचना की थी। सन् 2008 से भारतीय नौ सेना ने भी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। वे सब कार्यरत हैं, फिर भी लूट होती रहती है।

इन लुटेरों में 20-25 वर्ष के युवा लड़के होते हैं। वे पूर्व सोमालिया के पैन्ट-बेड़ प्रदेश के रहने वाले एवम् आधुनिक शस्त्रों से लैस होते हैं।

गुजरात के वाहन वटी (Shipping) एसोसिएशन ने नौकाएं एवम् नाविकों की रिहाई हेतु आंदोलन शुरू किया है। जब तक मामला निपटेगा नहीं, तब तक माल परिवहन नहीं किया जाएगा। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है और नाविकों में एवम् नौकाओं के मालिकों में दहशत का माहौल बन गया है। गुजरात सरकार एवम् एसोसिएशन केन्द्र से आज भी संपर्कित है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि केन्द्र सरकार उपरोक्त मामले में शीघ्र ही कार्रवाई करे। नौकाएं और नाविकों की सक्षम सुरक्षा के लिए विश्व मंच पर भारत इस समस्या के हल के लिए ठोस कदम उठाए। इस गंभीर समस्या के बारे में आज सदन एवम् सरकार चर्चा, चिंता और चिंतन करे।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदया, मैं एक बहुत ही संवेदनशील मामला सदन में उठाना चाहती हूं। हिन्दुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। एक प्रजातांत्रिक देश में पुलिस को वास्तव में लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में या कस्टडी में लेने के बाद अगर उसका अता-पता नहीं लगता है तो यह एक चिंता की बात हो जाती है।

मैं अपने लोक सभा क्षेत्र की एक घटना की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे क्षेत्र से एक व्यक्ति दिलीप पाटीदार को मुम्बई एटीएस पुलिस मालेगांव ब्लास्ट घटना के संदर्भ में पूछताछ के लिए 10 नवम्बर, 2008 को मुम्बई ले जाती है, जबकि वह व्यक्ति उस घटना में कोई आरोपी नहीं है। इन्दौर के खजराला थाने में इस बात को दर्ज कराया गया कि हम इस व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। पूछताछ के लिए ले जाने के बाद, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद बार-बार जब उस व्यक्ति के परिवार वालों ने सम्पर्क किया कि वह आदमी कहां है, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। कभी कहा गया कि पूछताछ हो रही है, लेकिन मुम्बई ले जाने के बाद उस व्यक्ति का कोई पता नहीं कि कहां उसे रखा गया है। जब इस मामले को इन्दौर न्यायालय में हैबियस कॉरपस लगाई गई तो आज करीब डेढ़ साल के बाद अचानक पुलिस कहती है कि हमने तो उसे चार महीने बाद ही छोड़ दिया था। वास्तव में कानूनन रूप से जिस थाने से उस उठाकर ले जाते हैं, वहीं लाकर उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन मुम्बई एटीएस पुलिस ने यह उत्तर देकर कि हमने चार महीने बाद छोड़ दिया।

लेकिन मुम्बई एटीएस ने यह उत्तर दिया कि हमने चार महीने बाद छोड़ दिया, इसलिए अब उन्हें नहीं पता है कि वह कहां है। यह बहुत बड़ा अपराध है। अगर पुलिस स्टेशन में उसे प्रताड़ित करके मारा गया है, तो उसका उत्तर भी देना चाहिए। इस तरह से एक व्यक्ति को गायब करना और न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कोई उचित उत्तर नहीं देना, यह सही नहीं है। जगह-जगह गुहार लगाने के बाद आज मैं इसलिए यहां यह मामला उठा रही हूं कि गृह मंत्रालय इस मामले की जांच करे। दूसरे राज्य से पुलिस आ कर किसी व्यक्ति को उठा कर ले जाती है। यह मामला वहां दर्ज है। अगर इसके बाद भी वह लड़का नहीं मिले, तो उसके परिवार पर जो संकट आया है, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। वह आरोपी नहीं है, इसलिए मैं इतना बोल रही हूं। जो आरोपी है, वे तो जेल में ठीक हैं। कसाब जैसे आरोपी को आराम से जेल में

बिरयानी खाने को दी जा रही है और कोर्ट में पेशी कराई जाती है, लेकिन हिंदुस्तान का एक नागरिक, जो आरोपी भी नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि गृह मंत्री इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच कराएं और उस लड़के को लौटा दें या उसके वेयर एबाउट्स पता कराकर न्याय दिलाएं।

12.12½ hrs.

SUBMISSION BY MEMBER

Regarding: Need to address the problems being faced by victims affected due to natural calamities in Bihar

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, अपने देश में ज्यादातर लोग गर्मी से तबाह हो रहे हैं। 40 से 45 डिग्री गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। नील गायें मर रही हैं, हिरण मर रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है। इसी दौरान भारी तूफान आया। 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। बंगाल, बिहार और असम के बार्डर के इलाके तबाह हुए। बिहार के पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किश्नगंज में करीब सौ से ज्यादा लोग मर गए। हजारों घर बरबाद हो गए। इतनी तबाही हुई कि अररिया जेल की दीवार टूट गई। वहां से कैदियों को निकाल कर दूसरी जेल में ले जाना पड़ा। इसी प्रकार से बंगाल और असम में सैकड़ों लोग मरे हैं और हजारों घर बरबाद हुए हैं।

इसी प्रकार से बिहार में कम से कम पांच सौ गांवों में आग लगी है। 15 से 20 हजार गरीबों के घर जलकर राख हो गए हैं। कई लोग जल कर मारे गए। झुलसने से जानवरों की भी मृत्यु हुई। गरीबों की गाय, भैंस, बकरियां मरी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट कहां है? इसी सदन में डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी पारित की गई थी। कहां है राज्य सरकार, कहां है भारत सरकार? विपत्ति पर विपत्ति पड़ी, ओ दयानिधि तेरी गति देख न पड़ी। इसका मतलब कोई राहत नहीं है, कोई पुनर्वास नहीं है। नदियों के कटाव से अलग तबाही हो रही है। बूढ़ी गंडक, बागमती, गंडक, गंगा नदी की तबाही से 30 हजार परिवार बरबाद हो गए हैं। कहां पुनर्वास हो रहा है, कहां राहत मिल रही है, कहां है राज्य सरकार? मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसमें दखल दे, केवल राज्य सरकारों पर ही इसे न छोडे। यह प्राकृतिक आपदाएं हैं। सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, तबाही अलग होती है, आगजनी होती है। लोगों के घर जलते हैं, लोग मरते हैं और अगर सरकार सहायता के लिए खड़ी नहीं होगी, तो कौन खड़ा होगा? मेरी दर्खास्त है कि भारत सरकार बताए कि तबाही का आलम क्या है? क्या सहायता दी गई है, इस बारे में राज्य सरकारों से रिपोर्ट मंगाई जाए। इनका डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी सफेद हाथी की तरह है। कहीं भी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है। हजारों लोग जो बेघर हुए हैं, उन्हें कब तक घर मिलेगा? उनके लिए क्या राहत है?

पुनर्वास क्या है? जो मर गए हैं, उनका मुआवजा क्या है? प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार को खड़े होना चाहिए, नहीं तो तबाही है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, इसे दैवी आपदा में नहीं माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिन गांवों में इंसीडेंट हो रहे हैं, फसल जल रही है, लेकिन इसे दैवी आपदा मानकर अतिरिक्त सहायता नहीं दी जा रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए। आप अपने को इससे एसोसिएट कर लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं अपने आपको इस मामले के साथ एसोसिएट करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए हैं। आपको एसोसिएट करना है तो कीजिए नहीं तो बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप इनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप बैठ जाइए। जगदम्बिका पाल जी, आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइए। शून्य प्रहर कितने अच्छे से चल रहा था और आप अचानक इतना उत्तेजित हो गए।

...(व्यवधान)

* Not recorded

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): दिल्ली विकास प्राधिकरण का ग्रुप हाउसिंग विभाग में आम आदमियों को फ्रीहोल्ड हक हस्तांतरण विलेख लेने के लिए इस कार्यालय के सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं तब भी उन्हें फ्रीहोल्ड हक हस्तांतरण विलेख नहीं मिल पाता जो उनका मौलिक अधिकार है। सप्ताह में केवल दो ही दिन सोमवार और बृहस्पतिवार जनता दरबार लगता है। कभी-कभी तो पिता जी का फ्रीहोल्ड हक हस्तांतरण विलेख उसके पुत्र को लेना पड़ा है। इस कार्यालय में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है । बिना घूस दिए एक भी काम नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही बढ़ाने वाले नियम आम जनता के हित में बदले जाएं। दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल नियामक संस्था जैसा व्यवहार करे मालिकाना संस्था जैसा नहीं और सोसाइटी फ्लैटधारियों के उत्पीड़न को रोके। इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग विभाग के वर्तमान अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाए एवं उनके स्थान पर ईमानदार, युवा, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। मैं इस सदन के माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण एक ही तरह के एक प्रकार वाले फ्लैट के एक से ज्यादा अदला-बदली को फ्रीहोल्ड हक हस्तांतरण विलेख जारी करते हुए अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन करे ताकि लाखों लोगों को घर मिल सके, न्याय मिल सके और वे सुखी रह सकें। उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान में कम से कम एक मकान तो मिल सके।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Kaushalendra Kumar is saying.

(Interruptions) ... *

MADAM SPEAKER: Shri Bhoopendra Singh -- absent.

Shri Om Prakash Yadav

... (*Interruptions*)

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान): अध्यक्ष महोदया, मनरेगा योजना अति महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना केंद्र सरकार ने गरीबों को प्रांत और उनके घर में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लागू की थी। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि 15 फरवरी को माननीय नीतिश कुमार, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने

* Not recorded

अपने करकमलों द्वारा तालाब की सफाई की चार करोड़ आठ लाख की योजना का शुभारंभ किया था। मजदूरों के आग्रह पर मैंने रात के दस बजे योजना का निरीक्षण किया तो पाया कि चार जीसीबी मशीन और 10 ट्रैक्टर लगाए गए थे लेकिन वहां से मजदूर पलायन कर रहे हैं। मेरे पास सीडी और पेपर की कटिंग है। यह योजना बिहार में फ्लाप हो रही है। हमने ग्रामीण विकास मंत्री, श्री सी.पी. जोशी को आवेदन दिया और वहां के समाहर्ता को भी आवेदन दिया लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा आपसे आग्रह है कि भारत सरकार एक टीम भेजे और इस योजना की जांच कराए। यह चार-साढ़े चार करोड़ रुपए घोटाले का मामला बनता है, इस बारे में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए।

MADAM SPEAKER: Shri Premdas Katheria -- absent.

… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, उन गरीबों का क्या होगा जो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत होकर सुनिए, मंत्री महोदय कुछ कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, the hon. Member, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, has raised the issue of natural calamities and the people who had died in Bihar. This issue was raised by the hon. Members of other States also.

As far as the State of Bihar is concerned, I will bring the issue that has been raised by the hon. Member to the notice of the hon. Home Minister, who is in-charge and looking after the calamities. I will request him to look into the matter. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गई, अब उन्होंने बोल दिया है।

श्री महाबल मिश्रा (पश्चिम दिल्ली): माननीय अध्यक्षा महोदय, आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं, मैं समझता हूं कि इससे आप और आपके पिताश्री स्व. भारत रत्न श्री जगजीवन बाबू भी संबंध रखते हैं और डा. मंगल पांडे, राजेन्द्र बाबू और अन्य बहुत से महापुरुष संबंध रखते हैं। भोजपुरी को आठवीं सूची

में सम्मिलित करने के विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन क्षेत्रीय भाषा को भी...(व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज): भोजपुरी में बोलिये। ...(व्यवधान)

श्री महाबल मिश्रा : परंतु सबको समझ में आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : आप शान्त रहिये।

श्री महाबल मिश्रा : भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा का दर्जा मिला, लेकिन अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी अष्टम सूची में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया था और इस विषय में वर्ष 2007 में श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ने यहां आश्वासन दिया था कि भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में सम्मिलित किया जायेगा और इसके लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनी थी। उस कमेटी ने अपना निर्णय सरकार को दे दिया है। आज देश में लगभग 18 करोड़ जनता भोजपुरी भाषा बोलती है। यह भाषा केवल भारत में ही नहीं बल्कि सूरीनाम, फिजी और मारीशस में भी बोली जाती है और भोजपुरी के प्रति आज सारे लोग समग्रता के रूप में देखते हैं।...(व्यवधान) भोजपुरी एक व्यापक और समृद्ध भाषा है। देश के कई विश्वविद्यालयों में यह स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों में शामिल है। यह भाषा संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के सभी मापदंडों पर खरी उतरती है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इस पर हम भी आपका समर्थन करते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग अपने नामों की स्लिप टेबल पर भेज दीजिए।

श्री महाबल मिश्रा : मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि देश की 18 करोड़ जनता भोजपुरी बोलती है। परंतु नेपाली और सिंधी भाषा बोलने वालों की यहां संख्या नहीं है। लेकिन नेपाली और सिंधी जैसी भाषाओं को अष्टम सूची में शामिल किया गया है। लेकिन भोजपुरी जिसे 18 करोड़ जनता बोलती है, उसे अष्टम सूची में शामिल करने के विषय को सरकार ने नजरअंदाज किया है। मैं आपसे मांग करता हूं, क्योंकि आप भी उसी से संबंध रखती हैं, आप इस विषय में एक डायरेक्शन दे दें। जब केन्द्रीय मंत्री, श्री शिवराज पाटील यहां थे तो उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था और उसी वर्ष भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। लेकिन अभी तक यह काम क्यों नहीं हुआ, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

मैं आपसे मांग करता हूं कि जिस भाषा को बाबू जगजीवन राम बोलते थे और आपने भी उस दिन बोला था कि इस भाषा में 'मैं' नहीं 'हम' है। ये आपके शब्द हैं। कुर्सी पर आसीन महोदया के शब्द हैं, जिन्होंने कहा था कि भोजपुरी भाषा एक ऐसी भाषा है, जिसमें 'मैं' शब्द नहीं है, इसमें 'हम' शब्द है। मैं

आपसे आग्रह करता हूं कि भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में सम्मिलित करने के लिए आज आप सरकार को निर्देश दें। जिस भाषा को भारत की 18 करोड़ जनता बोलती है, उस भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में अविलम्ब शामिल किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया : प्रो. राम शंकर, श्री सतपाल महाराज, श्री रामकिशुन, डा.रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री शेलेन्द्र कुमार तथा श्री जे.पी.अग्रवाल इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान नागपुर शाखा द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 1.25 करोड़ रुपये से अधिक के सब्सिडी घोटाले के पर्दाफाश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज्य की भावना के तहत बैंकों के माध्यम से 25 लाख रुपये तक का ऋण देने का तय हुआ था एवं उक्त ऋण पर 4.5 लाख रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। परंतु खादी ग्रामोद्योग के अधिकारियों ने गैरपात्र लोगों के साथ मिलीभगत करके न केवल उन्हे बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया, बल्कि सरकारी सब्सिडी भी दिलवाई। खादी एवं ग्रामोद्योग के अधिकारियों की कृपा से रोजगार गारंटी योजना के लिए मिले धन से भंडारा व नागपुर के 5 व्यापारियों ने राइस मिलें खड़ी कर लीं।

सी.बी.आई. के छापे में ऐसे 52 मामले सामने आए हैं, जिनमें खादी और ग्रामोद्योग के अधिकारियों ने गैरपात्र लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई है। सी.बी.आई. की देशव्यापी कार्रवाई की शुरूआत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नागपुर कार्यालय में हुई है।

यह अत्यंत गम्भीर मामला है। इसलिए इस पर सरकार को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि गैरपात्र लोगों को सरकारी धन क्यों और कैसे दिया गया? केन्द्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो धन दिया था, उसका दुरुपयोग जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार का भ्रष्टाचार न होने पाये।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदया, आज हिन्दुस्तान टाइम्स में एक न्यूज छपी है कि HOT ROD HORROR BRANDS CHILDREN IN JHARKHAND, इसके बारे में मैंने नोटिस दिया है। जिस दिन मैं सांसद बना, मैंने दो जून को शपथ ली और तीन जून को मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और कहा कि झारखंड ट्राइबल स्टेट के नाते बनाया गया है। इसके बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि वहां जो गरीब आदमी रहते हैं, खासकर जो ट्राइबल आदमी रहते हैं, शैड्यूल कास्ट रहते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है और बिहार उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। मैंने लिखा कि वहां पीने का पानी नहीं है और

स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। एक आदमी की जिन्दगी के लिए कम से कम ये दो बुनियादी चीजों की आवश्यकता होती है। उन्हें पीने का पानी मयस्सर नहीं है और उन्हें स्वास्थ्य सेवा मयस्सर नहीं है। मैं लगातार कम से कम 15-20 चिट्ठी गुलाम नबी आजाद साहब को लिख चुका हूं, प्रधानमंत्री जी को लिख चुका हूं, लेकिन एक रटा-रटाया सा जवाब आया कि यह राज्य सरकार का काम है और इसे राज्य सरकार को करना चाहिए। हम इसके बारे में राज्य सरकार को लिख रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि मैं जिन बुनियादी सवालों को उठा रहा हूं, शिक्षा को उठा रहा हूं, स्वास्थ्य को उठा रहा हूं, पीने के पानी की समस्या को उठा रहा हूं या हंगर को उठा रहा हूं कि लोग बेकारी और भूख से मर रहे हैं, वह विषय राज्य सरकार का हो सकता है, लेकिन झारखंड से जो आप कोयला ला रहे हैं, इस देश का 70 परसेंट कोयला झारखंड दे रहा है। इस देश का 60 परसेंट बॉक्साईट झारखंड दे रहा है, इस देश का यूरेनियम झारखंड दे रहा है, इस देश का कॉपर झारखंड दे रहा है। आप वहां से सारा कुछ निकाल रहे हैं। कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसबिल्टी के नाम पर उस ट्राइबल के नाम पर आप सारी चीजें राज्य सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते। यदि आप सारी चीजें राज्य सरकार के ऊपर छोड़ते हैं तो आप रॉयल्टी लेना बंद कर दीजिए। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है कि अभी भी आप चेतिये, वहां पीने के पानी के बिना पूरे झारखंड के लोग, संथाल परगना के लोग, संथाली ट्राइबल पीपुल मर जाएंगे, स्वास्थ्य के बिना मर जाएंगे। वहां एक भी हॉस्पीटल नहीं है। मैंने बार-बार लिखा कि यदि वहां के लोग बीमार होते हैं तो उनके पास बिहार में भागलपुर, पटना या यहां दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। कहीं भी एक हॉस्पीटल नहीं है। मेरे डिस्ट्रिक हॉस्पीटल गोड्डा में ऑक्सीजन के बिना लोग मर गये हैं। मैंने बार-बार आपका ध्यान आकृष्ट किया है और यदि आप नहीं चेते तो महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि झारखंड किसी दिन यदि नागालैंड हो जाए, झारखंड किसी दिन यदि जम्मू-कश्मीर हो जाये तो इसका दोषी केंद्र होगा और हम और आप जैसे लोग, जो यहां संसद में बैठे होंगे, वे होंगे।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि केंद्र सरकार को एक नया प्लान बनाना चाहिए। प्लानिंग कमीशन में एक नयी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वहां के लोगों को पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आने-जाने का साधन मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): महोदया, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा पूर्वांचल है, जहां पर इस समय दैवीय आपदा से हजारों एकड़ फसल का प्रतिदिन, अप्रैल के महीने में नुकसान हुआ है। वहां हवा चली है। कई गावों की फसलें तो साफ हो ही गयी हैं, आवास तक जल गये हैं। सेंट्रल रिलीफ फंड योजना से केंद्र सरकार आवास और फसल नुकसान के लिए पैसा देती है। सारे जनपदों से रिपोर्ट बनकर आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं दी गयी है। इस आग लगने का प्रमुख कारण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है। यह जो योजना उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, इसके तार वहां ठीक से नहीं लगाये गये हैं। जब हवा चलती है तो तार एक-दूसरे से सटते हैं, चिंगारी भड़क उठती है और पूरा का पूरा इलाका आग से खत्म हो जाता है । दस-दस किलोमीटर का इलाका पूरा साफ हो जाता है। दैवीय आपदा में जो इंदिरा आवास की सीमा का प्रावधान है, वह केवल पचास लाख रूपये का है। महोदया, मैं आपके जरिये सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दैवीय आपदा से नुकसान होने पर इंदिरा आवास के लिए जो पचास लाख रूपया दिया जाता है, इसे बढ़ाया जाए

पूर्वांचल के लोग बाढ़ की मार अलग झेलते हैं और यहाँ इतना भीषण अग्निकांड भी होता है कि दस-दस किलोमीटर तक पूरा इलाका साफ हो जाता है। पूरी की पूरी फसलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वहाँ पर छोटे-छोटे काश्तकार हैं। कई जगहों पर तो ऐसा हो जाता है कि उन लोगों ने अपनी लड़कियों की शादी तय की होती है और उनको शादियाँ टालनी पड़ती हैं क्योंकि उनको कोई सहायता नहीं मिल पाती। हम सरकार से आपके माध्यम से विनती करना चाहेंगे कि ऐसे इलाकों में विशेष रूप से त्वरित आर्थिक सहायता दी जाए और जिनके आवास जल गए हैं, उनके आवास की व्यवस्था ज़रूर करवाई जाए और फसलों की क्षतिपूर्ति भी देने का प्रावधान किया जाये ।।

अध्यक्ष महोदया : श्री हंसराज अहीर जी, आपने दो विषय दिये हैं, किसी एक पर बोलिये। किस विषय पर बोलेंगे?

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): मैं विद्युत पर बोलूँगा।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदया, हमारे देश में बिजली की कमी सभी राज्यों में है लेकिन महाराष्ट्र में बिजली की सर्वाधिक कमी है। महाराष्ट्र में 6500 मैगावाट बिजली की कमी होने की वजह से वहाँ के अनेक क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं जिनमें कृषि है, उद्योग है, शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है और बेरोज़गारी भी इससे बढ़ी है। बार-बार जनप्रतिनिधि और राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से अधिक बिजली मांगने का प्रयास भी किया लेकिन यह सब होते हुए भी एक गंभीर मामला हमारे सामने आया है। महाराष्ट्र में करीब

करीब आठ बिजलीघरों में 9000 मैगावाट बिजली बनाने की क्षमता है है। उनमें सिर्फ 5000 मैगावाट बिजली ही बन पा रही है। इसका कारण यदि कुछ है तो महाराष्ट्र सरकार का बिजली बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार के संबंधित मंत्री और मुख्य मंत्री, इन बिजलीघरों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण महाराष्ट्र की जनता में बेरोज़गारी बढ़ी है और कृषि-उत्पादन प्रभावित हुआ है, उद्योग प्रभावित हुए हैं। इसकी तरफ सरकार अनदेखी कर रही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहूँगा कि जितने भी बिजलीघर चलते हैं, सब केन्द्र सरकार की मदद से चलते हैं। केन्द्र सरकार का कोयला मंत्रालय कोयले की आपूर्ति करता है और सभी पावर प्लांट्स में कोयले का स्टाक भरा पड़ा है। यह सब होते हुए भी बिजली कम उत्पादन होने का कारण यह है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है, वह मिली-जुली सरकार है, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं और ऊर्जा मंत्री एनसीपी के हैं। इन दोनों के झगड़े में सभी पावर प्लांट्स में बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार की मदद से जो पावर प्लांट्स चलते हैं उनका काम ठीक न होने से महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता प्रताड़ित है। वहाँ के लोग चिन्तित हैं। इनको पूरी बिजली मिलने के लिए केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि ये पावर प्लांट्स अपनी पूरी क्षमता से चलें। मैं विनती करूँगा कि इस देश में चन्द्रपुर में इस देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट है जहाँ 2340 मैगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। वहाँ के लिए मैंने जानकारी मांगी तो 1200 मैगावाट बिजली वहाँ प्रतिदिन बनती है जबकि 2340 मैगावाट की क्षमता है। सरकार इसको पूरी तरह से चलाने में अक्षम है। यह मुख्य मंत्री और मंत्री की ओर से उपेक्षा हो रही है ...* इसको ध्यान में रखते हुए जो महाराष्ट्र का बिजली बोर्ड है, वह अपनी लापरवाही से और भ्रष्ट नीति से पावर प्लांट को सही नहीं चला पा रहा है।

अध्यक्ष महोदया : आपने अनपार्लियामैंट्री शब्द का इस्तेमाल किया है। Please delete it.

श्री हंसराज गं. अहीर : महाराष्ट्र की जनता पीड़ित है। इनको बिजली देने की मांग मैं संसद में रख रहा हूँ। मैं केन्द्र सरकार से और विद्युत मंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पावर प्लांट केन्द्र द्वारा चलाने हेतु टेकओवर करें, अपने कब्ज़े में लें और केन्द्र सरकार के एनटीपीसी द्वारा चन्द्रपुर पावर स्टेशन को चलाया जाए, यह विनती मैं करता हूँ।

MADAM SPEAKER: Shri Vishwa Mohan Kumar – Not present.

Shri Suresh Kumar Shetkar – Not present.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अति लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

---

* Expunged as ordered by the Chair

2005 में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट से और उत्तर प्रदेश की विधान सभा से 17 जातियों को, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, इनको अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया जो आज तक लंबित है। इसमें केसरवानी वैश समाज है, राजभर है, निषाद् है, प्रजापति है, मल्लाह है, कहार है, कश्यप है, कुम्हार है, धीमर है, बिन्द है, केवट, धीवर, बाथम, मछुआ, मांझी, तुरहा, अगोड़ है और इसके अलावा कोल जाति को भारत के अन्य सभी प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्राप्त है।

लेकिन उत्तर प्रदेश में कोल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके कारण से इन जातियों की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि समाज में जो पिछड़ी और उपेक्षित जातियां हैं, जिनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करके, इनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाया जा सकता है। केन्द्र सरकार में लम्बित प्रस्ताव को तत्काल अनुसूचित जाति में शामिल करे, ताकि इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और अपने को ये आगे बढ़ा सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन जातियों के जितने भी लोग हैं, वर्तमान में जो सरकार है, उसने इसको खारिज कर दिया है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां से निर्देश जाए, केन्द्र सरकार निर्देशित करे। धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं, केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय में ऐसे लोगों की पुलिस में भर्ती की गई, जो कि अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति में शामिल नहीं थे, उनकी एकतरफा भर्ती की गई थी।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, यह बहुत गम्भीर मामला है, इस पर मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदया, देश में जापानी इन्सीफ्लाइटिस, कालाजार, डेंगू, टिटनिस, काली खांसी तथा अन्य तमाम वैक्टर जनित बीमारियों से हजारों मौतें होती हैं। इन मौतों को रोकने के लिए इस देश के अंदर कुछ विशेष प्रकार के टीकाकरण की व्यवस्था थी और उसके लिए कुछ संस्थान स्थापित किए गए थे, जिनमें केन्द्रीय शोध संस्थान, कसौली; पाश्चर इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया, कुन्नूर; बीसीजी लैब,

* Not recorded

गिंडी और भी तमाम ऐसे संस्थान थे, जहां टीकाकरण बनाए जाते थे और इनके माध्यम से बैक्टर जनित बीमारियों के रोकथाम का प्रावधान था। यह दुखद है कि दो वर्ष पूर्व इन सभी संस्थानों को बंद कर दिया गया और उसका परिणाम है कि देश के अंदर पिछले दो वर्षों से वैक्टर जनित बीमारियों का प्रतिरोधी टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हजारों मौतें हो रही हैं। जापानी इन्सीफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों मौतें होती हैं, कालाजार और डेंगू से बिहार में जो मौतें होती हैं, उनकी बातें लगातार हम इस सदन में उठाते रहे हैं और इस बात की मांग करते रहे हैं कि टीकाकरण उसका एक माध्यम हो सकता है क्योंकि टीकाकरण से प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी और वैक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो संस्थान बंद किए गए हैं, यह कुछ निजी संस्थानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और साथ ही साथ विदेशों से टीका मंगवाए जाने के लिए किए गए हैं। हमारे देश में करोड़ों वैक्सीन्स की आवश्यकता है। इसमें कुछ लोगों की मिलीभगत है, इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। केवल डब्ल्यूएचओ को माध्यम बनाकर भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के टीकाकरण संस्थानों को बंद करना, इस देश के गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को बंद किया गया है, उन्हें पुनः चालू किया जाए, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए, उनकी गुणवत्ता को बेहतर करने का प्रयास हो और जापानी इन्सीफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया या वैक्टर जनित जितनी भी बीमारियां हैं, इन बीमारियों की रोकथाम करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

SHRI RAJAIAH SIRICILLA (WARANGAL): Madam Speaker, I am very thankful to you for giving me this opportunity. I rise today to bring certain facts, through you, before this august House. This is with regard to the sharing of water. There are several disputes in sharing of water. We all know that India is an agricultural country.

More than 80-85 per cent of the people are living in rural India and are dependent on agriculture. Most of the water is available only due to rains. We are utilizing just 10-15 per cent of that rain water and the rest is going waste. It is a peculiar situation in our country that on the one side we are facing floods and on the other side, we are facing drought situation. We are suffering not only for want of water for irrigation purposes, but also for drinking purposes. At the same time, there are

disputes in sharing the river waters. These disputes are pending in several courts for several years and we are not able to sort out this issue. This not only creates inter-State disputes, but this is also putting certain amount of pressure on the Government of India.

As of now, the subject of water is in the State List, but there is a feeling that it could no more continue to remain in that List, in the interest of the country and in the interest of the federal system. If it remains so, it may create certain other problems in the future.

Therefore, I would request the House, through you, Madam to consider this. This is the right time to think of bringing the subject of 'water resources' into the Central List or if not, at least into the Concurrent List so that water can be safely and without any dispute distributed among the needy areas of the country. Thank you.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे माफी मांगता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिए।

श्री विष्णु पद राय : मैडम, 1948 में भारत सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया था, उसके सैक्शन फोर के मुताबिक यह कहा गया था कि जब-जब सामान का दाम बढ़ेगा, प्राइस इन्क्रीस होगा, इन्फलेशन होगा, उस तरह से उन्हें बढ़ोत्तरी मिलेगी। उसी मुताबिक 1988 में लेबर मिनिस्ट्री कांफ्रेंस में इन्फ्लेशन के ऊपर यह फैसला हुआ था कि सामान का दाम बढ़ने पर उसे साल में दो बार प्राइस इंडेक्स के माध्यम से, उसकी मजदूरी बढ़ाई जाएगी। इसे देखते हुए 36 राज्यों में, खास करके यूनियन टेरेटरीस, लक्ष्यद्वीप, पांडीचेरी, गोवा, दिल्ली तथा बाकी राज्यों में भी उस तरह से साल में दो बार जब सामान का दाम बढ़ता है तो उन्हें भी उसके मुताबिक मिलता है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को साल में दो बार डीए मिलता है, उसी तरह मजदूर के लिए भी ऐसा किया गया था। लेकिन दुख की बात है कि अंडेमान और निकोबार द्वीपसमूह में सरकार का यह निर्देश संविधान के मुताबिक एक्ट या लेबर मिनिस्ट्री कांफ्रेंस का डायरेक्शन वहां माना नहीं जाता।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि अंडेमान और निकोबार द्वीपसमूह में भी, जैसे आपने बाकी राज्यों में किया, लेबर मिनिस्ट्री कांफ्रेंस को डायरेक्शन दिया गया, उसी मुताबिक अंडेमान-

निकोबार द्वीपसमूह में मिनिमम वेजेस में वेरिएबल डीए साल में दो बार वहां के मजदूरो को मिले, इस मांग के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया: श्री विश्व मोहन कुमार - अनुपस्थित।

श्री प्रेमदास (इटावा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आठ-दस साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक स्कीम चली। मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन था, उसमें प्रस्ताव पास करने का मौका मिला था। उसमें यह था कि दो हजार वाली आबादी के गांव पहले जोड़े जाएंगे, उसके बाद एक हजार आबादी वाले गांव जोड़े जाएंगे और फिर पांच सौ आबादी के गांव जोड़े जाएंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी एक हजार, दो हजार आबादी के तमाम ऐसे गांव पड़े हुए हैं, जो सड़क से नहीं जुड़े। प्रधानमंत्री सड़क योजना में पांच साल का मेंटीनेंस था, आज दो-तीन साल बाद सड़क टूट जाती है और कोई मेंटीनेंस नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजती हैं, लेकिन जो हम लोग मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता है।

13.00 hrs.

हम लोग गांवों में जाते हैं, तो देखते हैं कि तमाम गांव बगैर सड़कों के हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर बनने वाली सड़कों के प्रस्ताव सांसद से लिए जाएं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र औरैया में ऐसे तमाम गांव हैं जो चार-चार और दस-दस किलोमीटर दूर हैं, जिनमें आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उनमें सड़कें बनाई जाएं। जैसे ऐली गांव है, जमालपुर गांव है और छोकर की मडैया पुरवा है। इन्हें सड़कों से जोड़ा जाए।

महोदया, 18 और 20 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से सड़कें बनती हैं, लेकिन राज्य सरकारों के अधिकारी और कर्मचारी उनमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं, जिसके कारण बहुत घटिया किस्म का काम हो रहा है। इसकी जांच कर के हमें अवगत कराया जाए, क्योंकि इसमें केन्द्र सरकार का पैसा लग रहा है, इसलिए केन्द्र सरकार इस बारे में एक समिति बनाए, ताकि इस योजना में जो अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा सके।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): अध्यक्ष महोदया, देश में शिक्षा-माफियाओं का जाल फैलता जा रहा है। फर्जी-नकली सर्टीफिकेट और डिग्रियां बेची जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षा का स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। फर्जी, नकली सर्टीफिकेट बनाने वाले गिरोह पूरे देश में फैल गए हैं। ज्यादातर उत्तर प्रदेश के मेरठ में तो इसका गढ़ है। देश में आतंकवाद से बड़ा खतरा, तो फर्जी-नकली सर्टीफिकेट बनाने वाले गिरोहों का है, जो हमारी शिक्षा और हमारे दायित्व को समाप्त कर रहे हैं। ये नकली सर्टीफिकेट बनाने वाले इस तरह से सर्टीफिकेट बनाते हैं कि असली और नकली की पहचान भी आसानी से नहीं की जा सकती है। इसके कारण आम जनता में जनाक्रोश है, क्योंकि फर्जी सर्टीफिकेट के आधार पर कुछ लोग आसानी से नौकरी पा लेते हैं और मेहनती तथा ईमानदार बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि जनहित में फर्जी सर्टीफिकेट और डिग्री बनाने वाल गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसे रोकने के लिए स्मार्ट कार्ड देने की व्यवस्था हो। धन्यवाद।

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.04 hrs.

The Lok Sabha reassembled after lunch at Four Minutes past Fourteenth of the Clock

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

14.04½ hrs.

FELICITATIONS TO HON. DEPUTY SPEAKER ON HIS BIRTHDAY

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, आज आपका जन्मदिन है। हम सब की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

14.05 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Hon. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

(i) Need to announce a special rehabilitation scheme for the people whose land is being acquired for the development of National Highway in Kerala

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA) In my state of Kerala, the land acquirement is being done by National Highways Authority of India for the expansion of National Highways. It has created lot of problems and difficulties to the general public, who reside on both sides of the National Highway. Thirty years ago the Authority had acquired land up to 30 meters in width for the development of National Highway but till today there is no development. Now, the Authority is planning to acquire land again for the expansion of the Highway up to 45 meters. As Kerala is number one in density of population and the repeated acquirement of land caused lot of problems in the area. Besides this the alignment prepared for the acquirement also raises various doubts about the project. The rehabilitation package announced at national level is not sufficient due to high price of land. The Government has to announce a special rehabilitation scheme for Kerala, which is acceptable to the affected people.

* Treated as laid on the Table

(ii) Need to make Yamuna river pollution free

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, राजधानी दिल्ली में इस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, जिस कारण इस वर्ष बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुमान है । लेकिन, राजधानी दिल्ली से गुजरने वाली पौराणिक नदी यमुना की स्थिति अत्यन्त खराब है । यमुना की सफाइ पर आज तक अरबों रूपया व्यय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यमुना प्रदूषित बनी हुई है । यमुना में 70 प्रतिशत प्रदूषण देश की राजधानी से हो रहा है, जबकि बाकी जिन शहरों से यमुना गुजरती है, उनमें से केवल 30 प्रतिशत ही यमुना मैली होती है । स्थिति यह है कि राजधानी दिल्ली में यमुना वजीराबाद से लेकर दक्षिण में ओखला बैराज तक 22 कि0मी0 के रेंज में प्रदूषित होकर नाले में परिवर्तित हो चुकी है । यमुना में 17 बड़े नाले गिरते हैं । इनमें सबसे ज्यादा गंदगी नजफगढ़ व शाहदरा ड्रेन से होती है ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार यमुना में लगातार प्रदूषण बढ़ने के कारण इस समय यमुना में बायॉलजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बी ओ डी) 41 मिलीग्राम प्रति लीटर है जबकि मानकों के मुताबिक बी0ओ0डी0 केवल 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । इसी तरह यमुना में प्रदूषण फैलाने वाले कुल कॉलिफोर्म की संख्या भी 2.4 करोड़ प्रति 100 मिलीलीटर है । जबकि मानकों के अनुसार कुल कॉलिफार्म की संख्या 100 मिलीलीटर पानी में 5 हजार से कम ही रहनी चाहिए । इन्हीं के कारण यमुना में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ऑक्सिजन की मात्रा कम होती जा रही है ।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राजधानी दिल्ली में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी को प्रदूषण रहित बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाए ।

(iii) Need to open a new Railway Station at Maharajanagar on Tirunelveli-Tiruchendur Section in Tamil Nadu

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Tirunelveli is the second largest district in Tamil Nadu. This district has diverse geographical and physical features. It has lofty mountains and low plains and blessed with beautiful waterfalls and cascades and large number of tourists are visiting this place throughout the year. However, the people residing in the outskirts of Tirunelveli are facing a lot of difficulties to reach the railway station due to urbanization and the resultant traffic chaos.

There is a long pending demand for opening up of a New Railway Station at Maharajanagar on Tirunelveli-Tiruchendur Section, both on the northern and the southern side of the track. Large number of colonies, Government offices colleges and residential houses are located here and more are coming up and the population in this area exceeds 70,000 and it may cross 1 lac. mark in the near future. However, the people are not having any railway station nearby and they have to use Palayamkottai station which is 5 kms. away from their area. Vacant lands at two suitable sites are available nearby for construction of a new railway station.

This request is genuine and pending since long and I understand that it is under the active consideration of the Ministry of Railways. People from all walks of life have represented and favoured for a new railway station. I, therefore, request the Hon'ble Minister to take up the matter on priority basis and release adequate funds for opening of a New Railway Station at Maharajanagar, Tirunelveli at the earliest.

(iv) Need to accord approval to the proposal of Government of Rajasthan to introduce metro train in Jaipur

श्री महेश जोशी (जयपुर): महोदय, ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व के बड़े पर्यटक स्थलों में से एक होने के साथ ही जयपुर नए विकास की दृष्टि से भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है । देश के प्रमुख शहरों में आबादी के बढ़ने की दृष्टि से भी जयपुर सबसे आगे है जहाँ पिछले दशक 2010-11 के बीच 34.78 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी । जयपुर की आबादी वर्तमान में 31 लाख से अधिक है ।

लोकसभा के पिछले सत्र में केन्द्र सरकार ने तय किया था कि 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में मेट्रों ट्रेन चलाए जाने की योजना अगर राज्य सरकारें बनाती हैं तो उन्हें मंजूरी एवं आर्थिक सहयोग दिया जाएगा । जयपुर की आबादी, तीव्र विकास एवं नगरीय परिवहन की व्यवस्था के मद्देनजर तार्किक एवं व्यवहारिक दृष्टि से जयपुर में मेट्रो ट्रेन चलाया जाना एक बहुत ही सार्थक कदम माना जाएगा ।

राज्य सरकार की ओर से मेट्रो संचालन के लिए एक डी.पी.आर. केन्द्रीय नगरीय विकास विभाग, नई दिल्ली को फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत कर दी गयी थी एवं नए बजट सत्र 2010-11 में भी राज्य सरकार ने शुरूआती अंशदान के रूप में अपनी ओर से 179 करोड़ रूपए का प्रावधान करने के साथ ही जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन का गठन भी कर दिया है ।

मेरा आपसे आग्रह है कि जयपुर की जनता की भावनाओं को देखते हुए गुलाबी नगर जयपुर की इस बहुत महत्वाकांक्षी एवं व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ताकि इस योजना पर अविलंब व अतिशीघ्र कार्य आरंभ् किया जा सके ।

(v) Need to restore Athoor Anicut Channel in Athoor village of Dindigul district, Tamil Nadu

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): The Kodaganar river originates from hilly terrain at Athoor village of Athoor block in Dindigul District, Tamil Nadu. The river is one of the major tributaries of Cauvery river and confluences with Amaravathy river. During North East Monsoon, appreciable flow is realized in the river serving the ancient irrigation system comprising 7 anicuts filling tanks through supply channels. Kodaganar dam is a major reservoir constructed across Kodaganar river.

Athoor Anicut channel is a first supply channel which originates from first anicut and the supply channel is irrigating 311.12 ha of single crop and 11.50 ha of double crop directly and the supply channel is feeding three tanks namely Karunkulam, Pagadaikulam and Pilvettikulam which is having total ayacuts of 277.35 ha single crop and 34.90 ha of double crop and 260 ha single crop through wells situated around this system. Then the supply channel joins Kodaganar.

The average annual rainfall in this hilly region of Kodaganar is adequate.

It is proposed to line the supply channel and field channel by cement concrete in its entire length of 6980 m and to repair sluices of supply channel and it is also proposed to standardize the both sides banks of supply channel.

By executing the project at a cost of less than Rs. 10 crores the gap of 306.55 ha in single crop and 46.40 ha in double crop will be bridged and 419.14 ha of single crop will be converted as double crop. It will cause an additional food production of 4055.79.MT per year. This Project will be executed in one year from the date of sanction.

I urge upon the Ministry of Water Resources to take up this project for execution so that farmers of our constituency could be benefited.

(vi) Need to direct Bhakra Beas Management Board to release water to Rajasthan

SHRIMATI CHANDRESH KUMARI (JODHPUR): With your kind permission I would like to raise an important matter under rule 377 regarding releasing of water share for the State of Rajasthan by the Bhakra Beas Management Board. Hon'ble Chief Minister of Rajasthan has also written to the Hon'ble Prime Minister of India regarding releasing of water. The Rajasthan State Government gets its share of water from the river Ravi-Beas by Ranjit Sager Dam, Pong Dam and Bhakra Dam. The Ranjit Sagar Dam is under the control of Punjab State Government and the rest of the two are under Bhakra Beas Management Board. The Punjab Government is not releasing the share of 72,000- qusec. of water to Rajasthan Government. Due to this the Indira Gandhi Canal, which is the main feeder of water for Rajasthan, is always short of water. The minimum required water is around 2200 qusec. whereas the water released is only 1100 qusec. Due to this, the farmers and the general public is not getting adequate quantity of water. The people of Rajasthan are very angry with this. Whereas the Central Government has declared Rajasthan as drought-hit area, still BBMB is not paying any heed to our repeated requests.

The Punjab Reorganized Act 1966 Section 79 clearly says that this is the responsibility of the Bhakra Beas Management Board to provide water to the concerned States. Still nothing has been done by the Bhakra Beas Management Board.

I would urge upon the Hon'ble Prime Minister to instruct the Bhakra Beas Management Board to release the share of water to Rajasthan immediately.

(vii) Need for central assistance to construct another Legislative Assembly of Uttrakhand at Gairsain

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए 9 नवम्बर, 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नये राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया । इस राज्य को पहाड़ की जनता ने इस भावना से बनवाया था कि उनकी विधान सभा, उच्च न्यायालय, शिक्षा, पुलिस व स्वास्थ्य मुख्यालय आदि उनके अपने पहाड़ में ही सित होंगे तथा पहाड़ी क्षेत्रों का विकास भी मैदानी इलाकों की तरह तेजी से होगा तथा वहां की जनता की आय के साधन बढ़ेंगे ।

जिस प्रकार अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विधान सभाओं के सत्र दो-दो स्थानों पर होते हैं उसी प्रकार उत्तराखंड में भी विधान सभा के सत्र देहरादून तथा गैरसैण में किये जाएं । उन राज्यों में दो-दो स्थानों पर सत्र होने से जम्मू एवं धर्मशाला का विकास उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार श्रीनगर एवं शिमला का । वहां के लोगों के रोजगार के अवसर बढ़े हैं तथा विधान सभा सत्र होने से प्रशासनिक तंत्र भी विकास में तीव्रता दिखाते हुए कार्य करता है ।

गैरसैण उत्तराखंड का वह क्षेत्र है जो उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊँ क्षेत्रों के मध्य में स्थित है । यदि वहां विधान सभा का सत्र होता है तो गढ़वाल एवं कुमाऊँ दोनों क्षेत्रों का विकास समान रूप से होगा तथा उत्तराखंड राज्य के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उनकी भी मनोभावना पूर्ण हो सकेगी । मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार उत्तराखंड में भी इसी प्रकार की व्यवस्था गैरसैण में करें, वहां भी एक विधान सभा भवन बनाया जाए जिससे वहाँ भी सत्र होने पर प्रदेश का समग्र विकास हो सके ।

राज्य सरकार के सीमित संसाधान होने के कारण इस विधान सभा भवन को बनाने के लिए केन्द्र सरकार को पूर्ण रूप से सहयोग करना होगा तभी यह कार्य संभव हो पायेगा ।

(viii) Need to maintain only one toll plaza in Dindori Parliamentary Constituency, Maharashtra and stop collecting toll tax in tribal areas

SHRI HARISHCHANDRA CHAVAN (DINDORI): Rule 8 of the sub rule (2) of Toll Tax Policy provides that there should not be two toll plazas within the 60 km area. My constituency is situated in tribal and economically backward area. As most of the people are engaged in farming. People are facing lot of problems due to these toll plazas within the 60 km area.

I request Hon. Minister of Road Transport and Highways to maintain only one toll plaza in my constituency area as per the rule and give justice to the poor and tribal people.

In the meeting of District Planning Development Committee (DPDC), Nashik it was decided to stop collecting toll in all the tribal areas but still toll is being collected in my tribal constituency. I, therefore, urge upon the Government to issue necessary instruction for stopping collection of toll tax in tribal areas.

(ix) Need to undertake developmental works in tribal areas and allot forest land to Adivasis in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत नर्मदा जिले के डिडिया पाडा एवं सागबारा तालुकों में एवं भरूच जिले के झगड़िया तालुक के अंतर्गत आदिवासियों हेतु विकास संबंधी कार्य जैसे सिंचाई परियोजनाएं, स्कूल निमार्ण, सड़क निर्माण इत्यादि कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण आदिवासी लोग विकास संबंधी सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है । दूसरी ओर संसद ने वन अधिकार के अंतर्गत जो कानून पास किया है उसके तहत आदिवासी लोगों को वन क्षेत्र की जमीन का वन संबंधी कानून के कारण जमीन आबंटन नहीं हो पा रहा हे ।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध हे कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य किए जायें और वन अधिकार के अंतर्गत आदिवासी लोगों को रहने एवं खेतीबाड़ी करने हेतु वन क्षेत्र की जमीनों का आबंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ।

(x) Need to provide adequate medical facilities to rural expectant mothers under National Rural Health Mission in the country

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव व मातृत्व सुरक्षा की देखभाल के संबंध में मंत्रालय ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एक अध्ययन कराया है। अध्ययनकर्ताओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा उपरांत जो रिपोर्ट दी है उसमें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में तैनात ए.एन.एम. और डेढ़ लाख स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की सच्चाई का खुलासा है। इस संबंध में यूनिसेफ ने भी कहा है कि प्रसव हेतु न्यूनतम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट (एसबीए) नियुक्त होने चाहिए।

यही कारण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 52 हजार करोड़ रूपए खर्च करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव व मातृत्व सुरक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवाएं अब तक कारगर नहीं हो पाई हैं। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को अच्छी करके प्रसव के दौरान महिलाओं की मौतों में कमी लाई जा सके लेकिन इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है।

स्वास्थ्य केन्द्रों की दुर्दशा, अध्ययनकर्ताओं के आंकड़ें, खुद-ब-खुद बयान करते हैं। 26 फीसदी केन्द्रों में प्रसव टेबल तक नहीं हैं, 71 फीसदी केन्द्रों में डिस्पोजेबल प्रसव किट नहीं है, 52 फीसदी ए.एन.एम. की ड्रग किट खाली हैं, 33 फीसदी केन्द्रों में चिकित्सकीय उपकरण नहीं हैं। प्रसव सिर्फ 21 फीसदी उपकेन्द्र पर होते हैं।

मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक बनाने हेतु अविलम्ब अध्ययनकर्ताओं द्वारा दर्शाई गई कमियों का समाधान करें, जिससे ग्रामीण महिलाओं को उचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

(xi) Need to construct a permanent bridge on river Ghaghra at Kamhariya Ghat in Sant Kabir Nagar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): घाघरा नदी पर कमहरिया-घाट जो हमारे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। नदी के आर-पार जाने के लिए वहां की जनता को इसी घाट पर से पार होकर आना जाना पड़ता है। मुझे यह अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 62 साल बाद भी आज तक वहां एक स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो सका।

महोदया जी, यह घाट गोरखपुर से इलाहाबाद को जोड़ता है। अगर यहां पर एक स्थायी पुल का निर्माण हो जाये तो गोरखपुर से इलाहाबाद के लिए 70 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी, जिससे काफी वाहन ईंधन की बचत भी होगी। महोदया जी, इस घाट के ऊपर एक पीपे का अस्थाई पुल है जो जून से दिसम्बर तक बंद रहता है तथा वहां के निवासियों को नाव के द्वारा इस अवधि में नदी पार करनी पड़ती है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तथा काफी जान-माल का नुकसान प्रतिवर्ष होता है।

अतः आपसे आग्रह है कि यहां एक स्थायी पुल का निर्माण कराया जाये, जिससे कि यहां के लोगों को सुविधा हो सके।

(xii) Need to consult local M.Ps. in construction of roads and bridges under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से चलाइ जा रही अत्यंत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजना की खामियों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी, पिछड़े प्रांतों के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जन-सामान्य की सुविधा एवं बेहतर सड़क सम्पर्को के उद्देश्य से चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना का सही लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि धन की कमी के कारण एक तरफ जहां कार्य प्रगति की गति धीमी है वहीं दूसरी ओर किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। संयुक्त रूप से इस कार्य में लगी केन्द्रीय एजेंसी इर्कोन तथा राज्य सरकार का ग्रामीण विकास विभाग, जिस पर इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन का दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी के सम्यक निर्वहन में सक्षम नहीं है। हालत यह है कि स्थानीय सांसद जो कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अध्यक्ष होते हैं तथा विजिलेंस मोनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी शिकायतों पर न तो यह एजेन्सियां गौर करती हैं और न तो धीमी कार्य प्रगति का कोई समुचित कारण इनके पास है, जिससे इस योजना का समुचित लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इस योजना के अंतर्गत बनी सड़कों को जोड़ने हेतु छोटे-छोटे पुलों का निर्माण भी इसी योजना से कराये जाने की आवश्यकता है क्योंकि कई स्थानों पर छोटे-मोटे पुलों के अभाव में इस योजना से निर्मित सड़कों को आपसी सम्पर्क समाप्त हो जाता है और इन सड़कों का लाभ छोटे नदी-नालों के दोनों ओर बसने वाली ग्रामीण आबादी को नहीं मिल पाता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की जानकारी समय-समय पर स्थानीय सांसदों को दी जाये तथा इस योजना के तहत सड़कों के निर्माण में स्थानीय सांसदों से उनकी राय भी ली जाये।

(xiii) Need for early revival of the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, Haldia Division, West Bengal

SHRI SUVENDU ADHIKARI (TAMLUK): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Chemicals and Fertilizers towards the Hindustan Fertilizer Corporation Limited, Haldia Division situated in my Parliamentary constituency. This industry started functioning in 1979. The company manufactured Ammonia, Methanel, Urea, Nitric Acid, Sulphuric Acid etc. during the period from 1983-1986. However, the Government issued a closure notice in 2002. The total number of employees rendered jobless were 1314.

This factory has huge potential. The concerned Ministry should take up the matter very seriously. The whole HFCL including Haldia Division was referred to BIFR in 1992.

I would request the Hon'ble Minister to look into the matter on priority basis so that this valuable industry can start its operation immediately.

(xiv) Need to include differently abled persons in the ambit of Right to Education Act

SHRI D. VENUGOPAL (TIRUVANNAMALAI): As decided in the UN Convention in 2007, the Government of Tamil Nadu has announced that the physically disabled persons must henceforth be called as 'differently abled' persons. As a compassionate gesture, the Government of Tamil Nadu has set apart in this year's Budget Rs. 176 crore for the welfare of the differently abled persons which is a marked increased from Rs. 49 crore allocated in the previous years while setting up a separate department. Even those affected by the elephantiasis have been recognized as differently abled persons as they have lost the use of their limbs and a monthly assistance of Rs. 400 will be given to those people. About 60,000 visually impaired, 50,000 physically challenged and 10,000 people affected by muscular dystrophy will be getting an enhanced monthly assistance. Tamil Nadu Government has announced tuition fee waiver for Differently Abled Youth to pursue higher education and has increased the monthly assistance from Rs. 200 to Rs 450 for stay in both Public and NGO run hostels. As there is no mental health hospital in other parts of Tamil Nadu, except in Chennai, the Government of Tamil Nadu has decided to establish an Institute of Mental Health in Theni District. Apart from that, the State Government has decided to apportion Rs. one crore every year to set up 10 Mental Health Rehabilitation Centres, each of them covering three districts. Tamil Nadu, as such, remains a pioneering model state in this regard by way of carrying out this massive scheme for the differently abled persons.

I, therefore, urge upon the Ministry of Health and Family Welfare to include differently abled persons also in the ambit of Right to Education Act as it requires additional central funds for meeting the needs of special children and centre may extend more financial assistance to the Government of Tamil Nadu for all these measures.

(xv) Re: Need to expedite the implementation of welfare programmes for minorities including the proposals of the Ranganath Mishra Commission

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): The implementation of the Minority Development Programmes are presently not moving with the desired pace due to inadequacy of funds, lack of monitoring setup, and non accountability of the channelizing agencies. In this connection, Sachar Committee had also identified the issues which need to be addressed. Also, Ranganath Mishra Commission has specifically suggested the programme of action to be taken for the implementation in the light of Sachar Committee report. The Government has tabled it in the House without even an action taken report, that too, after two years. It is still uncertain as to what further action the Government is going to take in this regard. I urge upon the Government to take early action on the implementation of Minority welfare programmes including the proposals put forward by the Ranganath Mishra Commission.

(xvi) Need to mitigate the problems of villagers residing along border in Balurghat Parliamentary Constituency, West Bengal

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): My constituency Balurghat in West Bengal is almost surrounded by Indo-Bangladesh border. Due to international law, the Central Government has built up Border fencing 150 yards away from Zero Point. Even now some Border villages are situated between Zero Point and Border fencing line. The students, labourers, cultivators, employees and also relatives of that villages cannot enter their own villages in the evening because Section 144 of IPC is promulgated along the border area. Similarly, the people of the border villages cannot come from their villages from evening to morning even they cannot go to hospital. More over border villagers cannot avail Government facility such as rural electricity, drinking water and health facilities. Border gates are not timely opened. Peasants face difficulties in cultivating their lands.

I would request the Hon'ble Home Minister to ensure that there are sufficient gates at the border area, gates are opened in time, border villages are allowed to avail Government facilities and villagers may be allowed to take photo copy of identity cards across the border gate so that the original identity card is not damaged due to daily wear and tear besides allowing the cultivators to produce jute.

(xvii) Need to amend Securitisation Act, 2002 providing for relief and exemption to the Rubber Plantation sector from attachment of collateral in the event of non-payment of farm loan

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): I have come across a recent report of the Reserve Bank of India taking exception to non-provisioning of bad debts extended to agriculture sector thereby flouting the regulations of the Central Bank. This should act as a wake-up call for all lending institutions serving the farmer community who have under the garb of the provisions of the Securitization Act, is denying the process of natural justice to the borrowers from the farming community. The Securitization Act, 2002 vests powers with banking institutions lending to the agricultural sector to liquidate bad debts through the process of attachment of collateral by merely serving a notice. However, the above said provision does not apply to loans extended to the farming sector. Despite such immunity granted to the farming sector from the process of attachment of collateral under the Act, many banks lending to the agricultural sector are blatantly resorting to the provisions of the Act equating agricultural loans with commercial loans. Most of the victims of this discriminatory practice by banks belong to the Rubber plantation sector which has not been expressly identified as a beneficiary at par with the general farming community as mentioned in the Act. It is, therefore, necessary to provide the same measure of relief and exemption to the Rubber plantation sector also by amending the relevant provisions of the Act.

14.06 hrs.

DEMAND FOR GRANT(GENERAL)- 2010-11

Ministry of External Affairs

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will move to item no. 18. The House will now take up discussion and voting on Demand No. 31 relating to the Ministry of External Affairs.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demand for Grant have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within fifteen minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand No. 31 relating to the Ministry of External Affairs."

Dr. Murli Manohar Joshi to speak now.

MR. DEPUTY SPEAKER : Dr. Murli Manohar Joshi to speak now.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विदेश मंत्रालय की अनुदान संबंधी डिमांड्स के बारे में चर्चा करने का अवसर दिया। मुझे अनुदान के बारे में, उनके आंकड़ों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने जहां उनको देखा है, उनमें बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जैसे कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई एक करोड़। बड़े से बड़े काम जो आईसीसीआर को करने हैं, उनमें भी 10-12 करोड़। विश्वभर में आपने सेमिनार आदि किए हैं, उनके लिए भी 2 करोड़, 4 करोड़। यह इस बात का सबूत है कि विदेश मंत्रालय का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। कल्चर्ड अफेयर्स से बहुत कुछ हो सकता है। वर्ल्ड अफेयर्स जो हमारी संस्था है, उसके माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। आज कल्चरल डिप्लोमेसी बहुत बड़ा स्थान रखती है। सांस्कृतिक कूटनीति का अपना महत्व है। इसी प्रकार आजकल टेक्नोलॉजी की कूटनीति का बहुत महत्व है। मैंने देखा है कि उसका कहीं उसमें उल्लेख नहीं है। शिक्षा भी आजकल विदेश नीति का एक अंग बनी हुई है। अर्थव्यवस्था तो बनी ही हुई है। डब्ल्यूटीओ और सारे मामले आज विदेश नीति के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि विदेश मंत्रालय की इनमें किसी प्रकार की भूमिका नहीं है। यह चिंतनीय बातें हैं विदेश मंत्रालय को अपनी नई भूमिका, नए परिवेश में इसके बारे में विचार करना चाहिए। स्पोर्ट्स में भी एक अलग प्रकार की कूटनीति है। चीन ने इसके बारे में बहुत कुछ किया है। सारी दुनिया के विश्वविद्यालयों को बुलाकार उन्होंने अपने यहां कई बार ऐसे फंक्शन्स किए हैं। आज जीवन के हरेक क्षेत्र के साथ विदेश नीति के संबंध जुड़ गए हैं। टेक्नोलॉजी है, शिक्षा है, संस्कृति है, खेल-कूद आदि सब जुड़ गए हैं। इसके अलावा वैचारिक स्तर पर जो आदान-प्रदान है, आज उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दुनिया के बहुत से देश इस प्रकार की संस्थाएं बनाए हुए हैं। लेकिन मुझे इसे देखकर अच्छा नहीं लगता कि हमारी विदेश नीति और विदेश मंत्रालय वही 50-60 साल पुराने ढर्रे पर चल रहा है। मेरा आपसे पहला अनुरोध यह होगा कि इस बारे में आप अपने सारे कार्यकलाप का पुनरीक्षण करें और इसे देखें और जिन-जिन मंत्रालयों के साथ आपका संबंध होना चाहिए, उस संबंध को गहन करें। डिफैंस के साथ आपका संबंध बहुत गहन होना चाहिए, क्योंकि विदेश नीति और डिफैंस जुड़े हुए हैं। आप जो कह आते हैं कि अमुक देश हमारा मित्र है तो यहां का डिफैंस उसके बारे में वैसे ही सोचने लगता है। श्री प्रणब मुखर्जी जिस समय विदेश मंत्री थे, वे कह रहे थे कि China is a new security challenge to India. मुझे पता नहीं कि उन्होंने डिफैंस वालों से, प्रतिरक्षा मंत्रालय वालों से बातचीत की या नहीं, क्योंकि यह हमें वहां नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने यह सन् 2008 में कहा था और अब सन् 2010 के चार महीने हो गए हैं।

लेकिन डिफेंस की जो तैयारी है, वह हमें इसके अनुरूप दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ यह है कि विदेश नीति और डिफेंस मंत्रालय में कोई तालमेल नहीं है, कोई लिंक नहीं है, दोनों का विजन एक नहीं है। यह बड़ी चिन्ता की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की विदेश नीति, प्रतिरक्षा नीति, अर्थ नीति और विज्ञान नीति के बीच में कोई तालमेल नहीं है। इसलिए विदेश नीति के बारे में मुझे यह कहने में अफसोस है कि वह बड़ी धुंधली है, हेज़ी है, स्पष्ट नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसकी कोई दिशा नहीं है। यह चिन्ता की बात है।

हमारे वित्त मंत्री महोदय, अक्सर कौटिल्य का उदाहरण देते हैं। कौटिल्य ने इस बारे में जो कुछ कहा है, अगर उसे पढ़ लिया जाये, तो बहुत कुछ बातें साफ हो जायेंगी। कौटिल्य ने कहा है कि विदेश नीति का उद्देश्य क्या है? वह कहता है कि विदेश नीति उद्देश्यहीन नहीं होती। यह एक स्पष्ट दृष्टि के साथ होती है, उद्देश्य के साथ होती है। उसका एक उद्देश्य राज्य का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना है। राज्य का आस-पास के देशों में ही नहीं, बल्कि दूर तक उसका प्रभाव पड़े, लोग उसके बारे मे अच्छी बातें सोचें, उसको शक्तिशाली मानें और राज्य शक्ति का संचय करे, इसके लिए उसने कहा है कि राज्य का सैन्य बल और अर्थ बल जरूरी है। इसलिए उसने कहा है कि विदेश नीति, अर्थ नीति, प्रतिरक्षा नीति आपस में जुड़ी होनी चाहिए और एक दिशा में बढ़नी चाहिए। उसने यह भी कहा है कि विदेश नीति का एक उद्देश्य यह भी है कि दुनिया भर में जहां-जहां साधन है, उन साधनों को अपने राज्य में लाने का प्रयत्न होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह उद्देश्य हमारी विदेश नीति से दिखाई देता है। फिर उसने यह भी कहा है कि विदेश नीति का एक उद्देश्य शत्रु और मित्र की पहचान करना है, मित्रों का संचय करना है और शत्रुओं को पराभूत करना है। वे हमारे ऊपर हावी न हो सकें, ऐसी व्यवस्था करनी है। इसलिए विदेश नीति का एक जो व्यापक उद्देश्य है, उसे ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ये ढाई हजार साल पहले उसने कहा था। आज की परिस्थिति में इसे हम री-इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसके अनुसार हम विदेश नीति का एक स्पष्ट उद्देश्य बनायें। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि भारत एक इमर्जेंट ग्लोबल पावर है। उसका एक तर्क यह दिया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के नम्बर दो स्थान की तरफ बढ़ रही है। कभी कहा जाता है कि शायद हम नम्बर एक पर अर्थव्यवस्था की विकास दर में हो जायें।

महोदय, मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि केवल अर्थव्यवस्था से आप इमर्जेंट ग्लोबल पावर नहीं बन सकते। आखिर जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ हैं और दुनिया की दूसरे-तीसरे नम्बर की अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इमर्जेंट ग्लोबल पावर नहीं बना, क्योंकि इनकी जो आर्थिक शक्ति है, यह सामरिक शक्ति में परिणित नहीं हुई। इसलिए जब तक आपकी इकोनॉमिक पावर,

आपकी मिलिट्री पावर में परिवर्तित नहीं होती, उन दोनों के बीच में समन्वय नहीं होता, आप वर्ल्ड पावर नहीं बन सकते। अगर आपका ख्याल यह है कि अमेरिका के कंधे पर बैठकर आप वर्ल्ड पावर बन जायेंगे, तो माफ कीजिए, कोई किसी के कंधे पर बैठकर वर्ल्ड पावर नहीं बन सकता। वह तो आपको अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से बनना पड़ेगा। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इमर्जेंट ग्लोबल पावर कहने का अर्थ केवल यह है कि हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो जायेंगे या हमारी विकास की दर, ग्रोथ की दर बढ़ जायेगी, उससे हम कोई इमर्जेंट ग्लोबल पावर हो जायेंगे, ऐसा नहीं है। चीन इसलिए ग्लोबल पावर बना, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक पावर, उसकी मिलिट्री पावर में प्रदर्शित हो गयी। Until and unless the economic power is translated into the military power, you cannot become a global power. अमेरिका की अर्थव्यवस्था घट रही है, लेकिन वह बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास एक दृढ सामरिक शक्ति है। वह दूसरे देशों को कवर दे देता है, इसलिए देश उसके साथ हैं। आप कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए आपकी विदेश नीति और सामरिक नीति, इन दोनों के बीच में गहन संबंध होना चाहिए।

यहां प्रणब मुखर्जी जी बैठे हैं। उन्होंने सन् 2008 में इस बारे में कहा था कि --

> "On the day the Chinese Naval Chief arrived in New Delhi on his maiden visit to India, the External Affairs Minister Pranab Mukherjee said that China's rise was India's new security challenge."

उस समय आप विदेश मंत्री थे। मैं समझता हूं कि यह बात इनकी फाइलों में कहीं न कहीं होगी। आप उसे देख लीजिए। फिर आप देखें कि इस इमर्जिंग चैलेंज का हम किस तरह से सामना कर सकते हैं।

आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि चीन हमारे लिए क्या-क्या कठिनाइयां पैदा कर सकता है। चीन हमारा निकट पड़ोसी है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका हमारे निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं। इनके साथ हमारे क्या संबंध हैं और चीन वहां क्या कर रहा है? क्या हमने इन देशों को मित्र बनाया है? क्या इनमें हमारा प्रभाव बढ़ा है या चीन का प्रभाव बढ़ रहा है? मेरे पास पिछले साल की एक रिपोर्ट है जो रॉ की तरफ से दी गयी है। इसमें कहा गया है:

> "China out to clip India's wings; makes massive investments in neighbouring countries to spike nation's regional aspirations."

यानि ग्लोबल तो दूर की बात है, हम रीजनल पावर भी न बन पाएं इसके लिए चीन पूरे प्रयत्न कर रहा है। आप देखें कि हमने क्या गलती की है। आज चीन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान को

चीन ने हथियार और पैसे दिए हैं और साथ ही साथ उसके मार्फत ग्वाडर में एक बंदरगाह बनाना चाहता है, अरब सागर में पहुंचना चाहता है। इसी तरह से म्यांमार और बांग्लादेश के साथ उसके संबंध बढ़ रहे हैं। चिटगंग पोर्ट को वह विकसित करना चाहता है। हम क्या कर रहे हैं? श्रीलंका एक पोर्ट बनाना चाहता था, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की। वहां आज चीन घुस गया है। श्रीलंका अपने हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में चाहते थे कि हम लोग उसको विकसित करने में उनकी मदद करें, एक मल्टीलैट्रल और मल्टीपरपज पोर्ट के तौर पर उसे विकसित करने में हम मदद करें, लेकिन हमने मना कर दिया। अब चीन वहां आएगा, जब चीन उसकी मदद कर रहा है, तो चीन के जहाज वहां आएंगे। वे आपको दक्षिण से घेर लेंगे। माले ने इसी तरह का एक समझौता चीन के साथ कर लिया है। हैनीमाधो उनका एक बेस है, वहां चीन को बेस बनाने की इजाजत मिल गयी। चीन के लोग वहां आएंगे और एक बेस बनाएंगे। आप घिर रहे हैं। चिटगंग पोर्ट से चीन उधर जाना चाहता है, ग्वाडर से अरब सागर में जाना चाहता है, नेपाल में अलग से घुसना चाहता है। नेपाल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन घुस रहा है, बहुत लो बिड़िग कर रहा है और नतीजा यह है कि आपको उसने एक तरह से घेर लिया है।

आपके अंदर वह और गड़बड़ियां भी फैला रहा है। उनका एक लेख था, जो मैंने पिछली बार भी पढ़कर सुनाया था, इसमें उसने कहा है कि भारत का 25-30 टुकड़ों में बांट दो। यह एक बड़ी खतरनाक बात है। अगर वह यह बात कह रहा है, उसका लेख छप रहा है, उसकी तरफ से बराबर यह बात कही जा रही है कि इंडिया को तोड़ दो और उस लेख को लिखने वाले व्यक्ति को चीन सरकार का समर्थन प्राप्त है। वह पहले से भी ऐसा कहता आ रहा है, इसके लिए कोशिश भी कर रहा है। हमारे यहां के उपद्रवी लोगों को, आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, नक्सलवादियों को हथियार आदि की मदद चीन से आने की खबरें आती रहती हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहां नकली दवाइयां चीन की तरफ से भेजी जाने की खबरें आती रहती हैं, यानि हमारी अर्थव्यवस्था को हर तरह से नष्ट करने की कोशिश चीन कर रहा है, राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश करता है। हम क्या कर रहे हैं? इसको काउण्टर करने के लिए हमने क्या सोचा है?

मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने यह बात कही थी, एक समय था जब हम या तो पाकिस्तान से लड़ते थे, उस समय चीन चुप रहता था, अमेरिका और रूस चुप रहते थे। फिर जब कभी चीन से लड़ते थे, तो पाकिस्तान चुप रहता था, लेकिन आज ये दोनों मिल गए हैं और पिछली बात भूल जाइए, जब वर्ष 1962 में अमेरिका आपकी पुश्त पर खड़ा था। अब ऐसा नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकता है और चीन को भी नहीं छोड़ सकता है। भगवान न करे अगर कोई ऐसी स्थिति आ गयी तो फिर इनमें से कोई भी आपकी मदद करने नहीं आएगा। अमेरिका आपकी मदद

करने नहीं आएगा। उसकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर रखे। उसे अफगानिस्तान से निकलना है। इसके लिए वहां एक नई थ्योरी आ गयी है - गुड तालिबान और बैड तालिबान। वह कहता है कि गुड तालिबान के हाथ मे अफगानिस्तान को छोड़ दो, बैड तालिबान को हिन्दुस्तान की तरफ जाने के लिए पाकिस्तान को छुट्टी दे दो। अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक और सामरिक मदद कर रहा है। आज परंपरागत लड़ाई के मामले में पाकिस्तान आपसे पीछे नहीं है, आपसे आगे है।

उसके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, वह कहां ले जाएगा, क्या चीन से लड़ेगा या ईरान से लड़ेगा, वह इन सबका प्रयोग भारत के खिलाफ करेगा। मैंने अभी देखा कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप बिल्कुल भरोसा रखिए, वे हथियार हिन्दुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यह तो उन्होंने मौखिक कहा है। जनरल आइसान हॉवर ने तो लिखित बयान दिया था जब वह पाकिस्तान को हथियारबंद कर रहे थे, तब हम लोगों ने यह आपत्ति उठाई थी, इस देश के लोगों ने, तब उन्होंने यही कहा था कि हम गारंटी देते हैं, लिखित देते हैं, लेकिन क्या हुआ उसका, आप देखें कि हमारे खिलाफ उन हथियारों का उपयोग हुआ। इसलिए आप अमेरिका की इस गारंटी के भरोसे मत बैठिए, पाकिस्तान की नीयत को देखिए। पाकिस्तान के आज तक के इतिहास को देखिए। इसलिए आप इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिए कि जो अमेरिका ने आज नीति बदल दी है पाकिस्तान के साथ फिर से ज्यादा निकट सम्बन्ध रखने की और हिन्दुस्तान को थोड़ा सा अलग रखने की, वह हमारे लिए गम्भीर चिंता का विषय है।

आप स्ट्रेटेजिक सम्बन्ध बनाए हुए हैं अमेरिका से, बार-बार उसकी दुहाई देते हैं। उसका परिणाम हमें क्या मिला, आप देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है। वे कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ शेयर्ड इंटरेस्ट है। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई। ओबामा साहब ने कहा कि हां हमारी जो यह नीति है इसमें हम पाकिस्तान के साथ शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ जाएंगे। What are those shared interests? यह गुड तालिबान-बैड तालिबान उनके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं या हिन्दुस्तान में पाकिस्तान जो आतंकवादी कार्रवाइयां कर रहा है, वह शेयर्ड इंटरेस्ट है। पिछले दिनों ओबामा साहब ने कहा, जब उनसे पाकिस्तान के जनरल कियानी मिले, तो उन्होंने कहा, I love Pakistan. As a college student I had visited Pakistan and we had shared values. What are those values? क्या पाकिस्तान की वेल्यूज और अमेरिका की वेल्यूज समान हैं? हमसे भी आकर कहते हैं कि आपके साथ हैं शेयर्ड वेल्यूज, यह सब क्या हो रहा है, हम इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे कि दुनिया में जो विदेश नीति का चक्र है, वह किधर घूम रहा है। क्या वह हमारे देश के हित में घूम रहा है?

आपने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान के बारे में अपनी नीति बदल दी। आज आपको वहां से गैस नहीं मिल रही है। ईरान के लिए आपकी क्या नीति है? मध्य एशिया के लिए आपकी क्या नीति है? ये तमाम ऐसे देश हैं जो प्राकृतिक साधनों से भरे हुए हैं। वे आपकी तरफ से मित्रता का भाव देखना चाहते हैं, लेकिन आप मित्रता नहीं करते। आपका उनसे कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं होता।

मंगोलिया ने आपके साथ सम्बन्ध स्थापित किया था। मंगोलिया सांस्कृतिक दृष्टि से भी आपके काफी निकट है। मंगोलिया जब रूसी तंत्र से आजाद हुआ तो उसने अपने संविधान में लिखा कि हम नागार्जुन, बुद्धिज्म के आधार पर अपना शासन चलाएंगे। नागार्जुन और बुद्धिज्म भारत की देन हैं। इतना निकट का सम्बन्ध उनके साथ हमारा है। वे गंगाजल अपने सिर पर रखकर ले जाते थे। लेकिन आज क्या स्थिति है? भारत सरकार ने वाजपेयी जी के जमाने में उनको एक सेंटर दिया। एक सेंटर पहले से था। एक सेंटर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर और दूसरे सेंटर का नाम राजीव गांधी सेंटर है। आपकी सरकार ने राजीव गांधी सेंटर की एड चालू रखी और अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर की एड बंद कर दी। क्या बात थी, क्या ऐसे विदेश नीति चलेगी? वहां के सांसद यहां आए थे, उन्होंने कि साहब यह क्या हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी विदेश नीति के संचालन का उद्देश्य क्या है? क्या आप मंगोलिया को दूर करना चाहते हैं, क्या आप उसे चीन के प्रभाव में ऐसे ले जाना चाहते हैं कि वह इस तरफ कभी आंख उठाकर भी न देखे? यह सोचने की बात है कि विदेश नीति का मतलब क्या है। हमारे कितने मित्र देश हैं। जो बने हुए हैं, वे हमसे दूर क्यों जा रहे हैं।

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI S.M. KRISHNA): The hon. Member is making a reference to Rajiv Gandhi and Atal Bihari Vajpayee. I did not get the full import of that.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : There were two academic educational centres given by the Government of India in Mongolia. One was named as Rajiv Gandhi Centre and the other as Atal Bihari Vajpayee Centre. I did not stop the grant of Rajiv Gandhi Centre, as a Minister I was dealing with it. But now, their Members of Parliament came here and told me that there is grant only to one institute and for the other there is no grant. Please examine it.

If it is so, correct it. आप इस बारे में बताएं। हमें उनकी तरफ से यह सूचना मिली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि विदेश नीति में कहां सुधार की जरूरत है। सैंट्रल एशिया के जो तमाम देश हैं, उनसे हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। लेकिन आज आपका

उनसे निकट का संबंध नहीं है। इसकी क्या वजह है? वे हमारे लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा खजाना हैं। वे हमसे मित्रता चाहते हैं। वे भारत के पुराने इतिहास को जानते हैं। वे जानते हैं कि भारत का सैनिक या राजनीतिक दबदबा बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रहा है। वे मित्रता चाहते हैं। वे डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि चीन उनके सामने मुंह खोले खड़ा है। उनको संकट लग रहा है और वे आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें साथ नहीं लेना चाहते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप मित्रों का संचय कीजिए। मुझे चीन के बारे में ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि सदन को मालूम है कि वह कराकोरम तक जा रहा है, वह आपकी सिंधु नदी को बदलना चाहता है। वह ब्रह्मपुत्र को बदलना चाहता है। सवाल यह है कि आप उस तरफ क्या कर रहे हैं। आप चीन को भाई-भाई बोल रहे हैं। आप बहुत पहले से भाई-भाई बोल रहे हैं। उसने आपके साथ क्या किया था और आज आप फिर भाई-भाई बोल रहे हैं। आप भाई-भाई बनाइए, लेकिन keep the powder dry. विदेशी नीति में हमेशा आपकी तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि यदि कोई भाई पीठ पीछे से कुछ मारना चाहे, तो आप उसे रोक सकें।

दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ ऐसे देश हैं, जो चीन से घबराए हुए हैं। वे आपका साथ चाहते हैं। आपके पास यदि कुछ है भी, तो भी आप उसे देना नहीं चाहते हैं। वियतनाम और मलेशिया साथ आ गए हैं। थाईलैंड भी उसमें साथ आ सकता है। कम्पूचिया भी आपके साथ आ सकता है। आपकी संस्कृति सौहार्द की रही है। यह भारत के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले देश रहे हैं और आज भी आपके लिए बहुत अच्छी दृष्टि रखते हैं, लेकिन आप वियतनाम को भी अपने साथ नहीं रख रहे हैं। वह आपसे मिसाइल चाहता था, आपने उसे नहीं दीं। वह ब्रह्मोस चाहता था, वह आपने नहीं दिया। वियतनाम कभी चीन से नहीं डरा है। वह अमरीका से भी नहीं डरा था। वह आपका अच्छा मित्र है और आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। कुछ मिसाइल्स देने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप चीन से डर रहे हैं या अमरीका से डर रहे हैं। डर-डर कर विदेश नीति नहीं चलती है। जब आप डरते हैं, तभी गड़बड़ होती है।

जब आप सामरिक शक्ति बनाते हैं, तभी आप शक्तिशाली बन सकते हैं और दुनिया आपके साथ आएगी। 1974 में देश ने परमाणु बम का विस्फोट किया। देश के बारे में दुनिया के अंदर एक धारणा बनी। उस समय हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे होंगे, लेकिन देश के अंदर आत्मविश्वास आया था और वैज्ञानिकों ने उसके बाद बहुत कुछ किया। 1998 में इस देश ने फिर एक प्रभा मंडल बनाया। दुनिया के तमाम देश आपके साथ आ रहे थे। आपकी शक्ति को वे आंक रहे थे कि भारत कितना आगे जा सकता है। परमाणु बम के विस्फोट ने देश की सामरिक शक्ति को एक नया आयाम दिया। वर्ष 2004 में हमने फिर से उसका

प्रदर्शन किया और नतीजा यह हुआ कि भारत की एक छवि बनी। भारत के बारे में लोगों की धारणाएं बनीं कि भारत के लोगों ने हिम्मत है। भारत डरता नहीं है। अमरीका के मना करने के बावजूद भी भारत ने परमाणु का विस्फोट किया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister wants to say something.

SHRI S.M. KRISHNA : Only if you yield, I can speak.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : Yes, I yield.

SHRI S.M. KRISHNA: The hon. Member did refer to two Centres of Information Technology founded by Government of India grants. One is the Rajiv Gandhi Centre on Vocational Training and the other centre is Atal Bihari Vajpayee Centre of Information Technology.

I am happy to convey to the hon. Member and to this august House that both these Centres are working extremely well. It is not true that they are not working any more. They are working to our satisfaction. … (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : How much is the grant that has been given? They are working!. … (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA: For Atal Bihari Vajpayee Centre, one million has already been given. … (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : What about the other Centre? … (*Interruptions*) What is the grant given to the other Centre? … (*Interruptions*)

SHRI S.M. KRISHNA: Simply because I am not able to provide you the information … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

SHRI S.M. KRISHNA: I will provide all these details in the course of my reply. … (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : If the grants are restored, it is fine. If they are not restored, please restore them. If they need to be upgraded, please upgrade them. These are the things. मैं आपको बता रहा था कि चारों तरफ का परिवेश हमारे साथ तभी रहेगा जब आप शक्तिशाली होंगे। जब आपकी सामरिक तैयारियां होंगी। अगर ये तैयारियां नहीं होंगी, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो दुनिया का कोई देश आपकी बात नहीं सुनेगा। आपका कोई मित्र बनने के लिए तैयार नहीं होगा। जब आप कोशिश करते हैं, शक्ति दिखाते हैं आत्मविश्वास दिखाते हैं लोग आपके साथ आते हैं। जब आप नहीं दिखाते, जब आपकी छवि बन जाती है कि आप किसी दूसरे देश के दबाव में काम कर रहे हैं कोई आपके पास नहीं आता है। मेरा यह बिंदु था कि भारत को विदेश नीति का संचालन करने के लिए अपनी सामरिक, परमाणु और आर्थिक क्षमता का विकास इस तरह से करना चाहिए कि आर्थिक क्षमता सामरिक क्षमता में परिवर्तित हो जाए, ट्रांसलेट हो जाए। मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि भारत को चीन का उद्देश्य समझकर नीतियां तय करनी होंगी। चीन आज अमेरिका से बात कर रहा है कि आप ईस्ट पेसिफिक ले लीजिए, वेस्ट पेसिफिक मुझे दे दीजिए और इसके साथ इंडियन ओशन दे दीजिए। अगर अमेरिका और चीन में समझौते हो जाते हैं तो सारा क्षेत्र चीन के कब्जे में आ जाता है। आज तक नौसेना और नेवल मूवमेंट की दृष्टि से यह चीन के एकाधिकार में नहीं था और अगर दोनों महाशक्तियों ने यह समझौता कर लिया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमने तो छोटे द्वीपों को भी, जैसे संशाइल्स जो हमसे बात करना चाहते थे, वहां भी सरकार के बेसिस पर कुछ नहीं किया। उनके साथ भी हम ठीक संबंध नहीं रख पाए। मेरा कहने का मतलब है और इस मामले में फिर वही बात आती है कि नेवी ने अपनी तरफ से जो कुछ देना था, अपने बजट से या और सरकार ने डिफेंस मंत्रालय के लिए इस काम के लिए अलग से बजट नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि विदेश मंत्रालय को इन बातों का पता है या नहीं कि हमारे समुद्री क्षेत्र में चीन क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है। हम इतनी बुरी तरह से घिरे हुए हैं, हम उसका प्रतिकार कैसे करें?

एक तरफ हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। कौटिल्य ने कहा था कि आपके प्रभा मंडल का विस्तार होना चाहिए जबकि आपका प्रभा मंडल और आपकी भूमि दोनों सिकुड़ रही हैं। आपने तिब्बत चीन को दे दिया। चीन आज उसके कारण से अरुणाचल पर अपना अधिकार चाहता है। वह कहता है कि यह तिब्बत का हिस्सा था और तवांग में दलाई लामा पैदा हुए थे इसलिए यह तिब्बत को मिलना चाहिए। आप क्यों नहीं उनके सामने कहते कि अरुणाचल तो मिलेगा ही नहीं और तिब्बत के बारे में होश की दवा कीजिए, हम उसका सवाल उठा सकते हैं। आप सवाल क्यों नहीं उठा सकते? अगर आज जरूरत है तो हम उठाएं और

चीन को उसी तरह से जवाब दें। लेकिन हम चीन के सामने डरे हुए हैं। हम क्यों डरते हैं? आपको हिम्मत के साथ कहना चाहिए कि यह तो होगा ही नहीं। लेकिन तिब्बत का मसला दोबारा उठाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ताकतें आपकी मदद करेंगी अगर आप ये मसले उठाएंगे। देश आपकी मदद करेगा अगर आप ये मसले उठाएंगे। आपकी एक समय सीमा हिमालय के उत्तर में थी और आज सीमा हिमालय के दक्षिण में आ रही है। वह अरुणाचल पर अपना दावा जमा रहा है। नेपाल में उसने प्रभाव क्षेत्र बना लिया है।

आपकी सीमाएं जो हिमालय के उत्तर में थीं, आज हिमालय के दक्षिण में मैदान में आ गई हैं। यह राज्य का प्रभाव नहीं बढ़ रहा है। यूरोपीय देशों से आपके कितने और क्या संबंध हैं, आप वहां जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वह एक अलग बात है। लेकिन उनसे आपको ज्यादा मदद मिलने वाली नहीं है। परंतु जो आपके निकटवर्ती देश हैं, आप उनके बारे में सोचिये। मध्य एशिया के बारे में आपकी क्या नीति है? वहां से भी आपके बहुत सारे संबंध हैं। मुझे पता नहीं कि क्रूड आयल आने की जो नीति है, जो वहां से आ रहा है, उसके बारे में विदेश मंत्रालय में कोई चर्चा होती है या नहीं होती है या खाली वह वाणिज्य और पैट्रोलियम मिनिस्टर के बीच में रह जाती है। संसाधन जहां-जहां से भी आते हैं, उन सबके साथ विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जुड़ा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि विदेश मंत्रालय के संचालन के लिए इसका पुनर्गठन नये सिरे से कीजिए। आज छवि यह बन गई है कि आप अमरीका के आश्रित बन गये हैं, पिछलग्गू बन गये हैं। यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अमरीका से दोस्ती रखिये। दुनिया के हर देश से दोस्ती रखना हमारे लिए अनुचित नहीं है, उचित है। हम हर एक को मित्र बनाना चाहते हैं। हमारा पुराना स्वभाव यही रहा है। लेकिन अमरीका का पिछलग्गू बन जाना उचित नहीं है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें हमने अमरीकी दबाव के सामने समर्पण किया है। आखिर हमने हवाना में क्यों कहा कि पाकिस्तान भी उसी तरह से आतंकवाद का शिकार है, जैसे भारत है, यह किसके दबाव में कहा? हमने शर्म-अल-शेख में बलूचिस्तान का मामला क्यों जोड़ा, किसके दबाव में जोड़ा? इस तरह से वर्ष 2004 में सरकार ने जो एक स्थिति पैदा की थी, उसे आपने पलट दिया। आप पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गये। आप बार-बार यहां कहते रहे कि तब तक बात नहीं करेंगे, जब तक 26/11 का हिसाब नहीं मिल जायेगा, जब तक 26/11 के अपराधी लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। फिर आप बात करने के लिए क्यों तैयार हो गये? जब देश में और यहां उस पर आपत्ति हुई तो थोड़ा-थोड़ा हिलने-डुलने लगे कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, सैक्रेटेरिएट के लैवल पर करेंगे, उसके लैवल पर करेंगे। आप ऐसे क्यों बदलते हैं? एक बार यहां सदन में यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया हुआ है कि एक-एक इंच कश्मीर की भूमि हमारी है तो आप अब उसे छोड़ने के लिए क्यों तैयार होते हैं? आप नये-नये फार्मूले निकालने के लिए क्यों तैयार होते हैं?

यह देश इसलिए बहुत चिंतित है कि आपकी विदेश नीति का संचालन देश के हित में है या अमरीका के हित में हैं। Are we working for the interests of the United States or are we working for the interest of India?

इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने रूस की तरफ क्यों नहीं देखा, उसके साथ आजकल आपके कैसे संबंध हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे एक बड़े प्रतिष्ठित विश्लेषण करने वाले ने यह लिखा है -

> "Elsewhere in the near-abroad, Russia has been neglected as a potential counterweight both to the US and China. In fact, the PM's putting all of India's eggs in the US basket means that he hopes that the US will play the protector role that the USSR performed in an earlier era. Manmohan Singh-ji is reportedly pressuring the Indian Air Force to buy American F-16 or F-18 aircraft for its 126-plane strong medium range multi-role combat fleet. Besides enhancing the IAF's operational problems because of the diversity of aircraft and logistics support in its inventory, it is guaranteed to further estrange Russia. This is extreme foolishness because Washington gives every indication of reconciling its differences with China to create a condominium to manage world affairs. Whence the concept of G-2,that is, America and China, two Superpowers, to supplant every other combination. Indeed, Moscow is being played as a second fiddle when Russia's utility in containing Chinese expansionism is obvious. And in Central Asia, the initial advantage India has because of its venerated cultural and other links, have been frittered away. In any case, the Government has nothing to show by way of any success in this region."

अभी मुझे पता नहीं प्रधान मंत्री जी विदेश से दौरा करके आये हैं, वहां क्या उपलब्धि हुई। वहां हमने क्या चीजें बताई हैं, हमसे क्या कहा गया है? अफगानिस्तान में हमारा कोई रोल रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हमें वहां से हटना पड़ेगा? ये सारी बातें हैं, जो हम जानना चाहेंगे।

अफगानिस्तान में भारत की भूमिका क्या होने वाली है, वह हमें वहां से हटा दें और हम यह कहें कि हां, बिल्कुल ठीक है, इन्हें तालिबान के हाथ में छोड़ दीजिए, क्या भूमिका होगी? हम वहां रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम नहीं जानते कि प्रधानमंत्री जी वहां क्या कह कर आए हैं। हम समझते थे कि वे संसद को इसके बारे में अवगत कराएंगे कि वहां उन्होंने क्या कहा है। तेहरान के बारे में आपकी नीति क्या रही, कोई नहीं चाहता कि उसके पास परमाणु बम बने, लेकिन कोई यह भी नहीं चाहता कि तेहरान को आप इस तरह से दबा दें

कि वह किसी काम का न रहे। आपको उनसे गैस भी नहीं मिल रही, आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप अपने देश के हितों को कितना पहचान लेंगे या केवल अमेरिका के इशारे पर अपनी नीतियां चलाएंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है? मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम अमेरिका से दुश्मनी कर लें और न मेरा अर्थ यह है कि हम रूस की गोद में जा बैठें, हम जबरदस्ती चीन से भीड़ जाएं। मेरा निवेदन आपसे यह है कि चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों को देखते हुए हमारी विदेश नीति की दिशा क्या होनी चाहिए, मित्र संचय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रूस से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अमेरिका से दोस्ती के आयाम क्या होने चाहिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका या रूस, मैं यह नहीं कह रहा हूं। हमारे हित जहां तक हैं, जहां तक हमारे अपने हित हैं, उसके हिसाब से हमें ये सारा संचालन करना चाहिए। यह जो न्यूक्लियर लायबिल्टी बिल है, इसके बारे में मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरे सामने वह बयान है, जो अमेरिका के एक आफिसर ने दिया था, वह बड़ा विचित्र बयान है। वे यह कहते हैं कि हमारी बात हो गई है और हिन्दुस्तान की सरकार बहुत जल्दी ही एक कानून पास करने वाली है, जिससे अमेरिकन कम्पनीस को सुरक्षा मिलेगी, कैपकम होगा और वे वहां जाकर इनवेस्ट कर सकेंगे, यह उनका बयान है। अभी पिछले दिनों मार्च के महीने में बयान दिया था। उसके बाद हम यहां संसद में वह बिल पेश करें, तो उसमें बिल्कुल यही धारणा निकलती है कि यह बिल अमेरिकन कम्पनी की सहायता के लिए है। ऐसा क्यों हो रहा है, इन घटनाओं से ये छवि हमारी क्यों बनती जा रही है? ये विचारणीय बात है कि विदेश नीति में अगर भारत एक आश्रित राज्य बन गया तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। सांस्कृतिक दृष्टि से मैं आपके बजट में देख रहा था कि राजभाषा के प्रचार के लिए भी मिशंस काम करते हैं। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि जिस दिन हमारे प्रधान मंत्री जी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में गए थे, उसी दिन क्या हुआ था, संस्कृत की जो चेयर थी, वह समाप्त हो गई थी।

"This culturally disastrous decision of Cambridge University was announced within hours of Cambridge honouring our Prime Minister Manmohan Singh with a doctor of law degree, in what some scholars believe to be the most cynical form of 'tactless academic marketing.'

प्रधान मंत्री जी को डिग्री दी और संस्कृत की चेयर समाप्त कर दी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कभी चिन्ता की? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दुनिया में जितनी संस्कृत की चेयर्स थीं, वे आज हैं या नहीं? हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हिन्दी कितनी जगह पढ़ाई जा रही है? विदेश मंत्री जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि आज संस्कृत और हिन्दी का स्थान चाइनीज़, परशियन और अरेबिक ने ले

लिया है। आपकी चेयर्स, आपके छात्र घट रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के पास कुछ देने के लिए नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। विदेशों में लोग तमिल भाषा का बहुत अध्ययन करते थे, तमिल और संस्कृत, ये भारत की दो भाषाएं थीं, जिनका जबरदस्त अध्ययन होता था। आज कितनी जगह इनका अध्ययन हो रहा है? जो लोग हिन्दुस्तान को समझना चाहते हैं, वे जानते थे। मेरे पास वह लेख है, जो विदेशों में इस बारे में लिखे गए हैं कि संस्कृत और तमिल का क्या महत्व है, आज हिन्दी का महत्व नहीं है, क्यों? विदेश मंत्रालय इस मामले में क्या कर रहा है? मैं जानना चाहूंगा कि आपके विदेशी मिशन हिन्दी के प्रचार के लिए और जहां-जहां हिन्दी की चेयर्स हो सकती हैं, वहां उन्हें स्थापित करने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं? सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की पहचान बनाने के लिए, एक स्वाधीन भारत की पहचान बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? चीन खोल रहा है, चीन नेपाल में भी चाइनीज़ सेंटर खोल रहा है। चीन अरुणाचल के बार्डर पर चाइनीज़ एजुकेशन के सेंटर खोल रहा है।

आप क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर चीन सांस्कृतिक आक्रमण कर रहा है। हम उसकी तरफ से लापरवाह हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि विदेश नीति का पूरे तौर पर आप पुनर्मूल्यांकन कीजिए। सबको बुलाकर राय लीजिए। विदेश नीति में बहुत गहरे मतभेद होने ठीक नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से देश की विदेश नीति ऐसी बने, जिस पर आम सहमति न हो। थोड़े-बहुत अन्तर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बातों पर एकमत होना चाहिए। भारत की छवि बने, भारत की प्रतिमा बने, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर आए और भारत, भारत के रूप में निकलकर सामने आए। भारत, सिर्फ एक भूगोल मात्र नहीं है, भारत सिर्फ आर्थिक दृष्टि से एक बाजार नहीं है, भारत एक विचार है। The idea that is India. वह आइडिया सारे देश और विश्व के सामने होना चाहिए। उस आइडिया को हम सारे विश्व के अंदर लोगों तक पहुंचा सकें कि What is the meaning of India? यह भारत क्यों है। वह कौन सी बात है कि 'मिटती नहीं हस्ती हमारी' वह बात हमें दुनिया के अंदर पहुंचानी है। यह विदेश नीति का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि ये कार्य विदेश मंत्रालय के द्वारा नहीं हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Mr. Deputy-Speaker Sir, I stand here to support the Demands for Grants of the Ministry of External Affairs. As I was listening to hon. Member Dr. Murli Manohar Joshiji, one thing that came across time and again was his proposition that India's foreign policy today is, in his own words, *dishaheen* and *lakshyaheen,* that is, without goal and without direction. Nothing could be farther from truth.

Let me start by quoting our first Prime Minister Jawaharlal Nehruji in a speech that he made in this very Parliament at the stroke of midnight, his famous 'Tryst with Destiny' speech. In the middle of the speech Nehruji took a pause and then said: "It is a fateful moment for us, for all Asia and the world. A new star rises, the star of freedom in the east." Nehruji had then, in 1947, anticipated the impact of the rise of India on the world.

Our Prime Minister Dr. Manmohan Singhji in his response to the Motion of Thanks to the President's Address had quoted Victor Hugo by saying 'no power on earth can stop an idea whose time has come'. Well, I believe the time for the rise of India has come, has arrived. We can see the rising global stature of India in the rightful place that India is getting in various global fora, ranging from G-20, where it is helping transform G-20 into a premier international organization in the post financial crisis world to the leadership that India has shown in the South-South cooperation in organizations such as BRIC.

We can see the rising India in the success of Indo-US nuclear deal in which without signing the NPT India was able to break through the apartheid and setting stage for a new global nuclear order. We can see India rising in the spectacular success that it has achieved in isolation of Pakistan in the aftermath of Mumbai attacks. And I will dwell much more on that attack later. We can see the global stature of India rising. Now our opposition benches can choose to blind themselves from this success, from India's rising stature. They can choose to completely ignore it. But I would urge them to take some pride in it.

Sir, I congratulate our hon. Prime Minister Dr. Manmohan Singh, the UPA Government and our hon. Minister of External Affairs for the success that India has had in this regard. This, I choose to be my main theme of my intervention today – the rising stature of India on the global stage – in response to Dr. Murli Manohar Joshiji.

Let me start by elaborating a little bit on the aftermath of Mumbai attack. The kind of consensus that we were able to build against terrorism or the terror attacks targeting India in the aftermath of Mumbai attack was unprecedented. The leaders from great nations of the world, from the United States to the United Kingdom, toppled over each other to express consolidation with India, expressed concern over the attacks and they even went further; they urged Pakistan to take action against the terror mechanism operating on its soil. This is a pointer towards rising global stature of India.

The reason why I say that is – we can contrast this reaction of the global leaders with the reaction in the aftermath of the attack on Parliament. What happened when Parliament was attacked? Immediately after the Parliament was attacked, we saw a period of rising tensions which led to American intervention. The then US President Bill Clinton said that India and Pakistan represent the most dangerous neighbourhood in the world. Compare this with the reaction that we were able to achieve. The reaction that we were able to achieve was not through jingoism or empty rhetoric. It was through hard work, behind-the-scene diplomacy and a clear-headed foreign policy approach.

I believe there has been a significant shift, a paradigm shift in the way we see us with respect to the world since UPA has come into being. I am not questioning the concern that the Opposition has. They are as deeply hurt in their hearts when the attacks on Mumbai occurred as we are. Similarly we were as concerned when the Parliament was attacked, as they were. But the difference lies in approach.

When I was listening to Dr. Murli Manohar Joshiji, a point which came across again and again is this. His whole argument was based on fear of our neighbours. कभी वह कह रहे थे कि चाइना हमें यहां घेर रहा है, वहां घेर रहा है। कभी वह कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास आज हमसे ज्यादा आक्रमण करने की शक्ति है। उन्होंने आज यह भी कहा। ...(व्यवधान) पाकिस्तान के बारे भी कहा और चाइना के बारे में तो उन्होंने बहुत बार कहा। His entire argument was based on apprehension of our neighbours, fear of our neighbours. I think our approach is based on confidence in us and that is the difference.

That is the reason why when Parliament was attacked we did not see a single nation come in our favour. We did not see the spectacular isolation of Pakistan that we see in the aftermath of Mumbai attacks. We have to start behaving like a serious and responsible global power which we have achieved in the last five or six years. We can see that - the sense of the degree of responsibility in the knee-jerk reaction after the Parliament was attacked. No responsible nation will be talking to its neighbour while the neighbour is readying to attack itself as we saw in the NDA regime. I think there has been a fundamental shift here.

Again, coming back to the central thing, the rising global stature of India, which I am hoping that by the end of my intervention, some of the Opposition Members will acknowledge and appreciate and take pride in, rather than just ignore, take the Indo-US Nuclear Deal. That also represented the rising global stature of India. Leaving decades of mistrust behind when in July, 2005 the Nuclear Agreement was signed between India and the United States, it laid the foundation for great relationship between two great nations, two great economies, two great peoples for the 21st century.

What did that Nuclear Deal and 123 Agreement represent? It did not represent for us only an opportunity to diversify our energy mix domestically, but it also exhibited to the world the emerging power that we are. We were able to penetrate through the seemingly impregnable NPT. We were able to carve out an exception for use in the global nuclear regime. We were able, through deft

diplomacy and clear-headed vision, garner IAEA with us and end the nuclear apartheid, which is the term Shri Jaswant Singh uses again and again. We were able to end that and lay foundation for a new nuclear order. This is something I will talk about when I talk about the Prime Minister's visit again.

While that was a great success and I think, it represented the rising stature of India globally, as far as Indo-US relationships are concerned, I have a couple of observations that I would like to make. With the conclusion of the Nuclear Deal and coming of the new administration, the Obama Administration, in the US, there were concerns whether we would lose steam and momentum. As far as Indo-US relationships are concerned, I think, we need to be careful on that count. There is a big opportunity for us to deepen our relationship and make it much more multi-faceted while there is no doubt that economics and business are going to drive this relationship and they will always provide the backbone. There is a huge opportunity in the field of agriculture, infrastructure and education and we need to take this relationship to the next level. This, in my opinion, is a very interesting opportunity in front of our Foreign Office as we go forward.

Again, America is showing an extraordinary interest in the Afghanistan-Pakistan situation today. I think, we should seek to use this extraordinary interest that they have there, in securing more pro-active Washington intervention and more pro-active pressure from Washington on Islamabad to bring about long-term structural changes inside Pakistan, when it comes to dealing with terror mechanism there. I congratulate hon. Prime Minister on bringing out a very important issue in his recent visit to the US, which was very widely reported in the Press, the fact that he brought up the concern over end use of military and monetary aid of America and that a large proportion of this aid ends up getting used against us. The fact that he was able to bring it up with President Obama, I think, is worthy of appreciation.

The third theme that I want to touch on today, again related to the central them of the rising stature of India on the global stage, is how the scope and

ambition of our Foreign Policy has shaped up over the last few years, be it the aftermath of global economic crisis and how India played the leadership role in transformation of G-20 into one of the premier organisations as far as the economic affairs in the world are concerned in the aftermath of the crisis. From there, be it the South-South Cooperation, it also exhibits this, with formulation of the BRIC. The Prime Minister is just coming back from Brazil. Dr. Murli Manohar Joshi was just saying that we have completely forgotten Russia. What better example can there be than that the first conference of BRIC was held in Russia. India was the first country to go there and our Prime Minister had a very successful visit there. From there, we have to look at India's engagement in the East – Look East Policy. Dr. Murli Manohar Joshi talked about China and all that. I think, we need to strengthen our Look East Policy. Be it our association with ASEAN or the East Asian Summit, we need to deepen our ties with East Asian countries which, I think, will help us in dealing with China and in actually gaining a better relationship out of China.

15.00 hrs.

Similarly, there is deeper engagement with Africa. This is a very appropriate example of the scope and ambition of our foreign policy. I was researching on what NDA's policy was towards Africa. I am sure there was some and I am sure that some of the Members will enlighten us with the policy that they had towards Africa later on. But I could not find any.

The first Indo-Africa Summit, which was held in 2008 in New Delhi signifies something very significant. The deeper engagement with Africa and the acceleration of our relationship with Africa, as we go forward, I think, is a very interesting opportunity for our External Affairs office as we go on. … (*Interruptions*)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): नेल्सन मंडेला कब आये थे? ...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): जब आपको बोलने का मौका मिले, तब आप जरूर बताइये। मगर बहुत रिसर्च की, लेकिन आपकी अफ्रीका के प्रति कोई पालिसी ही नहीं मिली।

Coming back to our neighbour, namely, South-East Asia, I believe that this immediate neighbourhood presents an interesting opportunity. I think that we need to change the way we have been dealing with our immediate neighbourhood with our new found confidence and the rising global stature. Let me explain as to what I mean by this. I think that the key principle in dealing with our immediate neighbourhood -- be it Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka -- has to be much more focussed on economy. I was looking at some numbers. The intra-regional trade in South-Asia, the Indian Sub-continent, as a percentage of the regional trade stands at 5 per cent making this the least economically integrated region in the world. The time has come for us to break the shackles and look towards furthering economic ties with our small neighbours.

We have taken a lot of welcome steps in that direction be it extension of credit lines of $ 1 billion to Bangladesh; Bangladesh opening up the Chittagong Port, which Mr. Joshi said that Bangladesh is giving Chittagong Port to China -- I do not know where he is getting his statistics from; or be it opening up of US $ 425 million line of credit to Sri Lanka to build infrastructure around Jaffna in North Sri Lanka. I think that we have taken right steps towards economic integration and deepening of economic ties, but much more needs to be done.

On the one hand we see that there is no economic integration in this region, and on the other hand we see that this region faces common humanitarian problems, and as some would say that this region has a common soul and we need to move towards deepening of economic ties and use it as a principle in our immediate neighbourhood. I think that while SAARC provides a framework to politically and culturally build our ties, but as far as economic relations are concerned, we need to focus much more on bilateralism and one-to-one discussions.

As far as China is concerned, China represents a challenge as well as an opportunity. Both the countries are one of the oldest civilizations; greatest cultures; most populous nations; and by 2030, we would represent the second and third largest economies. Therefore, we cannot afford to be at loggerhead with China. We need to build sustainable relationship with China, and our Government has been achieving sporadic success as far as this is concerned. We saw cooperation with China as far as G-20 is concerned; we saw cooperation with China in the Copenhagen Summit; and the recent visit of our External Affairs Minister led to establishment of direct communication line between our topmost leadership. Further, it is not that we do not have our share of problems that we need to solve and overcome while we move ahead with our relationship with China. But I must say and point out that sustainable relationship with China can only be achieved through our approach, which is an approach of confidence in us and not an approach, which fears China.

What Dr. Murli Manohar Joshi was repeatedly pointing out चीन हमें घेर रहा है and what Shri Yashwant Sinha said about the Copenhagen Summit … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : On the Copenhagen Summit, Shri Yashwant Sinha said that the reason why India and China cooperated there was because China needed us more than we needed China. I think there is a deep-rooted suspicion, even apprehension, even fear of China, in some of these thoughts. Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have to say that we do not fear China, we do not need to fear China. We have confidence in us. That is the basis on which we achieved sustainable relationship with the United States, and that is the principle on which we should look to build sustainable relationship with China, and on no other principle.

Finally, let me congratulate our Prime Minister on the success of the recent trip to the United States, on his remarks at the Nuclear Security Summit in which he reiterated India's stand, India's vision – a vision that was laid by late Rajiv

Gandhi Ji in 1988 of reduction in nuclear armament, when in 1988 he put forth a concrete action plan of complete nuclear disarmament, but on a non-discriminatory framework. I congratulate our Prime Minister for reiterating that vision at the Summit and also for showing leadership in offering to set up Global Centre for Nuclear Energy Partnership in India. I think it is a great leadership that Prime Minister showed in offering to set up such a Global Centre for Nuclear Energy Partnership in our country. I urge the Prime Minister to name the Global Centre for Nuclear Energy Partnership as Rajiv Gandhi Global Centre for Nuclear Energy Partnership since it was Rajiv Gandhi Ji who had actually shared with the world his vision of nuclear disarmament. चूंकि हम लोग लोक सभा के सदस्य हैं, आखिर में मैं प्रधानमंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि ग्लोबल सेंटर फार न्युक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप अगर इंडिया में बने तो वह रोहतक में, मेरी कांस्टीट्वेंसी में बने।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, विदेश नीति का मतलब है कि किसी देश के ज्यादा से ज्यादा मित्र देश हों और कम से कम विरोधी देश हों। ऐसी विदेश नीति ही सफल विदेश नीति मानी जाती है। अभी हमारे नौजवान साथी ने बहुत अच्छा बोला है, खुशी है कि उनमें उत्साह है, लेकिन विदेश मंत्री जी हमें यह बता दीजिए कि दुनिया में कौन सा देश आपका मित्र है? मैं यही जानना चाहता हूं। संबंध होना अलग बात है, लेकिन आज हिंदुस्तान का कोई मित्र देश नहीं है।...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी : सभी हमारे मित्र हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : नारायणसामी जी, खड़े होकर बता दीजिए कि फलां देश हमारा मित्र है। संबंध अच्छे हो सकते हैं, आर्थिक संबंध हो सकते हैं, संचार आदि संबंध हो सकते हैं, लेकिन मित्र कौन है, बता दीजिए। जब कोई देश आपका मित्र नहीं है, तो विदेश नीति कैसे सफल है? मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि देश वही सफल होता है विदेश नीति में जिसके ज्यादा से ज्यादा मित्र हों और बहुत कम विरोधी हों। कुल मिलाकर इस पर चलने की कोशिश कीजिए। चिदंबरम साहब आप कोशिश कीजिए, आप भी कोशिश कीजिए। आज जहां तक चीन का सवाल है, क्या आप यह समझते हैं कि चीन कभी आपका मित्र हो सकता है।

मैं यह बात रिकार्ड पर लाकर कहना चाहता हूं कि चीन हिन्दुस्तान का मित्र न कभी रहा है और न कभी रहेगा। मैं वह दिन जानता हूं, जब हम बच्चे थे। उस समय चाऊ एन लाई यहां आए थे और उन्होंने हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा दिया था। हम सब बच्चों से स्कूल्स में यह नारा लगवाया जाता था कि हिन्दी-चीनी भाई-भाई। आपने भी उस समय यह नारा लगाया होगा। उसके बाद चाऊ एन लाई तो यहां से चले गए और वहां जाकर उन्होंने हिन्दुस्तान की स्थिति का आकलन किया और पूरी तैयारी करके सन् 1962 में हिन्दुस्तान पर हमला किया। क्या आप उस वक्त जो एक लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन ने हमसे कब्जा लिया था, वापस लेने का दावा कर पाए हैं या उसे वापस लेने की हिम्मत या क्षमता रखते हैं? मैं मानता हूं कि तब से लेकर अब तक हिन्दुस्तान में काफी बदलाव आया है और वह पहले से अधिक शक्तिशाली हुआ है। सन् 1947 और आज की तुलना करें तो स्थिति में काफी फर्क है। लेकिन आप यह भी देखें कि जापान जो सन् 1943 में एक प्रकार से बर्बाद हो गया था, तब की तुलना में आज कहां है और चीन भी तब की तुलना में आज कहां है। आज हम इन देशों के मुकाबले में लोहे, कोयला और सीमेंट के मामले में कहां है। जिस अनुपात में जापान आगे बढ़ा है, उसके मुकाबले हम कुछ भी आगे नहीं बढ़े हैं। इससे पता चलता है कि आपकी विदेश नीति कहां है।

आपकी विदेश नीति इससे पता चलती है कि आप अमेरिका जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं, चीन जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं और रूस जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। यह तो वही बात हुई कि गंगा गए तो गंगादास और यमुना गए तो यमुनादास। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यह कोई मामूली बात नहीं है। मैं चीन की बात फिर दोहराना चाहता हूं कि चीन का निशाना हिन्दुस्तान है और उसके बाद अमेरिका है। यह उसकी दूर-दृष्ठि है। उसका निशाना अमेरिका भी है, लेकिन बीच में कहीं हिन्दुस्तान अवरोध न बन जाए इसलिए सबसे पहले वह हिन्दुस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहता है, और दबाव में रखना चाहता है। ऐसा उसने किया भी है। वह हमारी एक लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि पर अभी तक कब्जा किए हुए है। हम उसे वापस लेने की आज तक हिम्मत नहीं कर पाए हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि होता है तो चीन के शासनाध्यक्ष से हाथ मिलाते हैं।

मैं जब छात्र था, यह सन् 1962 के करीब की बात है, तब से हमारे दिमाग में यह भरा हुआ है कि चीन के हमले के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को झटका लगा था। उन्होंने चीन पर काफी विश्वास किया था और जब चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया तो उन्हें झटका लगा, परिणामस्वरूप उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अच्छा काम किया था कि हिन्दुस्तान को तृतीय दुनिया का अगुवा बनाया था, नेतृत्व किया था। आप बताएं के आप कितने देशों का नेतृत्व कर रहे हैं? नेहरू जी के जमाने में कितने ही देश हमारे मित्र बने थे। लेकिन चीन को यह खटका कि भारत आगे बढ़ रहा है इसलिए नेहरू जी की छवि खराब करने के लिए उसने हमारे देश पर हमला किया। हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, कारतूस नहीं थे। इस कारण उसने हमारे देश के काफी बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया और लड़ाई जीत ली। उस हमले में हम बुरी तरह से हारे और पिटे।

मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि चीन आपसे दोस्ती कभी नहीं कर सकता। हमारे प्रधान मंत्री जी आजकल विदेशों के काफी दौरे कर रहे हैं। वह ऐसे प्रधान मंत्री हैं कि दौरे ही दौरे हो रहे हैं, देश में कम ही दिखाई देते हैं। अगर कोई मीटिंग करनी होती है तो किसी मंत्री को अपनी जगह भेज देते हैं। सत्र चल रहा होता है, तब भी बाहर होते हैं या फिर तारीख बदल देते हैं। वह अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। आज सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो रही है, क्या प्रधान मंत्री जी का उसमें होना आवश्यक नहीं था?

निर्णय प्रधानमंत्री को लेना है। विदेश मंत्री को निर्णय नहीं लेना है। अगर किसी देश से बात करनी होती है, तो ऐसा नहीं है कि पहले कैबिनेट से बात करके जाते हैं। वहां प्रधानमंत्री अपने विवेक से फैसला लेता है कि किसी देश के साथ कैसे संबंध बनाने हैं। यह बात सही है कि आज हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान की न तो सेना कमजोर है और न ही किसान कमजोर है। हमें किसान और जवान दोनों मजबूत चाहिए। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने " जय जवान जय किसान " का नारा ऐसे ही नहीं दे दिया था। उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह नारा दिया था। इस नारे के पीछे कारण था कि खेती को आगे बढ़ाएंगे और जवानों को मजबूत करेंगे। वे देश की रक्षा करेंगे। देश को सम्पन्न और शक्तिशाली बनाने के लिए यह नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा करके भी दिखा दिया। यह अलग बात है कि उनका निधन किन परिस्थितियों में हुआ। हम यह मानते हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ, जिसने देश के सम्मान को बढ़ा दिया। उस वक्त देश का सम्मान ऊंचा हो गया था।

नेपाल के बारे में कहा गया है और यह बात सही भी है कि पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध रहने चाहिए। हम लोग गांवों में या शहरों में रहते हैं, जहां हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना जरूरी होता है। यदि अगर बगल के घर से दुश्मनी हो जाए, तो चिंता रहती है, तनाव रहता है। नेपाल हमारे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्या नेपाल आज हमारे साथ है? मैं नेपाल गया था। वहां चार-पांच दिन रहा। नेपाल की सरकार, वहां की जनता पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से सहायता की जा रही है, आटा भी देंगे, अनाज भी देंगे, लेकिन उस पर कब्जा करने चीन जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल चीन के हाथों में जा रहा है। नेपाल की सरकार और नेपाल की जनता बहुत परेशान है। नेपाल के राष्ट्रपति श्री राम बरन यादव हमारे यहां आए थे। आप बताएं कि हिंदुस्तान का कौन सा महत्वपूर्ण नेता उनसे मिला। मैं उनसे मिलने गया था। उनको अंदर से वेदना थी कि वे कुछ बातचीत करते और हमें अपने यहां की स्थिति के बारे में बताते कि उनके यहां सीमा पर क्या स्थिति है। वे हिंदुस्तान के हैं। नेपाल में तीन पीढ़ी से रह रहे हैं। बिहार में उनके पूर्वज रहते थे। उनको चिंता है और वे देख रहे हैं कि चीन उनके आस-पास क्या कर रहा है तथा क्या गतिविधियां चला रहा है। विदेश मंत्री जी और गृह मंत्री जी मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अराजकता और अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान किस तरह से हथियार चीन के माध्यम से नेपाल होते हुए भारत में भेज रहा है। आतंकवादी, नक्सलवादी को हथियार उपलब्ध करा रहा है कि हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा हो। क्या विदेश मंत्री और गृह मंत्री जी को इसकी खबर है? हमें खबर है।

हम इस सदन में सही खबर दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? नेपाल के लोग कह रहे हैं कि एम्बेसेडर बैठा है। आप नेपाल से पूछिए, गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री जी बुलाइए, नेपाल के राजदूत बैठे हैं उनसे पूछिए कि क्या आपको मालूम है कि किस तरह से हथियार पाकिस्तान नेपाल होकर ले जा रहे हैं? क्या यह आपकी जानकारी में है? क्या नेपाल के लोगों ने मिलकर, प्रतिनिधि मंडल ने उसकी सूचना दी है? आप हिन्दुस्तान में जवाब दें तो हिन्दुस्तान में नेपाल के राजदूत रहते हैं, उन्होंने आपको खबर दी थी, यह भी बताएं। अगर खबर नहीं दी है तो तत्काल बर्खास्त करो। अगर हमारी सूचना पक्की न हो तो बताएं। राजदूत को पता है और राजदूत ने कोई खबर नहीं दी, यह मेरी अब तक की जानकारी है। 15 दिन पहले तक की जानकारी है। मैं नेपाल गया था, बकायदा पूरे नेपाल की संस्कृति, स्वभाव, रिश्तेदारियां और वैवाहिक संबंध अब तक हिन्दुस्तान के साथ चल रहे हैं। उन्होंने सूचना दी कि यह हो रहा है और आपके राजदूत को हमने बता भी दिया है। यहां के राजदूत ने हिन्दुस्तान की सरकार को बताया या नहीं बताया? मैं वहां क्यों बैठा? मैं कह रहा हूं कि आज ही जानकारी लीजिए, अगर सूचना नहीं दी तो रातों रात दूसरे एम्बेसेडर को भेजिए और उन्हें हटाइए। अगर सूचना दी है तो आपने क्या किया, आपको सदन को बताना चाहिए। राजदूत ही यह काम कर रहा है। जब आप जवाब दें तो बताएं। नेपाल आपका करीबी है। हिन्दुस्तान के साथ शादी, विवाह भी हो रहे हैं, नेपाल चीन का साथ दे रहा है। हम दल का नाम नहीं लेंगे, वहां थोड़े दिन के लिए सरकार चीन के हाथ में थी। नेपाल के राष्ट्रपति बचा ले गए। वहीं करीब किनारे पर उनका रहना-सहना चीन की जमीन पर रहता है और बातचीत नेपाल से करते हैं। ये नेपाल में हो रहा है। राष्ट्रपति बन कर आए इसलिए राष्ट्रपति हम लोगों के हो गए। वे परेशान हैं, दुखी हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहां हमें कोई मिलने नहीं आया। कोई ऐसा नहीं आया, जिसे मैं बताने आया था, और कोई नहीं था। हिन्दुस्तान में कम से कम इस बहाने से हम सारी सूचना देते कि क्या हो रहा है। न विदेश मंत्री मिले, राष्ट्रपति जी ने खाना जरूर खिला दिया। राष्ट्रपति जी को मिलकर बात करनी चाहिए थी हम कैसे कहें कि हमसे बात कीजिए, यही मौका है। अगर कोई अकेले में मिलने गया हो तो सब बता देते। हम अकेले में मिलने गए तो सब बता दिया, मैंने कहा कोई आया, कहते हैं नहीं आया। कोई मिलने नहीं आया। न वहां के गृह मंत्री आए, न विदेश मंत्री आए। किसी ने मिलने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है मानिसकता के आधार पर न मिले हों। आप बुरा मत मानिए।...(व्यवधान) चलिए वह जानें कि कैसे किया था।...(व्यवधान) हां मिलने गए होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं। जब तक हम गए तब तक नेपाल के राष्ट्रपति जी से कोई मिलने नहीं गया था।

15.24 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)

पहली बार हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप पहले हैं जो मिलने आए हैं। अब आप सोचिए, खाना खिला दिया, यह अलग बात है। क्या यह मिलना माना जाएगा? क्या यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति जी का भोज हुआ है तो सब मिल गए। भोज की बात नहीं है, अलग से मिलने नहीं गए। बातचीत नहीं हुई, वे अलग से कहीं बैठकर बातचीत करना चाहते थे। उन्हें खाने का कोई शौक नहीं था, वे आपको सारी बातें बताने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हमसे कोई पूछने नहीं आया कि बगल में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय : आपकी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसीलिए मैंने नहीं टोका। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि पाकिस्तान नेपाल और बंगाल से होते हुए हिंदुस्तान में हथियार भेजे जा रहे हैं। ...(व्यवधान) जब नेपाल उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, फिर बिहार की क्या बात है। आप बिहार की बात बाद में कहिये, जबकि नेपाल उत्तर प्रदेश से पहले से ही मिला हुआ है। यह हालत आज विदेश नीति की है। विदेश नीति की आज कोई जानकारी ही नहीं है। कभी हम लोगों को भी बुला लिया करें। हम इसलिए ये बातें कह रहे हैं, चूंकि विदेश नीति के बारे में हम याद करते हैं कि विदेश सेवा में जब लड़के काम करते थे, तब विदेश नीति के बारे में डा.लोहिया उन्हें किस तरह से समझाते थे। लेकिन इस विदेश नीति के चलते किस तरह से देश में गम्भीर परिणाम होंगे, यह मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अब दर्पण की तरह लगता है कि जो वह बोल रहे थे, वही सही हो रहा है। यह आपकी विदेश नीति है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब भी सावधान हो जाइये। यह देश का बहुत गम्भीर सवाल है। इसलिए पूरा सदन इस मामले में आपके साथ है। हमारा देश किसी भी तरह से खतरे में न पड़े। चीन धीरे-धीरे इंच-इंच आगे बढ़ रहा है। क्या आपने पता लगाया कि हिंदुस्तान की इंच-इंच जमीन पर रोजाना चीन कब्जा कर रहा है। कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ अन्य जरिये से यह सूचना आ चुकी है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई है। हम फिर दोहराना चाहते हैं, यहां दोनों जिम्मेदार मंत्री बैठे हैं। होम मिनिस्टर साहब और विदेश मंत्री दोनों बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं। इनके ऊपर गृह का और बाहर का बहुत भार है। इसलिए हम आप दोनों से बहुत मजबूती से कह रहे हैं कि आप कभी हम लोगों को भी बुला लीजिए और हमारी बात सुन लीजिए। मैं देश के प्रति खतरे के मामले में आपको सावधान कर रहा हूं। आप मजबूत हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। मेरे से पूर्व नौजवान अच्छा बोल गया, ठीक है। आप मजबूत है, हमारी सेना मजबूत है। हमारे लोग कमजोर नहीं हैं। देश की जनता इस मामले में पूरी तरह आपके साथ हैं, यह हम मानते हैं। लेकिन आप छोटे-छोटे मुद्दों पर चीन के खिलाफ मत कहिये,

लेकिन कम से कम कुछ प्रतिक्रिया तो दीजिए। आप प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। इस बारे में कभी भी आपका एक बयान तक नहीं आया। हमने बयान भी दिये, हमने प्रैस कांफ्रैंस भी की। लेकिन उसके बाद कम से कम हमें ही बुला लेते कि आप क्या बयान दे रहे हैं। आप चीन के खिलाफ ऐसी नीति क्यों अपना रहे हैं? हम नेपाल में जो देखकर आये हैं, इसलिए उसे कह रहे हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी आये, करीब डेढ़-दो घंटे हम लोगों ने बातचीत की। मैं आपको आज सावधान करना चाहता हूं कि आज आप इस बात को सुनिये, समझिये, कभी हम लोगों को बुला भी लीजिए। आज और भी खतरे हैं, आज चीन और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि चीन कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता है और पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के साथ है। चीन उसे पूरी तरह से हथियार और शक्ति देकर आपके खिलाफ खड़ा करना चाहता है। पाकिस्तान अभी सीधा आपके सामने खड़ा नहीं होना चाहता है। लेकिन एक समय आयेगा, जब वह आपके सामने सीधा खड़ा हो जायेगा। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे जो विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले जो समझ पाया, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में कमी है, उसकी तरफ आपका थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं, फिर उसके बाद टैक्नीकल बात करूंगा। अभी तक मैं यह नहीं समझ पाया, हालांकि हमने पोलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जैक्ट पढ़े हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में कोई डेफिनेट पॉलिसी है ही नहीं, यह पॉलिसी जो मैं समझ पाया, फॉरेन सैक्रेट्री पर डिपेंड करती है। अगर नटवर सिंह जी आए तो दूसरी पॉलिसी हो गई, अन्य कोई आया तो दूसरी पॉलिसी हो गई, इसमें न कंसिसटेंट्सी, न सोच है और न कोई रिसर्च है। अगर कहा जाए तो यह फायर ब्रिगेड की पॉलिसी चल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आग लगी,...(व्यवधान)

मैं बता रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : ऐसा नहीं है। नेहरु जी के ज़माने में जो विदेश नीति अपनाई गई है, ...(व्यवधान) आप यह कहिए कि उसका ये पालन नहीं कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं धीरे-धीरे बात करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आप मंत्रिमंडल में थे, आपको ज्यादा मालूम है। लेकिन एज़ ए सिटीजन, 35 साल से हाईकोर्ट और कांस्टीट्यूशन लॉ को समझते हुए अभी तक इसमें कोई डेफिनेट शेप ही नहीं आयी। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, जैसे नेबर की पॉलिसी आई है। मैं हमेशा यह सोचता था कि हमें अपने नेबरहुड की पॉलिसी दो किस्म की रखनी चाहिए, एक वह नेबर, जो हमसे कमजोर है और एक वह नेबर, जो हमसे शक्तिशाली है। जैसे हमसे अगर कोई कमजोर है, आप नेपाल से शुरु करिए। कोसी नदी में जो पानी बढ़ कर आया, तीस साल से नेपाल की गवर्नमेंट कह रही है कि आप आइए, मदद करिए, हमारा डेम बढ़ा दीजिए, उसमें बिजली का हाईड्रो इलैक्ट्रिक पावर दे दीजिए, लेकिन किसी ने नार्थ ब्लॉक में कह दिया कि बिजली ये चार्ज करेंगे और यह नहीं हो पाया। हर तीन-चार साल बाद बिहार डूबने लगता है, पटना में पानी आ जाता है। नेबरहुड की पॉलिसी में कोइराला गवर्नमेंट के जमाने से पूरे भारतवर्ष ने नेपाल को डिस्टेब्लाइज़ किया, चाहे वह डेमोक्रेसी के नाम से हो। लास्ट में वहां जो हत्याकांड हुआ, उसे आप देख रहे हैं। अब हमारे उत्तरांचल के बार्डर में पूरी तरह से माओवादियों के कैम्प लग गए हैं और चाइना खुल्लमखुल्ला उनकी मदद कर रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारा कहना यह है कि जो छोटे नेबर्स थे, जिन्हें हम कल्चरली ठीक से कर सकते थे, हमारी यह फेल्योर कंसिसटेंट रही। अगर कोई कंसिसटेंट पॉलिसी होती तो नेपाल को हम लोग डेवलप करते और वे डेवलप करते कि हमारी इतनी ज्यादा कल्चरल रिलेशनशिप होती कि

उनकी इंटरफियरेंस न होती।...(व्यवधान) हमें मालूम है कि बंग्लादेश कैसे बना, मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन बंग्लादेश की पूरी गवर्नमेंट हमेशा हमारी तरफ मुख़ातिब है। शेख हसीना अभी भी आपसे हर तरह से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक छोटी सी रिफ्यूज़ी प्रोबलम सोल्व नहीं कर पाए। जब पानी भरता है तो हजारों-करोड़ों लोग आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब, इन्हें मत भगाओ, शायद ये वोटर हो जाएं, ऐसे तो पॉलिसी नहीं चलेगी। जब वे इतने तैयार थे तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए था। विदेश मंत्री तो बदलते रहते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो, जो इस पर कंसिसटेंट सोच करे, रिसर्च करे तो पॉलिसी क्रिस्टलाई होती है, थोड़ी-बहुत आप री-एडजस्टमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर लीजिए। आप श्रीलंका की पॉलिसी देख लीजिए। अगर हम लोग तमिलियन की पॉलिसी 80 और 90 के बीच में देखते तो राजीव गांधी जी की शहादत न होती। यह हमारी पॉलिसी का दोष था, हम श्रीलंका जैसे देश को ठीक नहीं कर पाए और जिस फज़ीहत से हमें अपनी फौजें, आर्मी विदड्रा करनी पड़ी, इस बात को सब जानते हैं, हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।

अब यह तो आपने श्रीलंका देख लिया। अब आपकी पॉलिसी क्या है। हम तो इससे अच्छा यह समझते हैं कि यदि दलाईलामा फॉरेन मिनिस्टर होते, तो और अच्छी तरह से पॉलिसी बनती। आप चायना से इतना डर रहे हैं कि वह अरुणाचल को अपना प्रदेश कह रहा है। वह कह रहा है कि जम्मू-कश्मीर से पहले हम वीजा नहीं देंगे। उससे आप इतना क्यों डर रहे हैं? हमारे कहने का मतलब यह है कि यदि हम अपने सिद्धान्तों की फर्मनैस नहीं देंगे, तो काम नहीं चलेगा।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 26/11 का मुम्बई में ओबराय होटल में जो कांड हुआ, उसका हम कोई एडवांटेज नहीं ले पाए। क्या कमी थी? मैंने खुद जाकर देखा है, जितनी हमारी फॉरेन एम्बैसीज हैं, वहां के दूतावास या तो अपने डैवलपमेंट में परेशान हैं या अपने सैक्रेट्रिएट के डैवलपमेंट में। उनका कोई पब्लिक रिलेशन दिखता ही नहीं है।

महोदय, अब मैं अपनी बात के सेंटर पर पुनः आना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जैसे दो किस्म की पॉलिसीज होती हैं। अब अगर हमें अपने नेबर्स में से किसी से खतरा है, तो सिर्फ चायना से है। जब माननीय मुलायम सिंह जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने 1962 के इनवेजन की बात कही। मई 1962 में इनवेजन हुआ। उससे पहले चाऊ-एन-लाई यहां आए और उस समय उनकी मांग सिर्फ यह थी कि हमारा जो बॉर्डर है, वह ठीक कर दिया जाए और कर्नल मैकमोहन बार्डर लाइन का जो वाटरशैड था, वह उनकी डिमांड थी। उस पर स्वर्गीय पं. जवाहर लाल नेहरू जी तैयार हो गए, लेकिन मार्शल टीटो और बाकी लोग जाने कहां चले गए और मंत्रालय में एक डिप्टी सैक्रेट्री थे, उन्होंने फाइल पर लिख दिया कि यदि यह

मैकमोहन लाइन का बार्डर मान लेंगे, तो न जाने कितने हजार स्क्वायर माइल गड़बड़ हो जाएंगे और चीन ने मई में अटैक कर दिया। वही मांग वर्ष 1983-84 में, इस समय मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, भारत सरकार ने मैकमोहन लाइन को अपना बॉर्डर मान लिया। अगर यही बात 1962 में मान ली जाती, तो यह इनवेजन नहीं होता। हमारी और आपकी दूसरी बात है, क्योंकि श्री कृष्णा मैनन को आपने बहुत ज्यादा फोकस दिया। हिन्दुस्तान में यह प्रथा है कि जो अच्छी अंग्रेजी बोले, यो युनाइटेड नेशन का फ्लेयर-अप हो, उसे आप होश्यार मान लेते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं और उसको एकदम इतना बढ़ावा देते हैं कि जब वह धम्म से गिर जाता है, तब दिमाग खुलता है। जो हादसा दो दिन के अंदर हुआ, उससे आप सभी परिचित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कल्चरल पोजीशन है, हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक सोच है, उसे हम क्यों प्रतिपादित नहीं करते?

महोदय, पाकिस्तान हम से हर चीज में कमजोर है, लेकिन डिप्लोमेसी में वह आपको पछाड़ रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि यह जो काम है, जो फ़ॉरेन पॉलिसी का वर्क है, यह बहुत टैक्नीकल है। It is very technical. यह काम जनरल ले मैन से नहीं चलाया जा सकता है। उस टैक्नीकल की एक्सपर्टाइज में एक ऐसी थिंक टैंक टाइप, नॉट पेंटागन, जो अमेरिकन्स में है, मंत्रालय में होनी चाहिए। मुझे याद है कि एक टाइम में कांग्रेस के जमाने में, एम्बैसेडर्स वगैरह, कोई दूसरे आदमियों को बनाते थे। श्री नटवर सिंह जी जिसको कहते, उसे ही एम्बैसेडर बनाते थे। हमारे कई लड़के, जो इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में हमारे साथ थे, वे कहते थे कि अब फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ नहीं, अब तो पी.एम.ओ. ऑफिस से एम्बैसेडर बनते हैं। यह क्यों?

महोदय, अब मैं दूसरी बात आपके सामने कहना चाहता हूं कि जहां तक मैंने चायना के बारे में पढ़ा, नेपोलियन ने कहा था कि Let the opium-eaters sleep. When they will wake up the world would be sorry. यह बात नहीं है, जितनी भी यह चाइनीज और मंगोलियन जनरेशन है, इनके कॉल और इकबाल पर कोई भरोसा नहीं है। ये इकनौमिक गेन्स के लिए हर प्रकार से काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जापान में देखिए, 5.00 बजे टोकियो बंद होता है और वहां लोग 9.30 बजे तक काम करते हैं। वे कोई ऐसे बड़े भक्त नहीं हैं, लेकिन इकनौमिक गेन्स के लिए काम करते हैं।

महोदय, अब मैं स्ट्रॉंग नेबर की पालिसी की बात बताना चाहता हूं। इसे कैसे शेप दिया जाए, यह एक्सपर्ट्स का काम है। हमारे विदेश मंत्री का अनुभव बहुत है। ये मुख्य मंत्री रहे हैं। विदेश में पढ़े भी बहुत हैं और बहुत सॉफिस्टीकेटेड हैं, लेकिन मैं एक कमेटी में था, उसमें आप कह रहे थे कि चायना से हमारे रिलेशन बहुत कोर्डियल हैं।

हमने उस समय टोका नहीं। जब मैं घर गया, तो मैंने भी आक्सफोर्ड एंड कोलिंस डिक्शनरी पढ़ी कि कोर्डियल का मतलब क्या है? तब हमने सोचा कि हमें तो उसी समय रोकना चाहिए था। विदेश मंत्री चाइना से रिलेशनशिप कोर्डियल अगर कहते तो यह बाहर कंजप्शन के लिए ठीक है, लेकिन रात को एनेक्सी में जब कोर्डियल कहे, तो हमें अफसोस हुआ। ...(व्यवधान) कोर्डियल का मतलब, अगर चाइनीज रिलेशन कोर्डियल है, तो फिर हमको अपनी इंग्लिश की आक्सफोर्ड एंड कोलिंस डिक्शनरी बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी। हुड्डा साहब के पुत्र बहुत अच्छा बोले, लेकिन वह समझ नहीं पाए। जिस लेवल पर डिबेट हो रही थी, वह उसे समझ नहीं पाए। *(Interruptions) ... (Not recorded)* लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट था...(व्यवधान) मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, it is not fair on his part to say like this.... (*Interruptions*)

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Sir, I am sorry and I withdraw it.

अब इकॉनामिक पावर पर आ जाइए। चाइना ने पूरा समान यहां फ्लड कर रखा है। चाइना ने भारत में आतिशबाजी के सामान से लेकर, बच्चों के ट्वायज से लेकर, सब कुछ भर दिया है। ऐसे-ऐसे सामान आए, जो टॉक्सिक थे, तो क्यों नहीं किसी ने लिटिल फिंगर रेज किया? क्या आप घबरा रहे थे? क्या आपकी मिनिस्ट्री जो इसको देखती है, उसने इसको दरकिनार रख दिया, क्योंकि चाइना से सामान आ रहा था। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं, आपको अगर काम करना है, तो आपको रियलिस्टिक पालिसी बनानी पड़ेगी और कहीं न कहीं अपनी प्लेस आफ नो रिटर्न दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखायेंगे, तो ये लोग आपके ऊपर सवार होते जाएंगे। हम पिछड़ते जाएंगे और वर्ष 1962 का हादसा फिर से हो सकता है। अब इस समय लड़ाई की जरूरत नहीं है। अब कोई जमीन नहीं चाहता है।

सभापति महोदय : विजय जी, अब आप समाप्त करिए।

श्री विजय बहादुर सिंह : जब आप मुस्कराए, तो मैं समझ गया। मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। आप जब स्माइल किए, you are so soft. लोकल एनेस्थीशिया लगाकर आप जो आपरेट कर रहे हैं, मैं समझ गया हूं। मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि चाइना की पालिसी के लिए, ...(व्यवधान) मेरा सिर्फ एक निवेदन है, चाइना हमको इकॉनामिकली डी-स्टेब्लाइज करना चाहता है। साफ्टवेयर आई.टी. में, जो हमारी आमदनी है, अगर हम उसको बढ़ा दें तो चाइना भी हमारे लिए कोई फियर की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि रॉंग डिप्लोमैसी से जो हाल हो रहा है, उसका आप मुलाहिजा यह कर लें कि अभी चाइनीज ने आपको एक बार हिलाया और फिर वह वॉच कर रहे है। मेरा मतलब यह है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो बाहर से एनआरआईज वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसको काफी लिबरल कर दिया जाए, तो हमारे यहां बिलयंस एंड बिलियंस डालर्स आएंगे। चाइना ने जैसी आटोमैटिक एक लाइन खींची है, अगर उससे बड़ी एक लाइन खींच दी जाए, तो यह काम समाप्त हो जाएगा। मैं यह बिल्कुल एग्री करता हूं कि यदि आप हैंड्रेड पर्सेंट अमेरिकन सिस्टम पर बिलीव कर रहे हैं, तो it is not safe to keep all the eggs in one basket. मैं अपनी बात इसी समय समाम्प करना चाहता हूं। अगर मैंने कोई बात कही, ...(व्यवधान) I have never thought of insulting anybody. आप इसकी पालिसी को ठीक से बनाइए और ट्रांसपेरेंसी लाइए। धन्यवाद।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, while raising the Demands for Grants pertaining to the Ministry of External Affairs having Demand No.31, I should rather try to concentrate on the publications that have been delivered to the hon. Members of the House.

Many things have been discussed and many deliberations have taken place. But it appears as if the Ministry of External Affairs is the combination of the Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of Finance and the Ministry of Commerce.

In the book and the publication which has been delivered, it has not been taken care of, nor is there any mention about it. I am very much interested to know as to what is the total plan outlay of the Ministry of External Affairs. What appears from the circulation is that the Ministry of External Affairs, by and large, has no plan allocation at all. It is the Ministry which mainly dependent on the non-plan allocation. This allocation is for what? This is for Bangladesh, Bhutan, and Afghanistan. These are the issues related mainly to the functioning of this Ministry. What the Ministry of External Affairs need to implement, and what duties it has to perform have to be recorded in today's deliberations by the Members of both the sides who are taking part in the debate.

You have 166 Missions in different parts of the world that are to be taken care of. You have Passport and Immigration Department to take care; another is training; another is special diplomatic expenditure; entertainment charges which you have to incur for hospitality towards foreign dignitaries or VVIPs who visit our country. International cooperation is an important area concerning your Ministry. Haj goodwill delegation is also very important. Every year millions of people are going for Haj.

Another important thing is technical and economic cooperation with other countries. Another important thing is capital outlay on public works and housing. We must appreciate a few steps taken by the Government of India this time. The

visits of hon. Prime Minister to the USA and to Russia, no doubt, have strengthened our relations with those countries.

Once there were two major forces in the world, the USA and the Soviet Union. Now, the Soviet Union is not in existence. So, the USA has automatically emerged as a big brother of the world. So, we should not have any hesitation in strengthening our relations with the USA. On the issue of nuclear deal, the Government was challenged by some parties. The Party which supported the UPA I, has withdrawn support to the Government on this issue. So, the Government should remain alert and cautious with these types and groups of people. I would rather say that we have to have close association with the USA. If having good relations with the USA is dangerous, then is not having good relations with China not dangerous? If China thinks that 2010 is 1962, then they are making a mistake. Now, it is 2010 and we can say *hum kisise kam nahi.* If China things that it is 1962, then we can give a befitting reply if they want to have any sort of battle or war. We will certainly take care of that.

We should build good relations with all our neighbouring countries. Shri Vijay Bahadur Singh made a mention about Nepal. In Nepal, now the Maoists are in the Government. Did the Government inquire whether any Indian politician keeps visiting Nepal and keeps in touch with the Nepalese Maoists in a close manner? Do these activities reflect in the Indian politics?

Why should we not take into consideration what relations are there between the Maoists of Nepal and a particular political party's Polit Bureau members of this country, who are keeping in touch very regularly, very closely and they are operating.… (*Interruptions*)

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Will you name the particular political party?… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I am naming it. The name of the party is positively the CPI (M) and the Polite Bureau member [*]……. (*Interruptions*)

SHRI A. SAMPATH : Sir, he is telling something about the Polit Bureau members of the CPI (M). The CPI (M) is not encouraging the Maoists.… (*Interruptions*) His party, the TMC is hand in glove with the Maoists.… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I would better repeat it.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please sit down. Let me give the ruling. Shri Bandyopadhyay, what did you say?

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I want to reiterate that the members of the CPI (M) party including (*Not recorded*), positively (*Not recorded*) go to Nepal, interact with the Maoist Group of Nepal. I would like to know whether the Maoist Group has any communication with or connection in India, with those who are operating the Maoist activity in our country.… (*Interruptions*) This is a very simple question. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It can be an exchange of ideology and exchange of views.

… (*Interruptions*)

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Nobody should question our patriotism.… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I think the hon. Home Minister Shri P. Chidambaram will support my stand.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please let him speak. Nothing will go in the proceedings except Shri Sudip Bandyopadhyay's speech.

(Interruptions) ... [*]

MR. CHAIRMAN: What do you want?

SHRI A. SAMPATH : Do not allow him to take the names of the Members of the Upper House.… (*Interruptions*) I am on a point of order.

---

[*] Not recorded

MR. CHAIRMAN: Under what rule are you raising the point of order?

… (*Interruptions*)

SHRI A. SAMPATH : Sir, under what rule is he making allegations against my party?… (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I am delivering my speech.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It is just a statement. Politically, it is generally leveled. From the Chair, I do not want to say anything. Day before yesterday, Shri Acharia was speaking. He also cast some aspersions like this. Therefore, it should not be taken so seriously.

…. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: It should not be taken so seriously.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Bandyopadhyay, please go ahead.

… (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Shri * is a Member of the Upper House. Can he take his name? This is the point which they are making.… (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY : When your Member speaks, let him reply.… (*Interruptions*) He is a political leader.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Mahtab, we can delete the name of *. There is no hard and fast rule.

*(Interruptions) ...**

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : I still reiterate it in the next paragraph. I go ahead with it. It is the question of India's voice heard throughout the world because India is the worst sufferer of terrorism. So, what India is facing nowadays, the world is also facing the threat in the same manner. We must keep our relations

* Not recorded

and build up our relations with our neighbouring countries with two slogans: one, international solidarity and two, brotherhood. India is the firm believer of these two principles: international solidarity and brotherhood. India wants to give this message to the entire world because the world is now facing tension every moment. No country is aware which country is going to be affected at what time.

The South Africans issues have been raised and discussed here. Who does not know that? Our great leader Shri Rajiv Gandhi gave the African Fund to give total moral support. It is not only the total support to Dr. Nelson Mandela's work.

We are extending our fullest economic support to our neighbouring countries which are being appreciated by the whole nation. We have reiterated our commitment to fight against terrorism. We are for food security. I would request the Government to take a strong initiative in this regard. We want to have good relations with different countries of the world whether it is the USA or China. Even on the issue of climate change, the External Affairs Ministry has taken a stand.

Sir, Mulayam Singhji very correctly said about the threat from Pakistan. This is the only country about which we have to remain totally alert. Pakistan is sponsoring terrorism in the whole world. Pakistan is not even prepared to accept the truth that it is their citizens who have attacked the Taj Hotel and other places in Mumbai in 2008. We have arrested one terrorist from that group. Our Home Minister Shri Chidambaram is delivering all the information and documents relating to it, but the Government of Pakistan is not in a mood to accept that the group of terrorists has come from Pakistan. So we must actually remain alert about this force. But there is no enemy as such to us in the whole world because we want to maintain peaceful relations with everybody and even with Latin America, we do not disagree to keep our relations with this group also. Then, we want to know from the hon. Minister of External Affairs as to what is our stand on the G-20 process, G-8 Plus, G-5 Summit and we also want to know as to what actually transpired in the Climate Change Conference in Copenhagen.

So, we are of the firm opinion that the Government of India is trying to build India as a country who have no alignment with any force and India, shining through this Ministry, will certainly come up in the world.

MR. CHAIRMAN : Shri A. Sampath – Not present.

Shri Pinaki Misra.

SHRI A. SAMPATH : Mr. Chairman, Sir, I have come and I can speak now.

MR. CHAIRMAN : Since I have taken the name of Shri Pinaki Misra, he can speak now and you can speak after him.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for giving the Biju Janata Dal an opportunity to participate in this very seminal, very important debate.

Sir, I have heard many of the distinguished speakers who preceded me with a great deal of interest. This is a discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of External Affairs for the year 2010-11. What I have heard here is a lot of lyrical prose. A lot of speakers have waxed eloquent about the pros and cons of our Foreign Policy. Unfortunately, very little attention has been given to the nuts and bolts in terms of the facts and figures that go into budgetary allocation and, with your permission, Mr. Chairman, I would like to draw the attention of this House to some of those important aspects.

Sir, phrases such as 'emerging global power at the international high table' is very high sounding, but it has to be looked at in the backdrop of the figure of 35 per cent of our people living below the poverty line which is now the order of the day. I am sorry I am not one who is prone to say that we must wax eloquent about our country regardless of all the ills that beset us because we must present a rosy picture to the international community. If one Ministry's figures are enough to puncture this delusion of grandeur straightaway, that we are players at the so-called International high table that we are a so-called emerging global power, it is this Ministry's figures.

16.00 hrs.

Apart from this 35 per cent below poverty line figure, Mr. Chairman, if this House only peruses the facts and figures relating to the Demand which has been put by the External Affairs Ministry, you will see what is the actual position. The actual position unfortunately to quote an unfortunate incumbent of this Ministry who is no longer there is 'cattle-class'. In fact, Mr. Chairman, it is rather 'cattle-like'. The word 'class' is a misnomer because it actually does not have any class. There is a remarkable lack of class in the facts and figures.

Mr. Chairman, I will tell this House straightaway, why? Kindly see, in these figures, there is an observation made that during each financial quarter of the Financial Year 2009-10, during the first three quarters of the year, only Rs.3,983 crore were spent against an estimate of Rs.6,333 crore. Just about 50 per cent was spent in three quarters of the year. Just a little less than 50 per cent, about 47 per cent or 48 per cent allocation is to be spent in the last quarter.

Why has this remarkable situation obtained? This obtains for a very extraordinary reason. It is because the Ministry which waxes eloquent about spreading e-commerce and e-technology the world over is supposed to be integrated with what is known as the Integrated Mission Accounting System which is known as the IMAS. As on date, not more than 50 of our Missions or Posts abroad are linked with this. The rest are still travelling cattle class. The rest are still not connected. So, they do not get the figures till the last quarter and therefore, there is a rush to spend between 28th of February and 31st of March and 40 per cent gets spent in the last month. This is the manner in which the Ministry of External Affairs wishes to conduct its affairs in this era of technology.

16.02 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

Mr. Chairman, Sir, apart from this, kindly see that we are supposed to be pioneers the world over in what is known as I-TEC and this is again one of the significant things this Ministry is supposed to be doing which is that it is providing technical aid, which is mainly focussed on the IT sector and capacity building of the personnel under international technical and economic cooperation programme, that is the I-TEC Programme. With great respect, this is high sounding vain glarious verbiage and that is the only way I can describe it, when less than 50 per cent of the Missions are connected with e-technology abroad. I cannot understand where this comes from.

Mr. Chairman Sir, let me give you one more example. There is what is now in the West universally regarded as the virtual *sine-qua-non* of a developed nation, which is you have a biometric or an e-passport. In the Annual Report of 2008-09 it was stated that based on the experience gained from a pilot project done earlier e-passports of ordinary category would be issued by 2009. Mr. Chairman, that technical committee, till today, has not frozen the technical specifications. So, when we go abroad, we travel with a cattle class passport and we have to spend hours therefore in queues abroad because of our cattle class passport.

Mr. Chairman Sir, a large part of the outlay of the External Affairs Ministry goes in developmental projects because that is how we are supposed to spread our influence worldwide. Let me give this House a little sample of what we do abroad. The Tala-hydro-electrical project in Bhutan – I will show to this House why Bhutan is critical to India – is the only plan project that has recently been completed. The detailed project report cost of Tala was Rs.1,048 crore at 1993 price levels.

This was revised to Rs. 3580 crore in September, 2002. Do you know what the final completion cost, Mr. Chairman, was? This House would be aghast to learn that the final completion cost has been Rs. 4125 crore. So from Rs. 1048 crore, it has gone up four times to Rs. 4125 crore. And we have a projected development axis in Bhutan of 10,000 MW by 2020. With great respect I have to tell the House that at this rate, we are going to be bankrupt helping Bhutan.

It is not Bhutan alone. Let me just take this House into confidence as to what has happened in Nepal. In 2005, the Government of India and the Government of Nepal signed an MoU for what is known as the implementation of various projects in Nepal. No headway has been made till date. I will tell this House what China has done in the meanwhile, what Pakistan has done in the meanwhile in Nepal. In Sri Lanka, these figures – to my friends from the South, particularly from Tamil Nadu – are startling. The Government of India has made various commitments to provide aid for relief, rehabilitation, and reconstruction of war-affected people and areas in Sri Lanka. The Standing Committee has noted that against the announcement of assistance of Rs. 500 crore, only Rs. 90 crore have been budgeted and Rs. 63 crore have been utilized. This is the state of Sri Lanka. The Members from the Treasury Benches are sanguine. They continue to wax eloquent about India's great role as a global superpower, that we ought not to be too worried about this increasingly hostile neighbourhood that we are encircled with. I do not know which world they are living in, Mr. Chairman, but, this side of the benches, I think, we tend to be a little more realistic.

I really urge this House that at some point this House should pass a resolution that a large geo-political map of this part of the world should be placed not just in every MP's homes but every officer's home whether it is the MoD, MEA, MHA or any other critical Ministry, because, otherwise – hon. Members here are laughing – I cannot understand how hundreds of thousands of crores of Defence money is returned unutilized every year. How money of External Affairs Ministry is returned unutilized, I cannot understand. They must get up in the

morning, have a look at that map, and see how India is being increasingly encircled from all sides.

Mr. Chairman, I want to tell this House that today there is 350 km. per hour trains running on railway track which is up to Lhasa. China is going to increase it up to Hotan. From the north, they are encircling us from Urumqi to Kashgar. As the hon. Member Dr. Murli Manohar Joshi said, it is going down the Karakoram Highway all the way down to Gwadar. Today, for China, to bring in troops at 24 hours' notice, where it will take us 24 days if not 24 weeks to mobilize troops and to mobilize the requisite armoury, is a matter of actually hours if not minutes.

Mr. Chairman, you can see, I am not going to waste the time of the House waxing eloquent; I am giving facts and figures. The moment you tell me my time is actually over, I will sit down because I am a lawyer; I do not extend time beyond what is actually permissible. So, you have to tell me exactly what you feel your mind is; if you want me to sit down, I will sit down because I do not like the bell ringing again and again.

MR. CHAIRMAN : One minute more.

SHRI PINAKI MISRA : Sir, kindly give me two or three minutes.

MR. CHAIRMAN: Two minutes I will give you, please.

SHRI PINAKI MISRA : There are other tired aspects, frankly. I want to bring to the notice of the House, for instance, IDCA. It is a very significant thing that this Ministry would have done. It is the India International Development Cooperation Agency. This was started in 2007-08; now it has been scrapped. This would have been a very important vehicle as far as spreading our influence abroad is concerned. There are two other ways in which we ought to be able to spread our influence. One is the Public Diplomacy Division which unfortunately functions in the most tired way possible, and of course the ICCR which again, we have seen apart from a few cultural programmes a few junkets abroad, is a most tired organization. These are not organizations that can take on the might of all the *madarsas* that are dotting the skyline in Nepal, of all the extraordinary amount of

foreign policy initiatives taken by think-tanks in China. This is not an answer, Mr. Chairman.

Mr. Chairman, Sir, I just want to draw the attention of this House to another very important organisation because this is the Ministry of Overseas Affairs which is included as a part of the debate, I would assume. This was the Ministry which was started in 2004 by the Congress Party because they wanted to rehabilitate somebody who, I think, could be rehabilitated in no other place. So, they carved out this Ministry. That gentleman has been divested of his portfolio but this Ministry remains. I do not understand what this Ministry does because this Ministry works through the External Affairs Ministry.

Forget about the PIOs, OCDs and all these. Really this Ministry has now become a playground of influential people like Sant Singh Chatwal. So, that people of dodgy backgrounds are is given some sort of sanctity by this Ministry.

Sir, I come from Puri parliamentary constituency where there is an Assembly segment called 'Banpur', where hundreds and thousands of people are languishing in the Middle East without succour. They are exploited by ruthless agencies, by ruthless employers, by hostile governments, by a hostile milieu. If this Ministry is to function at all, it can do one thing, which is open up a single window grievance cell in many of these areas abroad where we have a very large Indian labour class. The Sant Singh Chatwals do not need this Ministry. The Sant Singh Chatwals have the Clinton's wine and dine to them. The people who need this are the very poor and they are the very marginalised people. Very importantly, it must have a dedicated legal service. That is the most important thing that they need. This Ministry must have a dedicated legal service, which will provide, free of cost, the legal facility needed for them to be able to at least return home without being in a coffin. That is the most important thing, Mr. Chairman.

I am summing it up. I have seen the way particularly the Standing Committee on External Affairs functions, which is manned by its very able

Officers. They are vastly competent officers, and there is no question about that. Some of them are sitting here. Very vastly competent Officers are manning it.

I can only say, and with a great deal of regret, that what this Ministry has lacked unfortunately from the beginning of UPA-I is the political leadership. Starting with Shri Natwar Singh, who had to resign in disgrace and ending with Shri Tharoor, who had to resign in disgrace, I am very sorry to say that this Ministry has not had the requisite political leadership, and which is why, I think, this Ministry is languishing in the manner it is. I am deeply sorry to have to say that.

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महोदय, मैं विदेश मंत्रालय के अनुदानों की चर्चा और मतदान के लिए शिव सेना की ओर से खड़ा हुआ हूं। विदेश नीति के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे विदेश मंत्रालय को उठाने चाहिए, मैं उनके बारे में कुछ कहने वाला हूं। हिन्दुस्तान के नागरिकों का ध्यान विदेश मंत्रालय की तरफ है, हम सफलता पाते हैं और इसके बारे में चर्चा रोज होती है। हम जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर, भारत-चीन संबंध, पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले हादसों के बाद किस तरह का संबंध होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं, इस संबंध में सरकार ने क्या मदद की है। अफगानिस्तान में भारत के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स गए हैं, उन पर भी आक्रमण हुआ है, मंत्री जी हमें बताएं कि हमारे संबंध अफगानिस्तान से अच्छे हो रहे हैं या नहीं। ब्राजील, रशिया, यूएसए, चीन के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, इसके बारे में हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे। यूएसए ने दबाव तंत्र से न्यूक्लियर डील की और इसी कारण हम उनके दबाव में रहते हैं। 14वीं लोकसभा में सिविल न्यूक्लियर बिल जिस तरह से पास हुआ, वह ठीक नहीं रहा लेकिन आज भी हम लोग उनके दबाव में हैं। मैं चीन के बारे में कहना चाहता हूं और आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी ने भी कहा कि हमें गंभीर रूप से चीन के बारे में सोचना चाहिए। चीन आगे जाना चाहता है, जो वर्ष 1962 में हुआ था वह आगे कभी भी हो सकता है। हमें चीन के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अरुणाचल भी उनका मुद्दा है, उनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती होती है। हिन्दुस्तान पर अटैक करने की बात पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, हमारे देश में जो हादसे होते हैं, उनके बारे में भी सोचना होगा। इनके साथ संबंध कैसे होने चाहिए, इसके बारे में भी गंभीरता से सोचना होगा। यह अनुदानों की मांग तो ठीक है। लेकिन विदेश मंत्रालय के शेष संबंध कैसे होने चाहिए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

महोदय, मैं पाकिस्तान के बारे कहना चाहता हूं कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो 13वीं लोक सभा में मैंने एक वक्तव्य लोक सभा में दिया था कि पाकिस्तान के साथ कभी भी कोई संबंध मत रखिये। चूंकि पाकिस्तान जिस तरह से हादसे कराता है, दाऊद और लादेन जैसे लोग उनके यहां छुपे हुए हैं और पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेन्सी के माध्यम से कहीं भी हादसे करा रहा है। पुणे में जर्मन बेकरी पर जो हमला हुआ। उसमें आरोपित हैडली कहां गया, कैसे आया, उसे कैसे पासपोर्ट मिला? आपको इस पर भी विचार करना चाहिए। हैडली जैसा आदमी यहां आ जाता है। हमारे शिवसेना भवन के पास जाता है। वह मुम्बई में कई जगहों पर गया। उसे एन्ट्री कैसे मिली? क्या उसके ऊपर हिंदुस्तान की कोई खुफिया नजर थी या नहीं? तब हमारा आई.बी. कहां गया था? मैं समझता हूं कि हमें पाकिस्तान की नीति के बारे में ही सोचना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि मुम्बई में इतना बड़ा हादसा हुआ, 26/11 को लगभग 200

लोग मारे गये। उसके पहले भी मुम्बई में और देश में जो हादसे कराये जा रहे हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुए हमें पाकिस्तान के साथ कभी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। यह मेरा और हमारी पार्टी शिवसेना का दृष्टिकोण हैं और शिवसेना प्रमुख श्री बालासाहब ठाकरे भी वही कहते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी कुछ समय से हादसे नहीं हुए हैं, यह उनका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य है। लेकिन हादसे कभी भी हो सकते हैं। पुणे की जर्मन बेकरी के हादसे के बाद अभी कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन हादसे होने के बाद हम लोग पहले की तरह पाकिस्तान के ऊपर दो दिन लोक सभा में चर्चा करेंगे और बाकी बयान दे देंगे। लेकिन मैं आज भी उसी बात को दोहराता हूं कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्री से इसके बारे में मांग करता हूं कि उन्हें इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए और हमें पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। हमें उनके खिलाड़ियों के साथ भी खेलना बंद करना चाहिए, उनके खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान में आकर खेलते हैं। आज आईपीएल का क्या चल रहा है। अभी लोक सभा में दो दिन उसी पर बहस चली है। लेकिन ऐसा भ्रष्टाचार करके पैसे जमा करना और बाद में आतंकवादियों को मदद पहुंचाना, यह गलत बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से विदेश मंत्रालय को बताना चाहता हूं कि आज आस्ट्रेलिया में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। मेरे यहां का एक बच्चा आस्ट्रेलिया गया। उसके पिताजी यहां एक पुलिस ऑफिसर थे, उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके लड़के ने होटल मैनेजमैन्ट का कोर्स किया था और वह आस्ट्रेलिया जाना चाहता था। उसकी विडो मां ने लोन के लिए एप्लीकेशन दी। उसने मुझे भी बोला और मैंने खुद बैंक में जाकर उनका 25 लाख का लोन सैंक्शन भी करवाया। लेकिन आज उस लड़के को वहां से मारकर निकाल दिया गया है। अब उसके 25 लाख रुपये कौन भरेगा? हमारा विदेश मंत्रालय क्या करता है? हमारे देश के बच्चों के साथ वहां मारपीट हो रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां की सरकार बोल रही है कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं हो रही है और हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां यहां से जो भी बच्चे जाते हैं, वहां के लोग उन्हें देख-देख कर मारते हैं। चाहे वे ड्राइवर हों, डाक्टर हों या कंप्यूटर इंजीनियर हों, उन्हें वहां मारना चालू कर दिया। मैं समझता हूं कि जैसा पाकिस्तान के साथ व्यवहार है, वैसा ही हमें आस्ट्रेलिया के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं विदेश मंत्री से इसकी डिमांड करता हूं।

महोदय, इसके बाद मैं अपने क्षेत्र की डिमांड के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे महाराष्ट्र में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मुम्बई में है। महाराष्ट्र से बहुत सारे बच्चे विदेशों में गये हैं, चाहे वे कंप्यूटर इंजीनियर्स हों

या अन्य प्रोफेशनल्स हों। उन्हें पासपोर्ट मिलने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, चूंकि वहां से फोलो अप हो जाता है, इसलिए उन्हें पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन यह प्रोसैस काफी लम्बा पड़ता है। बहुत से बच्चों की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, वे गरीब होते हैं। मेरा क्षेत्र सम्भाजीनगर, औरंगाबाद मराठवाड़ा की राजधानी है। वहां पहले हम लोगों ने एक छोटा सब-रीजनल ऑफिस खोला था। आज मैं आदरणीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे यहां मुम्बई हाईकोर्ट की बैंच भी है। हमारा क्षेत्र डिविजनल प्लेस है। हमारे यहां सब रीजनल ऑफिसेज भी हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि हमारे यहां मराठवाड़ा के आठ जिलों के लिए और खानदेश के जिलों के लिए भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का सब-रीजनल ऑफिस सम्भाजीनगर, औरंगाबाद में खोलें।

आपके भाषण में यह मुद्दा आया था कि पासपोर्ट के करीब 80 हजार तक एप्लीकेशंस पड़े हैं, ऐसा आपने बताया था, लेकिन मैनपावर नहीं है। मैं यह कहूंगा जैसे कि आज अनुदानों की मांग हो रही है तो हमारे यहां पासपोर्ट ऑफिस के लिए मैनपावर हो। मैं एक्सटर्नल कमेटी में 13वीं लोक सभा में था तो सब लोग कह रहे थे कि उनके पास स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ न होने के कारण से उनकी स्क्रुटनी नहीं होती है, इसलिए बच्चों को प्रोबलम होती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में पहले जो ऑफिस खोला था, उसे दोबारा अच्छे स्वरूप से, पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारे यहां सब-डिवीजनल ऑफिस खोला जाए। जो विदेश नीति चल रही है, आपको पता है कि जैसे आस्ट्रेलिया में बच्चे जा रहे हैं, लेकिन ओबामा जी के बनने के बाद में उन्होंने कहा कि नो आउट सोर्सिंग, मतलब हिन्दुस्तान के बच्चों के लिए, बाकी अन्य जगह के बच्चों के लिए एंट्री नहीं है। अभी थोड़ा सा कुछ ठीक हुआ है, उन्होंने मंदी की लहर के कारण से भी बोला होगा। आज हम लोग कहां जाएंगे, इसके लिए यूएसए, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में आप अपने विचार स्पष्ट करिए और पाकिस्तान के साथ में किसी भी हालत में दोस्ती न रखिए। उनके खिलाड़ी भी यहां नहीं खेलेंगे, यह मैं आपके माध्यम से अपनी मांग रखता हूं।

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, I would try my best not to repeat any points that have been raised by my learned friends and seniors in this august House.

I would like to seek a clarification from the hon. Minister. What is the exact number of Indians living and working outside India? It is because it is a bit confusing when I go through the Annual Report of the Ministry of External Affairs. On page nine of the Introduction and Synopsis, it says that it is five million in the gulf region. In the same book, on page 42, it says that it is about 4.5 million. But when I went through the Annual Report of the Ministry of Overseas Indian Affairs, there is a mention there. But it says of overseas Indian community. It begins with, "The overseas Indian community spans the globe with their presence in 189 countries across the world, estimated at over 25 million." It says so. Whatever be the data, I doubt that. Even now our Government is going on with the guesstimates. Guess work plus estimates equal to guesstimates.

This is not fair because as per the Reserve Bank of India, the total private remittance from abroad in 2008-09 was 46.9 US billion dollars. Of this, 30 billion dollars came from the Gulf region. I am coming from a State from where more than three million people have gone abroad, especially to the Gulf region, to earn a livelihood.

We believe that it is the duty of the Ministry of External Affairs to protect the interests of those who are working abroad and living abroad. If one holds the passport of Indian Republic, it is the signature of the sovereignty of India. But may I know how many officers and how many staff members are working in those countries? The Ministry of External Affairs itself admits that the officers, the IFS officers, who know the foreign languages, their number has to be increased.

My State is very near to a country called Sri Lanka. There, only one IFS Officer is expert in Sinhalese. I would like to raise a point. How many officers of the Indian Embassies and Missions abroad know the regional languages of the majority of the people who speak those regional languages? If the people who speak Malayalam, Tamil, Kannada and Telugu approach an Indian Embassy, there would be nobody to look after their affairs because the language they speak sounds Greek to the officers. It is just like a migrant worker is always a migrant worker. Our nation needs their money. The banks are happy; the Government is happy because of the remittances. But they do not want them – 'you please do not come here; please do not come back; you send your money for ever; but you do not come back'.

The exploitation starts from the very moment one gives an application for the passport. Even now we have only 37 Passport Offices. I am coming from a district called Thiruvananthapuram, the northern part of it is my constituency. By profession I am a lawyer. Very near to my lawyer's office, everyday I see mothers with their new born babies in the queue in the Passport Office in the capital city of Kerala. Then what would be the picture in other places? Hundreds of people under the scorching heat stand in the queue to give applications. There are no minimum facilities for them. Previously one thousand passports were issued per day. Now it has come down to 300 or 350. The Government of India itself says that. The revenue generated from issuing of passports and visas is to the tunes of more than Rs.600 crores and Rs.900 crores respectively. So, it is a milking cow. My humble request to the Government is, please do not milk it till it bleeds. They are the poor people who do not get any jobs here. They are our brothers and sisters who are going abroad. They are exploited by the Passport Officers, passport officials, the touts, the travel agents and even the national careers.

Our Airlines are saying that they are in loss. But, from where do they get the maximum revenue? Is it from the New York sector, is it from the Europe sector? No. They get the maximum revenue from the Gulf sector. But the Government should give justice to them.

Today we all have read a newspaper article, a statement by the Chief Election Commissioner. There was a cry for long years. All the political parties support that our brothers and sisters living and working abroad should be included in the electorate and should be given the voting right. If the data is correct and suppose the guesstimate is right and cent per cent correct, then more than 50 lakhs of people are losing their right to vote. Is it fair?

I would like to invite your attention. I was a bit lucky to get a point raised under Rule 377 in this august House regarding the creation of a fund and establishment of a welfare scheme for the Non-Resident Indians. I got a curious reply from the Ministry of Overseas Indian Affairs. It is dated 21st August 2009. I shall read out only the relevant paragraph:

> "This Ministry had earlier requested the Finance Ministry for making a budget allocation of Rs.100 crore in the current financial year for setting up of a contributory pension scheme for the welfare of the overseas Indian workers and their families. However, this was not included in the budget proposals."

So, it is just like saying give us the money. Not even a single penny is being earmarked for their welfare.

But, I am proud. I am coming from a small State which is not rich. That Government has enacted a law. … (*Interruptions*) Sir, I am concluding within three minutes.

Sir, 18th of December is the International Day of the Migrant Workers as per the call of the International Labour Organization. In the year 2008, the Legislative Assembly of Kerala has unanimously passed a Bill and now a welfare fund has come into existence giving pension, accident relief, maternity benefit,

loans for house construction, loans for the studies of the children etc. Even though it is a very humble beginning, it is a model.

Next to China, we have the largest population and next to them we are sending the maximum number of people outside, abroad to work. But we should at least show some mercy to our brothers and sisters. I would say that it is their right that we are denying them. A small nation like Philippines is working much better than us. There should be coordination between the Ministries of External Affairs, Overseas Indian Affairs, Home, Finance, Commerce, Labour etc. But, I do not see such coordination. Everyday we receive many complaints from the relatives of the people who are working abroad. Of course, I understand that this is a very complex issue. We all know that whenever a diplomat says 'yes' definitely there will be a 'no' and whenever the diplomat says 'no' there will be a 'yes' also to it.

Sir, with your permission, I have certain points to raise here which I would like to bring to the notice of the hon. Minister also. You please give more aircraft more services to the passengers going abroad and those who are coming back. Secondly, you open more passport offices. Thirdly, you provide sufficient number of staff to the passport offices. Fourthly, give sufficient number of staff and officers to the Indian Missions abroad and fifthly open the help desks there and ask them to work 24 hours a day because now 20 per cent of the workforce going abroad consists of women. Now, not only men but 20 per cent of women – without any women's reservation – are going abroad. They are working there and they are sending the money to this nation. We are getting the precious foreign exchange. But we should know that we have to save their precious lives and we have to honour their dignity of life.

I am concluding. In this House, some discussions have taken place in the last Session and before that also. There have been certain statements by various Ministers at various places which have created certain confusions and made the situation more complex. The foreign affairs is not a private matter. It is a matter of concern even to the public. Everybody should know. You see what has happened.

MR. CHAIRMAN : Kindly conclude. You have taken lot of time.

SHRI A. SAMPATH : I am going to conclude. I am one of the most obedient Members. I am going to conclude.

MR. CHAIRMAN : Do not be obedient; but conclude.

SHRI A. SAMPATH : Take the Indo-US Nuclear Treaty. My Party was deadly against it. Today there is a news. While we are assembling here and discussing about the Demands for Grants of the External Affairs Ministry, there is a news that the US Congress is not going to honour it as per what the Government of India has expected. There are some provisions which are different. The reprocessing of the fuel spent is going to be a problem. What we think is different than what they think. We all know that it is a race of cat and mice. It depends as to who is the mice and who is the cat.

Some of the hon. Members have raised some very valuable points. We have to fight the terrorism in our land. It is our duty. At the same time, we have to protect the integrity of the nation. While we are doing our duty, we should not forget that we are one of the founding fathers of the Non-Aligned Movement. But, it is a pity to see that now we are at the end of somebody else's wagon. If it is the United States of America which is now giving directions to India and if we are going to play the second fiddle to the US aspirations and the US interests, that will not be tolerated by the people of India. This country has to take another path. Definitely we have to appreciate and we have to strengthen the BRIC. We have to strengthen the relations with the Third World countries. The future is not for a unipolar world and India has a role to play and we have to fulfil that. It is what the time and history have asked us to do.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा, जिसे माननीय जोशी जी ने प्रारंभ किया, उस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। विदेश मंत्रालय एक आम मंत्रालय है और यह अपेक्षा होती है कि हमारी विदेश नीति जहां अपने विचारों से जुड़े हुए सांस्कृतिक संबंधों को आस-पास के क्षेत्र में मजबूती के साथ प्रस्तुत करे, वहीं अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक सफलता के माध्यम से विश्व धरातल पर अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज करे। यूपीए सरकार की वैदेशिक नीति हम लोग पिछले छ: वर्षों से अनुभव कर रहे हैं। यह लगता है कि उन्होंने विदेश नीति को केवल एक वैचारिक कल्पना तक सीमित रखा है। आस-पास के क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और इस देश में जो घटित हो रहा है, उससे कभी नहीं लगता कि यूपीए सरकार की वैदेशिक नीति एक सम्प्रभुता सम्पन्न और विश्व के उभरते हुए शक्तिशाली भारत की विदेश नीति है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उसका अवलोकन करें, तो कहीं नहीं लगता कि यह सरकार अपने आस-पास के जो पड़ोसी मित्र राष्ट्र हैं, जो सांस्कृतिक रूप से भारत के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उन सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सरकार कहीं भी प्रतिबद्ध दिखाई नहीं देती।

महोदय, नेपाल हम सबका एक निकटतम पड़ोसी राष्ट्र रहा है। आज भी है। नेपाल के बारे में कहते हैं कि शरीर दो है लेकिन आत्मा दोनों के अंदर एक है। एस सांझी सांस्कृतिक विरासत, एक सांझी परम्परा है। लेकिन इस सबके बावजूद आज नेपाल भारत से दूर क्यों? नेपाल का भारत से दूर होना इस सरकार की विदेश नीति की विफलता है। चीन को हस्तक्षेप करने का यह सरकार पूरा अवसर दे रही है। यह वही यूपीए सरकार है जिसने नेपाल के मूल चरित्र के साथ खिलवाड़ करके नेपाल के अंदर उन माओवादियों को, जिसका दंश आज भारत सर्वाधिक झेल रहा है, उन माओवादियों के हाथों में वहां की सत्ता सौंपी थी। वे माओवादी आज भी भारत को लगातार चुनौती दे रहे हैं। भारत के अंदर नक्सलवादियों को सीधे-सीधे प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत के नक्सलवादियों और नेपाल के माओवादियों में एक संबंध है। लेकिन केवल इस बात की चिढ़ कि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिन्दु राष्ट्र है और हिन्दु अधिराज्य के रूप में उसे इस बात की सजा दी जाए, संभवत: और अपना एक नया दुश्मन वहां आने के लिए प्रेरित किया जाए, नेपाल उसका एक उदाहरण हो सकता है।

महोदय, भारत की 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगी हुई है। उस सीमा की स्थिति बारूद के ढेर जैसी है जो कभी भी सुलग जाये। वहां कोई सुरक्षा की स्थिति नहीं है, क्योंकि दोनों की सीमाएं खुली हैं। लेकिन सरकार ने उसे कभी भी गंभीरता से नहीं लिया है। चीन लगातार वहां हस्तक्षेप कर रहा है। चीन को वहां पर अपनी हर प्रकार की गतिविधियों को चलाने की पूरी छूट सरकार दे रही है। लेकिन अनुदान की मांगों में नेपाल के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ हम नेपाल को हर प्रकार की सहायता दे सकें, इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। यह केवल नेपाल ही नहीं, मुझे लगता है कि आज के दिन भूटान को छोड़ दिया जाये, तो कोई भी देश भारत के साथ मजबूती से नहीं जुड़ा है। उतने मधुर संबंध किसी भी देश के साथ नहीं हैं। भूटान की बहुत बड़ी व्यवस्था भारत द्वारा संचालित होती है। भूटान में उल्फा के जो कैम्पस थे, उन्हें एनडीए सरकार के समय नष्ट किया गया। एक शुरूआत हुई थी कि पड़ोसी देशों के अंदर आतंकवादियों के, उग्रवादियों के जो कैम्पस चल रहे हैं, उन्हें नष्ट किया जाये, लेकिन वह भूटान तक सीमित रहा। बंगलादेश ने उन्हें समाप्त नहीं किया। नेपाल के अंदर नये-नये कैम्पस प्रारंभ हो गये हैं। आज भारत में नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों के एक नये केन्द्र के रूप में उभरा है। चाहे जाली करेंसी को भारत में लाने का मामला हो, चाहे चीन के इलैक्ट्रानिक आइटम्स को भारतीय बाजार में लाने का मामला हो, चाहे माद्रक द्रव्यों की तस्करी का मामला हो या इस देश के अंदर जेहादी आतंकवादियों को भारत में किसी भी स्थान पर पहुंचाने का मामला हो, भारत और नेपाल की इस खुली सीमा के माध्यम से वे तेजी के साथ भारत में घुस रहे हैं। वे कराची से काठमांडू और काठमांडू से भारत के अंदर किसी भी सीमा में कहीं भी घुस सकते हैं और उनकी शरणस्थली भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो कुछ केन्द्र उगे हुए है, जिनके प्रति आज भी सरकार मौन बनी हुई है, मूक बनी हुई है, उन जेहादी आतंकवादी केन्द्रों में वे सीधे से शरण पाते हैं। लेकिन कभी भी उनको रोकने का कोई प्रयास न भारत सरकार ने किया और नही नेपाल पर इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि वह उसे रोके। इसका कभी भी प्रयास नहीं हुआ।

महोदय, आज कौन से देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं? हम लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर म्यांमार के साथ अपने पूरे संबंध विच्छेद कर दिये, समाप्त कर दिये। वह चीन के पास चला गया। चीन तेजी के साथ वहां पर अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। चीन ने वहां पर अपने केन्द्र स्थापित किये हैं। चीन की सेना का पूरा हस्तक्षेप आज म्यांमार में है। बंगलादेश में सरकार के आने-जाने पर निर्भर करता है कि भारत के अंदर संबंध किस रूप में होने चाहिए। लेकिन बंगलादेश में कोई भी सरकार हो, आतंकवादी कैम्प्स आज तक समाप्त नहीं हुए। हूजी के कैम्पस समाप्त नहीं हुए। लश्कर-ए-तैयबा के कैम्प्स वहां समाप्त नहीं हुए। लगभग साढ़े तीन करोड़ की संख्या में जो बंगालदेशी शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, उन्हें वापस

बंगलादेश भेजा जा सके, इन मुद्दों को विदेश मंत्रालय ने कभी भी मजबूती के साथ बंगलादेश के सामने नहीं रखा या बंगलादेश को कभी भी इस बारे में अवगत नहीं कराता कि वह अपने इन अनचाहे मेहमानों को अपने देश वापस ले जाओ। कभी भी इस बारे में नहीं रखा गया। उसी प्रकार से श्रीलंका की स्थिति है। श्रीलंका के साथ हमारे संबंध आज से नहीं रामायण काल से हैं। लेकिन श्रीलंका ने जब लिट्टे के आतंकवादी मनसूबों को ध्वस्त करना चाहा, तो उसने भारत से मदद नहीं मांगी। वह चीन की मदद के लिए लालायित था, वह पाकिस्तान से मदद के लिए लालायित था। वह भारत से पूछता नहीं है। आज श्रीलंका के अंदर हजारों की संख्या में तमिल भारतीय मूल की महिलाएं विधवा हैं। उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पा रही है, ईमानदारी से नहीं कर पा रही है। उसी प्रकार से पाकिस्तान और चीन, ये दो भारत के जग-जाहिर दुश्मन हैं और दुश्मन के रूप में उन्होंने हमेशा अपनी भूमिका का उसी रूप में निर्वाह भी किया है। लेकिन लगातार भारत को अस्थिर करने की पाकिस्तान और चीन की हर साजिशों को, हर उन गतिविधियों को नजरअंदाज करने का प्रयास यह सरकार कर रही है।

राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में बहुत से ऐसे देश थे जहां भारत सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से उनके साथ एक आत्मिक संबंध स्थापित कर सकता था। मैं थाईलैण्ड गया था, वहां भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि थाईलैण्ड के राजा आज भी अपने को भगवान राम के वंशज मानते हैं। हो सकता है कि इस सरकार को राम से परहेज हो, लेकिन मुझे लगता है कि राम के बगैर यह राष्ट्र नहीं चल सकता है। थाईलैण्ड के अंदर, उन्होंने अपने सभी नेशनल हाइवेज के नाम राम के नाम पर रखे हैं। वहां के राजा ने अपने ग्रैण्ड पैलेस को रामायण को डोनेट किया, रामायण की चौपाई से, रामायण के चित्रों से पूरा भवन भरा हुआ है। थाईलैण्ड की पुरानी राजधानी, जिसे आज भी वे अपनी सांस्कृतिक राजधानी मानते हैं, उसका नाम अयोध्या रखा गया था। यह मान्यता भारत के प्रति उनके सम्मान के भाव को दर्शाती है। हम इसके माध्यम से उनको अपने साथ जोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

कंबोडिया में अंकोरवाट का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। वहां अंकोर कांप्लेक्स में हजारों मंदिर हैं, उन मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम हो सकता था, इसके लिए मदद देकर भारत अपने सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से आत्मीय संबंध स्थापित कर सकता था। हमें दुख हुआ कि जापान की मदद से बनने वाला मंदिर वहां पर तेजी के साथ बन रहा है, कोरिया की मदद से बनने वाला मंदिर वहां पर तेजी से बन रहा है, लेकिन भारत की सहायता से बनने वाले मंदिरों के जीर्णोद्धार की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उनकी अत्यंत खराब स्थिति थी। हम लोगों को यह देखकर दुख हो रहा था कि जिसके लिए भारत को वहां मदद देनी चाहिए, जिसके मदद से अपने सांस्कृतिक संबंधों को यहां स्थापित किया जा सकता था, भारत सरकार

उसके प्रति पूरी तरह अनभिज्ञ है। इसी प्रकार से मलेशिया में, इसी सरकार के समय में भारतीय मूल के, तमिल मूल के तमाम नागरिकों पर अत्याचार हुए, उनके पुराने धर्मस्थल वहां तोड़े गए, उनको वहां से अपमानित करके भगाने का प्रयास हुआ, लेकिन सरकार मौन बनी रही। इस सरकार ने तब भी कुछ नहीं किया। मलेशिया से हम अपने संबंध स्थापित कर सकते थे, इंडोनेशिया के साथ संबंध स्थापित कर सकते थे, सिंगापुर के साथ उन सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सकते थे, लेकिन हमारे वैदेशिक नीति की विफलता आज चीन को मजबूती के साथ उन देशों में हावी होने का अवसर दे रही है। वहां चीन मजबूती के साथ हावी हो रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude. There are a lot of speakers who are yet to speak. Please take only one more minute to conclude. After that, I will call another speaker.

योगी आदित्यनाथ : यह सरकार वैदेशिक नीति के माध्यम से इस राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है अमेरिका का पिछलग्गू बनकर। विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों में यहां कुछ बातें आई हैं। हज के नाम पर पैसा दिया गया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जाते हैं। अगर हज सब्सिडी आप देते हैं, हज यात्रियों को हज यात्रा के लिए अनुदान देते हैं, सहायता देते हैं, उनके लिए स्पेशल टर्मिनल बनाए जाते हैं, तो कैलाश-मानसरोवर की यात्रा के लिए जो तीर्थ यात्री जाना चाहते हैं, उन्हें ये सुविधा क्यों नहीं प्राप्त होती है?...(व्यवधान) उन्हें इस प्रकार की सुविधाएं क्यों प्राप्त नहीं हो सकती हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please sit down.

योगी आदित्यनाथ : इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर हज यात्रियों को आप अनुदान प्रदान करते हैं तो कैलाश-मानसरोवर के साथ-साथ इस देश के अंदर तमाम यात्राएं चलती हैं, उनके लिए अनुदान और सहायता देकर इस देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं के साथ न्याय होना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude. You have made your point.

योगी आदित्यनाथ : इसी तरह जो सिक्ख बन्धु तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, जैसे अभी बैशाखी के अवसर पर ननकाना साहिब गए थे, उन लोगों को अनुदान क्यों नहीं प्रदान किया जाता है? उन्हें भी इस तरह से अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार इस तरह के दोहरे मानक न बनाए। एक विदेश नीति की उपस्थिति मजबूती के साथ हो, उसमें यह दोहरापन किसी भी स्थिति में न प्रस्तुत हो, यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा।

महोदय, नेपाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

नेपाल के साथ गोरखपुर से काठमांडु को जोड़ने के लिए इंडो-नेपाल कनेक्टिविटी में यह तय हुआ था कि नेपाल को, काठमांडु को गोरखपुर और लखनऊ के साथ जोड़ेंग। यह बात एनडीए सरकार के समय तय हुई थी, लेकिन अब इन बातों को भुला दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please conclude. There are lots of speakers. Please conclude in one minute. I will call another speaker.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There is a list of 15 Members to speak. I request you to be very brief. Those who want to lay their speeches on the Table of the House, they may please do so. Hon. Member I am giving you half a minute and thereafter, I will call the next speaker. I have given you too much time.

योगी आदित्यनाथ : सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहता था कि इंडो-नेपाल कनेक्टिविटी में हम अपने विकास की यात्रा को नेपाल तक ले जाएं, उन देशों तक ले जाएं, जो गरीब हैं और हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। जब भारत और नेपाल एक आत्मा और दो शरीर हैं वाली बात है तो क्या कारण है कि नेपाल भारत से दूर जा रहा है। इसलिए इस विषय पर सरकार को विचार करना चाहिए। अभी एक सूचना आई थी कि नेपाल में पुनः माओवादियों को सत्ता सौंपने की तैयारी हो रही है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में वह अवश्य हस्तक्षेप करे। … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Adhir Chowdhury to speak. Nothing should go on record except the speech of Shri Adhir Chowdhury.

(Interruptions) ... *

* Not recorded

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to support the Demands for Grants under the control of Ministry of External Affairs. Under the Demand Number 31, it is sought to defray the charges… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you should understand how should I conduct the House. Not a minute more. I have already called him. Nothing is going on record.

(Interruptions) ... *

SHRI ADHIR CHOWDHURY : This expenditure of the Ministry of External Affairs is of Rs.700 crore for Plan expenditure and Rs.5674.97 crore for non-plan expenditure, that is, totaling to Rs.6374.97 crore.

Indian representation at 168th Mission it also provides expenditure on 30 passport offices and so on. First of all, we should send one message from this august House that India is desirous to have cordial relations with all the members of the comity of nations because it is our civilization, it is our culture, which has never taught us to be hostile to our neighbours. Today's debate was initiated by hon. Senior leader Dr. Murli Manohar Joshiji. He was stating that India has been playing a second fiddle to the US Government. मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, तब उन्होंने चीन का दौरा क्यों किया था, जाहिर है चीन से रिश्ता मजबूत करने के लिए ही किया था। उसके बाद एनडीए सरकार के समय में कारगिल वार हुई थी। उस समय हमारे जवान सरहद पर कारगिल जैसे बर्फीले इलाके में तैनात थे और एनडीए सरकार वाशिंगटन का दौरा कर रही थी। अगर हम कहें कि आप लोग अपना सिर छिपाने के लिए अमेरिका का दौरा कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे?

In diplomatic jargon there are neither permanent friends nor permanent foes. In diplomacy we only put our emphasis on permanent interest.

India's international relations evolved on some core issues. We always focused on our individual interest, on our autonomy, on our developmental priorities and fundamental securities. The most important issues for our country

* Not recorded

are border and territory disputes, Kashmir issue, international rivers, Indo-Pak, Indo-Nepal, Indo-Bangladesh issues, trade and security, cross-border terrorism and smuggling of drugs.

Everybody knows that in spite of all kinds of political opposition, in spite of the ambivalent role of Chinese Government, in spite of the tentative attitude of Nuclear Suppliers Group, India by dint of its diplomatic skills has been able to sign the India-US Civil Nuclear Agreement. I think the first decade of the 21st century will be remembered by the most spectacular success in Indian diplomacy because we have achieved the recognition of all nuclear States in the world.

India is very much a part of the international market for trade of nuclear technology from which she was excommunicated since the peaceful nuclear explosion of 1974. India is now a stakeholder in international security and non-proliferation regime.

During the period of cold war we had hostile relations with China. अगर किसी ने अरूणाचल प्रदेश की मांग की, तो इसका मतलब यह नहीं कि हिंदुस्तान उसे देने के लिए तैयार है। किसी ने मांग की, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे सरेंडर कर चुके हैं। Arunachal Pradesh is a part and parcel of India and that has been steadfastly stated by the hon. Prime Minister of our country. Not only that, all our dignitaries visited the State of Arunachal Pradesh in spite of opposition of the Chinese Government. When Barack Obama feared to meet Dalai Lama, we gave assent to Dalai Lama to visit Arunachal Pradesh. What does it speak of? It speaks of the autonomy of our foreign policy.

बीजेपी के साथ-साथ दूसरे विरोधी दल यहां चाइना फोबिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना हम लोगों को दबाने के लिए आ रहा है और हम घेराबंदी में घिर गए हैं। हिंदुस्तान कमजोर देश नहीं है, जिसे कोई दबाने की हिम्मत करे। बीजेपी को यह बात समझ लेनी चाहिए। With the emergence of complex multi-polar world, try to understand Joshiji, the wall of cold war crumbled; witnessed the resurgence of Asia. India is one of the giants in Asia.

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर कमजोर नहीं है, तो चीन ने जितनी जमीन ले ली है, उसे वापिस लिया जाए।

MR. CHAIRMAN: No crosstalk please. Mr. Chowdhury, please address the Chair.

श्री अधीर चौधरी : हिंदुस्तान गज है। यह गज की तरह चलता है। यह धीरे चलता है, लेकिन हिम्मत से चलता है। जब गज चलता है, तब जमीन कांपती है। हिंदुस्तान किसी से डरता नहीं है।

17.00 hrs.

With the emergence of complex multi-polar world, international politics has entered the context where the rules of the international conduct, issues of technology, multilateralism, environment, terrorism, etc. are getting re-written. This needs to be understood. India exudes remarkable stability and resilience in its political economy and international diplomacy.

Sir, inspite of the collapse of the international financial system, the carnage in Mumbai India has emerged victorious by its dimplomatic manoeuvring we are a country which is maintaining the resilience of our economy. Sir, I would like to quote our hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh ji so that our Opposition can understand the basic tenets of our foreign policy. I quote:

> "Increased competition – internal and external – helps those who are strong enough to benefit from the new opportunities. However, it can hurt those who are ill-equipped to face the challenges of competition. We must adopt concerted measures both at the national and international levels for an equitable management of increased global inder-dependence of nations. At the national level, the State must be modernized to create an environment conducive to creativity and growth and also to ensure that the fruits of growth are fairly and equitably distributed."

India has been growing by its own stature not by the grace of any Superpower because India is destined to be emerged as a Superpower in the generation to come.

17.01 hrs.

(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

I am coming from the State, West Bengal. I am happy that the relations between India and Bangladesh has been strengthening with the passage of time. In this regard, this UPA Government has taken a number of bold initiatives which would help in further strengthening of our relations, which is the need of the hour. In this regard, I would request the hon. Minister of External Affairs that high priority should be given to address the outstanding issues, that is, the exchange of enclaves and adverse possessions, delineation of the outstanding 6.5 kms. of our more than 4,000 kms. long border and construction of flyover that will replace the Tin Bigha corridor, thereby permitting 24-hour access for Bangladesh and the electrification of the Dahagram Angarpota enclave.

Insofar as border line is concerned, every now and then, there creates a short of turmoil and tension in the Indo-Bangladesh border. If we are able to develop more coordination better BDR and BSF, more interaction could be done between BDR and BSF, then, I think, the people who are living in the border area would be much benefited. In this regard, a few years ago, a mechanism was devised, that is, coordinated simultaneous joint patrolling by BDR and BSF at key points along our common border. I want to know as to whether this devise has been implemented, if not, you may try to implement it the border people are suffering from various reasons. BSF people are not proficient in Bengali language. They cannot understand the nuances and complex nature of the local villagers.

Secondly, I would request the hon. Minister to see whether border trade could flourish in the Indo-Bangladesh area because thousands of small, petty middle class traders used to earn their livelihood by trading between India and Bangladesh. If border trade could be developed, then the entire scenario could be changed. I would hope that the hon. Minister will take very special initiatives in this regard. I learnt that during the visit of the hon. Prime Minister of Bangladesh, some sort of discussion had been held in regard to the border trade. If it is held,

then the Murshidabad district which has the largest concentration of Muslim population in the country should be given priority so that they could feel that the neighbouring country, Bangladesh is their friend and we can develop trade between India and Bangladesh.

India, under the leadership of Dr. Manmohan Singh Ji and under the leadership of Madam Sonia Gandhi Ji, has been striding ahead; there is no country under the Sun which is able to make us fear or to intimidate us.

With these words, I am concluding my speech.

*DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR):

There are two UN resolutions no. 1373 and 1267 under which every country is obliged to supports others in the investigation and trial of terror related offences. These resolutions are equally binding on the USA. India and USA already have Extradition Treaty and Mutual Legal Assistance Treaty. Realistically, in the light of all these mutual and international agreements the very commitment of USA is also on test and let an impression not go that "USA is only interested in getting at terrorist groups that harm its interests while showing scant regard for terrorist threats to India". After all the life of an Indian is equally important as is the life of a US citizen. We are getting only mixed signals as to Whether USA will hand over David Headley to India or not. Is there a reluctance to share because ISI would be conclusively exposed. USA needs to be reminded that the war against terror does not admit of any selectivity. Equally on test is the self proclaimed achievement of the UPA Government that we are having very good strategic relationship with the USA.

The Government is seeking to fulfill a hidden commitment to deliver a legislation which safeguards the interests of the United States at the expense of the safety of the Indian people.

INDO-CHINA RELATION

Some salient observations from ground zero are as follows.

(i) 1962, India lost huge tracts of land when the Chinese invaded recklessly occupying major land mass and the bitterness of Nehru's failed Indo-China diplomacy looms large over the Nation. The irreparable loss both in terms of dignity and geographical area remains a black spot post independence. the reminiscences of Nehruian policy are amply visible today, which again eventually may end up costing the Nationa heavily. We fear that the present policies of UPA on China are no different.

* Speech was laid on the Table

(ii) Successive Governments post 1962 and as recent as 1996 turned a deliberate blind eye to frequent incursions and clandestine occupation of stragegic posts and locations in the mountainous Ladakh region.

(iii) Thousands of kilometers of metalled roads on the Chinese side marks a contrast to the abysmal infrastructure both in terms of road communication and other basic logistical facilities. The demoralization on the Indian side is amply visible. The Army & ITBP positioned to man the outposts in one of the most inhospitable terrain find their presence and strength inadequate.

(iv) The disputed border markings, the LAC and the changing contours of Indus River and associated watershed leave enough space for intrusion with forces manning them clueless about government's own stand.

(v) China has devised zero conflict strategy using nomads and grazers to invade pasture lands and g razing grounds inching quietly and providing a discreet protection to their nomads successfully unleashing a virtual creepy invasion.

(vi) Chinese have frequently succeeded in putting a spoke on infrastructure work on the Indian, even as recent as preventing the construction of NREGA road in Demchuk and other areas at high altitude.

(vii) By failing to recognize the legitimate demands of the Ladakh region who simply have no similarity to the state of J&K, the UPA governments has failed to connect to the strong Indianism in the Ladakhis who swear to recover every inch of land lost to China. They today are victims of both Chinese aggression & Indian government's apathy.

(viii) The privacy imposed by the Indian government preventing Indians and other tourist to access the frontiers bordering China without permit which stretches into thousands of miles and lakhs of square kilometer of snowy dessert has kept the region deprived of public interaction. This

has impeded the awareness of common Indian to the ground realities on China front.

(ix) Simply since the Leh-Ladakh region is treated both by MHA, MoD & MEA as non-conflict zone, the presence of the Army & other paramilitary force is miniscule and inadequate. The large tracts of unmanned land spread into thousands of square kilometers leave enough space for intrusion.

(x) The Bhubaneswar Passport Office be upgraded at the earliest.

(xi) Opening the way to Mansarovar from the Ladakh range which was the usual route and path of pilgrimate reduce the visit to mere two days has been left ignored.

Therefore, I demand from Government to take necessary action in view of the above matter.

*SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM):

I would like to to draw the attention of this august House some of the import issues regarding Ministry of External Affairs.

- We should improve our ties with our neighboring countries and the bilateral ties with China, Pakistan, Srilanka, Bangladesh should be strengthened. In this context entire country reiterates our stand that Kashmir is the integral part of the country.
- Our country has been suffering from the terrorist attacks originating from the neighboring country. Our Parliament has been attacked. We should bring these countries to discussion table and convey the message that terrorism will not help any country and we all should work towards development. Thos governments should sincerely work towards this direction.
- After liberalization the country's growth and development is clearly visible to the world. We should work towards a goal where our neighbours should also be partners to this growth. So I call upon the government to further strengthen SAARC.
- "Look East Policy" initiated by Prime Minister Narasimha Rao in 1992 and Dr. Manmohan Singh has introduced our new policy 'look west' to work with Middle East countries like Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and UAE etc.
- The Gulf region, like South-East and South Asia, is part of our natural economic hinterland. We must pursue closer economic relations with all our neighbours in our wider Asian neighbourhood. India has successfully pursued a "Look East" policy to come closer to the countries of South-East Asia. We must, similarly, come closer to our western neighbours in the Gulf.

* Speech was laid on the Table

- The attacks on Indian students styding in Australia have attracted global attention. This rabid cultural and racial menace has attracted worldwide condemnation. Mr. Sravan Kumar Theerthala from my Constituency of Khammam was hit with screwdriver and it has pierced through his head in his house at Melbourne in June 2009.
- Baljinder Singh, another student from India styding in Melbourne, was robbed and stabbed in his abdomen.
- Since then several attacks took place against Indians in Australia.
- To keep up the morale of the Indian students from Andhra Pradesh and India on the advise of our leader Shri Nara Chandra Babu Naidu I along with my colleague from the Andhra Pradesh Legislative Assembly visited Australia and met the affected students there and also the opposition leaders in Melbourne parliament House to show our concern over the attacks. I also met our embassy posted in our mission there and discussed this issue.
- Telugu Desam party and my Leader Shri Nara Chandra Babu Naidu wants the lives and property of Indians who are in other countries safe land this government should take proactive steps to protect them.
- The WTO-GATT agreement was signed by us in 1995 and till now what has been agreed with regard to subsidy has not been implemented and our farmers are not able to withstand the competition of the farmers from developed countries. These countries provide a subsidy to the tune of 60% percent at the time signing the WTO agreement and it was decided to bring down to 10% to their farmers. Where as we are giving only 2.4% subsidy to our farmers. We should increase our subsidies to the level subsidy of 10%. However, this government has not sincerely worked towards this direction and our farmers are still suffering.
- We should also explore in improving ties with African countries. These countries like us at one time were under colonial rule and we in

coordination with these countries should improve bilateral trade with these countries. There is a lot of potential for bilateral trade.

In order to enhance the bilateral trade between India and African countries, the "Focus: Africa" Programme was launched by Minister for Commerce and Industry on 31st March, 2002. But after 8 years there is no much development abroad and further strengthened.

In the conclusion, I would call upon the government to take a note of all the issues which I have so far raised and I am confident that these measures will greatly help the country to achieve remarkable levels of development. Hence, I again request this government to implement these suggestions on priority without losing any precious time.

With these words I am concluding my speech.

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Thank you very much for having given me the opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants pertaining to the Ministry of External Affairs.

As I was a Non-Resident Indian in the UAE for the past 25 years, till early 2009 and as I had many opportunities of going and visiting foreign countries, very particularly the region of the Gulf countries, I do clearly understand the problems that the Indian citizens are facing in all those places, what are the boiling problems that they are having, what are their desires and what are their inquisitiveness.

Most of the people, the Indian citizens going for jobs are found to be uneducated. In different platforms, they are cheated by either agencies or by the sponsors who are taking them to different countries. Due to their ignorance, they are put behind the bars. They are put in jails for long terms. They are not getting any assistance in adequate manner. Even after the judgment in the courts, they are put in the jails; even after the period of imprisonment is over, they cannot get out of the jail and travel back to India. There are poor people getting treatment in the Government hospitals due to the contagious diseases and the natural health disorders. Though they are getting some assistance from specific Government hospitals, since they are not having relatives or friends, they do not get proper and sufficient assistance.

We know very well Indian Embassies, Consulate Generals of India and different Indian Missions. Our authorities are very much helpful to those who are stranded but up to what extent? In each and every Indian Mission, authorities are there but how many people are there for assisting such kind of stranded people? There may be two or three executives or at the most four people. Lakhs and lakhs of expatriates are there in certain countries. They are facing very serious problems. How do the Indian Missions know what kind of assistance is to be given to those needy people and to redress such kind of grievances? To alleviate the problems, Embassy authorities are helpful to some extent as I already noted. But the exact solution is that Indian Missions should seek proper help, assistance and

coordination from Indian business community, Indian philanthropists, other Indian welfare units and dedicated social activists who are living in those countries. In these kinds of things the Indian Mission should concentrate.

As a very good model, in the United Arab Emirates in Dubai, the Consulate General of India has made one committee called Indian Community Welfare Committee (ICWC). They have formed this committee under the affiliation of the Consulate General of India. They are inviting all business community of our country, other entrepreneurs, social activists and social welfare units. With their assistance, coordination and cooperation, they are helping in time those who are stranded and needy. I could recall the Consulate General of India in Dubai and those who have served there in an excellent manner. I could see in the panel of Ministry of External Affairs here, Shri Sinhaji. He was Consulate General of India, Dubai. I could remember Shri Venurajamani. He has recently been transferred to Delhi. They have been contributing through their excellent service for the welfare of people by utilising their good experience in their office terms with the Government of India. If they consider forming such kind of Indian Community Welfare Committees in most of the countries where our Indian expatriates are thickly populated, it will be very much appreciable.

As per the announcement of our hon. Prime Minister, the voting right will be given to the Indian expatriates before the next General Elections. These expatriates are eagerly waiting for this. We know what are the difficulties in implementing such kind of things. But to hasten the process, if the Government of India take it on urgent basis, it will be much appreciable.

A welfare scheme should be there for repatriated Indians who have come back after spending so many years of their lives in foreign countries. They are giving huge amount of foreign exchange. For such people, a welfare scheme has to be created by the Government of India. In Sri Lanka now the war is over. Political settlement is to be made in an amicable manner. Now to have a political settlement, the situation is very much feasible. Our Tamil people are still

suffering in different camps. A few months ago, our hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar Karunanidhi, sent a delegation of Members of Parliament to look into the situation prevailing in different camps. Accordingly, that delegation has given a proper picture not only to the President of Sri Lanka but also to the Government of India through the Government of Tamil Nadu.

At that time the Government of India had announced a sum of Rs. 500 crore as aid to the Sri Lankan Tamils. But now as we come to know from the speech of Shri Pinaki Mishra, an hon. Member from Orissa, that out of that Rs. 500 crore, only a sum of Rs. 90 crore has been budgeted and out of that only Rs. 63 crore has been spent. I would like to take this opportunity to request the Ministry of External Affairs and also the Ministry of Finance to extend this assistance to the Sri Lankan Tamils. The Government may also consider looking at the ethnic population in countries like Singapore, Malaysia and Gulf countries in order to facilitate these people to come and interact with the people at the Indian Embassies about their problems. The Government may consider setting up an Ethnic Cell where you have staff who are having the mother tongue of those people coming to the Embassies to interact with them with their problems. It will be help the poor people a great deal who would have the opportunity to talk about their difficulties and grievances in their own language.

Sir, I would like to make a point in regard to the Haj quota. Due to increase in population and also due to economic growth, we require more number seats. The demand is increasing every year. The Haj quota has to be increased keeping in view the growth in population; particularly I would like to make a point about Tamil Nadu. The State is given a quota of 3000 people by the Central Haj Committee. Now, the constituency that I represent, namely, the Vellore parliamentary constituency, has a very big Muslim population and I think, a share of just 3000 seats would be insufficient for a constituency like Vellore itself, let alone the State of Tamil Nadu. So, I would like to take this opportunity to request

the hon. Minister of External Affairs to consider increasing the number of Haj quota for the State of Tamil Nadu than what is being provided at this moment.

Sir, with these words, I support the Demands for Grants for the Ministry of External Affairs.

MADAM CHAIRMAN : I would like to remind the hon. Members that every Member would be given ten minutes to make their speeches.

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Madam Chairperson, India is one of the biggest democracies in the Comity of Nations. A very good foreign relations and neighbourly relations are required for every nation to have growth and development, safety and security. The multi-faceted growth would help our country to emerge as a strong power. Our country has assumed an important place in the Asian Continent and is being closely watched by Asian countries. We are in the 63rd year of our Independence. It calls for a soul searching as to whether we have succeeded in establishing very cordial relations with our neighbouring countries. The answer will be an unpleasant 'no'. This only suggests that the time has come to have a re-look, revisit and review our Foreign Policy.

We are not very sure about what kind of relations we are maintaining with the closest of our neighbour, the State of Sri Lanka. It has become a daily ordeal and a continuing horror tale faced by our fishermen to have been shot at by the Sri Lankan Navy. It has become a routine for the Sri Lankan forces to take away the catches of our fishermen and take them away to their prisons.

It is not long back that they have killed lakhs of Sri Lankan Tamils who are of Indian ethnicity and origin. The Sri Lankan military might had raised to the ground many of the hospitals and schools in Tamil populated areas. They did not spare even children and women. They had let loose cruel attacks on the innocent people. On the one hand, the Sri Lankan Tamils belonging to that soil were wiped out and on the other hand, those who managed to escape and became Internally Displaced Persons were put in refugee camps. Whether the rehabilitation measures meant for them were carried out sincerely is a million dollar question. Rs. 500 crore was allocated from our Union Budget last year for the relief and

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

rehabilitation work there. Even Rs. 90 crore has not been spent on the needy suffering people. Whether any purpose was served by way of sending a team of our MPs is another moot question. The factual reply could be that nothing has come out of it. The rehabilitation work goes on at a snail's pace. Even now hundreds of Tamils in the IDP camps are facing starvation deaths. This only suggests that our foreign relations with Sri Lanka is a failure. Our foreign policy that discriminates the Sri Lankan Tamils is condemnable. In order to promote Indo-Sri Lankan relations and to safeguard the interests of our fishermen, we must get back the Katchativu Islet that was handed over to Sri Lanka. This is what our leader and the former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has been reiterating.

Have we normalized our relations with Pakistan? This is another question that needs to be answered with all sincerity. The honest reply would be that we have miserably failed. Everyday, the Indo-Pak relations gets dented and gets deteriorated. Such a situation prevails now. In 2008 Mumbai attack was carried out. Series of bomb blasts are taking place, Kashmir problem is still haunting us, terrorists from across the border with their base either in Pakistan or Afghanistan are fomenting trouble. All these factors are throwing a big challenge to strengthen Indo-Pak relations. All the sad episodes and incidents only make us to resolve that we need to review our foreign policy pertaining to Pakistan.

Have we gained anything from our ties with the US? This is another question which needs to be analyzed. Has it strengthened or helped our neighbourly relations with our neighbouring countries? Unfortunately, the reply can be a big 'no'. As the saying goes, waking up the child and rocking the cradle is what the US is doing. It provokes Pakistan and India both and watches the clashes. This is the ground reality. If the US is really concerned, then it must have contained and condemned the extremist tendencies showing up its ugly head in Pakistan. It could have ensured very cordial relations. Even at a time when there is a danger of nuclear weapons slipping into the hands of the terrorists, the US has

not helped wholeheartedly to normalize the Indo-Pak ties. We need to ask a question whether the US reflects truly the faith we have reposed in them. Hence I would like to caution this Government about the Indo-US relations which we maintain as of now.

In Australia Indian students and establishments are being attacked. Our nationals are forced to flee and return to our motherland. This sordid affair continues. But it is said that Indo-Australian relations are very cordial. Then we need to ask the question as to why these attacks against the Indians are continuing there. It is paining to see such things when we term our relations are smooth.

In our neighbouring countries like Nepal and Bhutan, it is reported that the Maoists who have resorted to violence are having are their base camps. If these countries are real friends and are loyal to India, then they must not be seen to be providing shelter to them creating conducive atmosphere for them. This, in fact, throws a very big challenge to our neighbourly relations with these countries.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude. There are almost 15 more Members to speak. The hon. Minister is scheduled to give his reply at 6.30 p.m. Please be brief or you may lay your papers on the Table.

SHRI C. SIVASAMI : Our Indian workers who suffer injuries and lose their limbs and body parts are repatriated from some of our so-called friendly countries without being compensated and deprived of insurance benefits. I urge upon the Union Government to ensure that our migrant labour are adequately compensated when they meet with accidents in foreign countries.

I would like to bring to the notice of the Government a strong apprehension lurking in our minds as to whether the developed countries that include America are considering India to be a growing threat to them for it is acquiring a fast paced economic growth due to the hard work put in by Indians meeting with development in various spheres of activity with a spirit of humanitarian attitude to forgive even those who have harmed us. Is it that they consider it to be better for them to find India not having good neighbourly relations with its neighbours?.

Have we woken up at least after losing our eminent leaders like Smt. Indira Gandhi and Shri.Rajiv Gandhi. In order to ensure a national growth to outsmart the developed countries, we must have to re-vitalise our foreign policy revisiting and reviewing it. With this I conclude.

*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Sir I raise to support this Demands for Grants of Ministry of External Affairs. I thank the Hon'ble Minister for opening passport office in Madurai. I request the Tamil Nadu Government to open a sub office to facilitate the poor citizens of Madurai, Trichy and Chennai.

Sir Tamil speaking people are living abroad and working abroad particularly in UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Malasia, Singapore, Far-East and Western countries; more than one crore south Indians are working abroad. They are sending their salaries in foreign currencies. It accounts for more than one lakh and twenty thousand crore rupees but these foreign workers are not taken care of. Thanks to that Government that they can send Rs.10,000/- worth of goods free of duty to their near and dear ones but the courier companies like DHC, Blue Dart are not taking small packets of lakhs of lakhs of workers working abroad who send their parcels during the festival seasons.

The fate of ordinary workers is very pathetic. They cannot grease the palms of the officers so that they are cleared. They are not cleared in time. I request the External Affairs Ministry and Overseas Indian Affairs Ministry to intervene. I request the custom officials to clear the small couriers of the workers immediately.

Sir, in Ceylon, Singapore, Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Malaysia lakhs and lakhs workers are there but there is no Tamil speaking officer in these Indian Embassies. If anybody goes on Friday evening they can enter only on Monday for their repatriation.

Twenty four hours of emergency Office can be set up to facilitate the working forces abroad. Tamil speaking Indian Officers can be posted there; visa charges should be abolished for the Indian origin people living aborad. In all these countries only Hindi speaking Officers are in important positions. I plead with the Government to consider this.

With these words, I conclude by supporting this Grant.

---

* Speech was laid on the Table

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you Madam Chairperson. I must thank the Chair first because we got an opportunity to express our views with regard to foreign policy of our country in the form of discussion on the Demands for Grants on the Ministry of External Affairs.

We are proud of our foreign policy of our Government. Our Government is not a subordinate country of any big power. It is said earlier that our foreign policy is non-allignment. India led the Non-Alignment Movement. Our former Prime Minister Madam Indira Gandhi led the Movement. She was the Chairperson of the Non-Alignment Movement. Our country had led the developing countries and the Third world countries several times on several occasions.

What is the real position today? Are we following the same policy? Or are we gradually shifting day-by-day from our long standing foreign policy? What is our attitude towards our neighbouring countries? Several Members have already pointed that out. So, I do not want to reiterate all these things. We are getting marginalised. Are we in good terms with our neighbouring countries, like Pakistan, Afghanistan, Nepal, Sri Lanka and Bhutan? A lot of disputes are there which remain unsettled. Our country is being victimised by various forces coming from the soil of the neighbouring countries, particularly Pakistan. What is our attitude towards Afghanistan? Due to paucity of time, I do not want to deal with them in detail. But in short our great nation is getting isolated and it is getting marginalised. India's record in moulding conditions in neighbouring countries is very poor. Since the early eighties, India has got excessively identified with the Northern Alliance composed of Tajikistan, Uzbekistan and other non-pashtun countries and backed by Iran and Russia.

What is the position today? What is our relation with Iran? We are gradually going to succumb to the pressure of the USA. So many examples are there. It is a long debate. I am not going into the issues like the nuclear deal, the joint military venture with the USA, the joint naval venture, the joint air venture and all these

things. We have voted against Iran. Iran is a very close friend. We have longstanding friendship with Iran. What is the attitude towards Iran? So far as Sri Lanka is concerned, India withdrew the forces from Sri Lanka It is all right. About the settlement of the key issue with Sri Lanka, what is the sort of role played by India now? So, all these things are involved.

India's strength does not and never can come from being a subordinate to the USA. So far as the Nuclear Bill is concerned, the dagger is on our head, I mean the Act adopted in the US Congress. Now, one Bill is already pending. I am not going into that. So, there are so many instances. Several hon. Members have already pointed out these things. Gradually, we are going to succumb to the pressure of the USA. My point is that our country, the leaders and the External Affairs Minister in particular should realise that the main strength of the world is changing. The USA wants to make a unipolar world. The situation is not like that. The main strength does not lie in the Europe. The main strength does not even lie in the USA. The focus is gradually shifting towards the East – India, Russia and China. We are getting close. Yes, we should do it.… (*Interruptions*)

Madam, India's strength can never come from being a subordinate to the USA. It comes from having a voice in the neighbourhood – West Asia, South Asia, China and Russia.. But, unfortunately, it is getting marginalised. The inability to articulate a policy dear to the West Asian hearts, the voting against Iran at the IAEA at a politically critical time, the confused policy in respect of Sri Lanka and Nepal - all these are there. The list is long.

I am now coming to some economic aspects. I will take only two minutes.

MADAM CHAIRMAN : Shri Panda, the allotted time is over.

SHRI PRABODH PANDA : I will take just one minute. If we look at the economic policy, it will be clear that we just want to follow the same policy, which policy created the economic recession, the melt down situation in the USA. We are going to pursue it. We are going to follow the open market policy. This Budget demonstrates to the NRIs in particular. It is a Budget more to the NRIs rather than the Indians. The lowering of income tax rates is there. The norms of FDI have also been eased and streamlined. All these things are there. The open market policy is being gradually strengthened.… (*Interruptions*) But suffice it to say, the market economy can never be a substitute of sound diplomacy.

With these words, I express my grouse in this regard.

MADAM CHAIRMAN: I would like to remind the House that if the hon. Members have a long speech, they can lay their speeches on the Table of the House.

* DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB) : Madam Chairperson, I am grateful to you for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grant (2010-11), pertaining to the Ministry of External Affairs.

Madam, sixty-two years have passed since we gained independence. We espoused a non-aligned foreign policy and suffered a lot due to this. In 1962, China stabbed us in the back. It was a debacle. We were young and studied in the colleges. We used to raise slogans of "Hindi-Cheeni, Bhai-Bhai" (Indians and Chinese are brothers). However, China brazenly attacked us in 1962 and occupied thousands of square kms of our area. We failed to get back our area illegally annexed by China. Now, China has the audacity to claim that the entire Arunachal Pradesh is theirs. The Deputy Commissioner of Leh in Ladhakh has said that the Chinese have put up boards on Indian soil claiming it to be part of China. I am surprised that the Foreign Minister of India has not even cared to issue a statement on this sensitive matter.

Madam, the Chinese are bullying us and browbeating us. But, the Indian Government has turned a blind eye to this problem. We should not be afraid of Pakistan. But we must be very cautions and wary of the evil designs of China. However, we continue to feign as if our relations with China are very rosy. Enemies must be given a befitting reply. Enemies do not understand the language of peace. We must talk to China from a position of strength. China is also indulging in proxy-war against India. It is helping the Maoist insurgents in India. Arms and ammunition are being smuggled into India through the porous Indo-Nepal border. Pakistan and China, both are helping the divisive elements in India.

Madam, I reside near the Indo-Pak border. My house is only six kms away from the international border. Fake currency is being smuggled into India in lakhs. It is a deliberate

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi

mischief on the part of Pakistan to derail Indian economy. Drugs and narcotics are being smuggled through this border. Pakistan aims to destroy the lives of Indian youths through its machinations.

Madam, a minister of the Central Government has welcomed people from Pak-occupied-Kashmir to come and settle in Jammu & Kashmir. However, the Government keeps quiet regarding the Sikhs who are being hounded in Afghanistan and who are desirous of coming and settling in India.

We had met the Hon. Minister when he had visited Amritsar. We asked him not to have two yardsticks. The Sikhs in Afghanistan are people of Indian origin. There should not be two yardsticks – one for people of Pak – occupied – Kashmir and another for Sikhs of Afghanistan.

Madam, the Sikhs are second to none so far as making sacrifices for the country is concerned. We were at the vanguard during the freedom movement. But, the Sikhs are being ignored now. The Sikhs in Afghanistan were tortured and killed by fanatic elements. Their property was looted. Their women were raped. They must be provided shelter by India.

Madam, thousands of people of Indian origin from Afghanistan have sought refuge in Delhi. They are crying out for justice. But, the Indian Government has failed to provide them Indian citizenship. They are our own people. We must take care of them.

Madam, seventeen innocent Indians have been implicated in a false case in U.A.E. and awarded capital punishment. Hon. Dhindsa ji visited those hapless Punjabi youths. The case dragged on for 15 months. But, the Indian embassy in U.A.E. did nothing during this period to help these poor youths. I am grateful to the Prime Minister of India. We requested him to help these innocent youths. Now, some legal assistance is being provided to these youths.

MADAM CHAIRMAN : Dr. Ajnala, your time is over.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Madam, I have just started.

MADAM CHAIRMAN Kindly wind up.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Madam, I have to raise many important points.

MADAM CHAIRMAN **:** Please be brief and to the point.

DR. RATTAN SINGH AJNALA :The Central Government is not helping the Sikhs and Punjabis. The Central Government is very quick to help the Tamils in Tamil Nadu and also in Sri Lanka. So, why is it fighting shy of helping Sikhs and Punjabis in foreign countries. Are they not Indians?

Madam, crores of rupees are spent on Haj pilgrims. However, when Sikh devotees want to visit their religions places in Afghanistan, they are denied visas. We don't need doles of crores of rupees. But, at least provide us visas to visit our religious places in Pakistan.

Madam, injustice is being meted out to Punjabis and Sikhs. Thousands of our youths have been duped by greedy travel agents and dumped in Spain, Italy and other European countries. The Pakistan embassy in these countries has taken steps to bring their youths back. However, the Indian embassy in these countries are blissfully indifferent to the plight of our youth stuck up in these countries. In fact, some officials are seeking bribes from these hapless youths. This is the depth of corruption.

Madam, these youths are sons of poor parents. Their parents had to sell off their land so that their sons could have a better future abroad. But the agents duped them. These youths have been left in the lurch in foreign countries. They are languishing in prison. Hence, the Government must come forward and bail out these youths and help them in their quest. There should be no double – standard. When people of Pak-occupied – Kashmir can be helped by India, why not our own Punjabi youths?

Madam, I am happy to say that Punjabis have made a name for themselves wherever they have gone. In Canada, 9 Members of Parliament are Punjabi. In Britain, 4 Members of Parliament are Punjabi. In Singapore, there are 2 Punjabi Members of Parliament. And in Malaysia too, there are 2 Punjabi Members of

Parliament. Punjabis have brought a good name for India wherever they have gone. But, the Central Government has never provided our due to us. Grave injustice has been done to us.

Madam, I do not talk only about Punjabis. Wherever in the world, if people of Indian origin are in distress, it is the moral responsibility of the Government of India to help them. The Government must provide relief and succour to Indians abroad if they are in trouble.

Madam, as far as foreign policy is concerned, if we cannot have good, friendly relations with our neighbours, we cannot sleep peacefully. I am sorry to say, none of our neighbours is friendly towards us. Whether it is Nepal or Pakistan or China, no country has friendly relations with us. Even Bangladesh, which came into existence due to our help, nurses anti-India feelings. Surely, something is amiss somewhere in our foreign policy.

MADAM CHAIRMAN Dr. Ajnala, please wind up.

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Madam, kindly grant me one minute more. Almost 3 to 4 crore Bangladeshi nationals are illegally living in India. These are just rough estimates. The Government has turned a blind eye to this grave threat to our security. Many Bangladeshis are caught in Punjab while trying to cross over to Pakistan. Things have come to such a pass. Hence, I appeal to the Government to rectify the mistakes in its foreign policy so that the interest of India can be safeguarded.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, विदेश विभाग की डिमांड पर बहस करते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व चाहे प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री या जो कोई भी करता हो, वह याद रखे कि हिन्दुस्तान दुनिया का छठा हिस्सा है। हम दुनिया की 17 फीसदी आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने आये हैं। हमारी विदेश नीति ठीक चले। जिस समय मानसिक गरीबी से पीड़ित लोग होंगे, हिन्दुस्तान की विदेश नीति भी उसी तरह से होगी। विदेश नीति का सबसे प्रथम धर्म है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो। चाहे जो कुछ हो, देश के हित पर, जनहित पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे, वही नीति होगी। अब उस नीति में कूटनीति और अनेक तरह की नीतियां शामिल होती हैं। यह ठीक बात है कि हिन्दुस्तान अभी आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया में उभर रहा है और इसी तरह की हमारी पालिसी होनी चाहिए।

आपने समय का बंधन कर दिया है, इसलिए मैं अपनी संक्षेप में अपनी बात कहता हूं। यूएनओ दुनिया की पंचायत है, उसकी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए हिन्दुस्तान का प्रयत्न करना चाहिए। हिन्दुस्तान को अपनी विदेश नीति और कूटनीति उस तरह से सफल और मेहनत करके बनानी चाहिए कि जो गरीब, पिछड़े और दलित मुल्क हैं, हिन्दुस्तान उनकी अगुवाई करे। चूंकि आजादी से पहले डा. राम मनोहर लोहिया, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी और जितने हमारे पुरखे हुए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सभी लोगों ने जो विदेश नीति तय की गुटनिरपेक्षता की, उससे हमें न पीछे हटना चाहिए, न उससे समझौता करना चाहिए। अमेरिका बराबर खिलाफ रहा है, हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति की खिल्ली उड़ाता रहा है, लेकिन वह हमारे खून में है। आज लोग हमें ग्लोबलाइजेशन सिखाने चले हैं। वसुधैव कुटुम्बकम् की सर्वोच्च नीति हमारे संस्कार में है कि दुनिया एक परिवार की तरह है। मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं। सवाल नंबर एक, यूएनओ की फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक नहीं है। उसे विश्व पंचायत के रूप में कार्य करना चाहिए। यदि दुनिया का छठा मुल्क यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य नहीं होगा, तो यूएनओ और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल का क्या मतलब है? हमारी डिप्लोमेसी कहां है कि उसमें हमारी सदस्यता नहीं हो पा रही है? कहां कमजोरी है? कहां कूटनीति विफल हो रही है? इसीलिए हिन्दुस्तान जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं रहेगा, यूएनओ और सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मतलब नहीं है।

सवाल नंबर दो, दुनिया की दूसरी सर्वाधिक आबादी द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी भाषा कहां है? यूएनओ की मान्य भाषाओं में स्पेनिश आदि दूसरी भाषाएं हैं, लेकिन हिन्दी नहीं है। क्यों नहीं है हिन्दी? माननीय विदेश मंत्री जी हमको इसका जवाब दें कि कहां कमी है और कहां इनको समर्थन चाहिए? यूएनओ की जो पांच-छः भाषाएं हैं, उनमें हिन्दी शामिल क्यों नहीं है?

सवाल नंबर तीन, इसी संसद ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था जब चीन ने सन् 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि उससे पहले और उसके बाद में चीन और हिन्दुस्तान के बीच में गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन कूटनीतिक गोलियां चलती रहती हैं, कभी तवांग के नाम पर, कभी वीजा नहीं देने के रूप में, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अलग वीजा देंगे, कई भागों में कई वेबसाइट्स पर चीन साइबर वार कर रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी संसद ने यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है कि चीन द्वारा दखल की गयी इंच-इंच भूमि हम वापस लेंगे, नहीं तो हम दम नहीं लेंगे। आज लोग खर्राटे ले रहे हैं, बड़े ताकतवर बने हैं। हमारी एक इंच भी धरती अभी तक चीन क्यों दखल किए हुए है?

सवाल नंबर चार, जम्मू-कश्मीर में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे गुलाम कश्मीर भी कहते हैं, वहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, पाकिस्तान हमला करता है तो उसका समझौता करा लेंगे। सभी बीमारियों की जड़ एक है, जम्मू-कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के दखल में है, उसके लिए भी संसद का पारित प्रस्ताव है। मैं आपको याद कराता हूं, क्यों इसे भूल जाते हैं? क्यों प्रस्ताव पारित किया हमसे पहले वाले लोगों ने इसी सदन में कि हम उसको वापस लेंगे, वापस कराएंगे? उसके लिए आपकी क्या कूटनीति है? क्या पॉलिसी है? हम उस पर क्यों चुप हैं? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से पीड़ित हैं, तो उसके यहां शिविर चल रहा है, हम अमेरिका से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या दूसरा कोई हमारी सहायता करेगा? हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हिन्दुस्तान में हम सभी लोग और दल जितना एकजुट होंगे, हम दुनिया के छठे हिस्से हैं, दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। दुनिया में लोकतंत्र हिन्दुस्तान में पैदा हुआ। जब भगवान बुद्ध आए थे, उन्होने कहा - वज्जि नाम सतः परिहानिया धम्मः, अर्थात seven virtues of Vajjian's leading not to decline. यहां नियम के आधार पर लोग हुक्म जारी करते हैं। जब दुनिया में राजा-रजवाड़े थे, उस समय वैशाली में जनतंत्र था।

जनतंत्र हिन्दुस्तान की पैदाइश है, दुनिया ने हमसे जनतंत्र सीखा है। हमने एब्राहम लिंकन से जनतंत्र की परिभाषा नहीं सीखी है, यह हमारे पुरखों ने पैदा किया है। लेकिन जनतंत्र के लिए हमने क्या किया, आज म्यांमार में आन सान सू की जेल में क्यों बंद हैं? आन सान सू की आज म्यांमार में जनतंत्र के लिए ही लड़ाई लड़ रही हैं और जेल में बंद हैं। वहां के मिलिट्री हुक्मरानों ने उन्हें जेल में बंद कर रखा है। क्या हिन्दुस्तान का यह कर्तव्य नहीं है कि हमारे एक पड़ोसी मुल्क की नेता जेल में बंद है, उसके लिए आवाज उठाएं?

चीन ने तिब्बत में दखल दिया और वहां के धार्मिक गुरू दलाई लामा ने हमारे देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या हमें तिब्बत पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? तिब्बत पहले इतने समय तक आजाद मुल्क रहा है। आज भी हमारे देश में इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स है।

सभापति महोदया : डॉ. साहब, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं अपनी बात समाप्त ही करने जा रहा हूं, क्योंकि कूटनीति और इसका इतिहास, भूगोल और संस्कृति इतना लम्बा विषय है कि इस पर घंटों चर्चा हो सकती है। इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाकर केवल पाइंटवाइज बोल रहा हूं। तिब्बत को चीन क्यों नहीं मुक्त कर रहा है, कभी तिब्बत हमारे देश की सीमा से लगता हुआ मुल्क था, जो कि अब चीन का हिस्सा बना हुआ है। जब कभी इस पर बात होती है तो हमारे लोग कहते हैं कि चीन से झंझट नहीं है, यह तो बोर्डर डिस्प्यूट है। जब हम लोगों ने कबूल कर लिया कि तिब्बत उनका हिस्सा है, तो फिर क्या किया जा सकता है। आज तिब्बत के धार्मिक गुरू दलाई लामा वहां से निर्वासित होकर हमारे देश में आए हुए हैं। हमें चीन से साफ-साफ कहना चाहिए कि वह हमारी इंच-इंच जमीन खाली करे और तिब्बत की लड़ाई में हमें उसे समर्थन देना चाहिए तथा विश्व के मंच पर इस सवाल को उठाना चाहिए।

नेपाल हमारा हाड़-मांस का टुकड़ा है। लेकिन वहां भी अब हिन्दुस्तान के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है। वहां कोई प्रचंड माओवादी हैं, वे हिन्दुस्तान का विरोध करते हैं। हमारा नेपाल के साथ काफी गहरा सम्बन्ध है। भारत और नेपाल केवल सीमा पर लगते हुए दो मुल्क नहीं हैं, अगर किसी का यहां घर है तो वहां से वह पानी ला रहा है। इसी तरह से अगर किसी का वहां घर है तो यहां मार्केटिंग कर रहा है। मैं काफी दिनों तक सीमांत क्षेत्र सीतामढ़ी में रहा हूं। मैंने देखा है कि दोनों देशों के लोगों के बीच ऐसा अपनापन है कि लगता नहीं है कि अलग-अलग मुल्क के लोग हैं। इसलिए हिन्दुस्तान के पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए।

श्रीलंका के साथ भी हमारा रिश्ता कभी-कभी गड़बड़ में पड़ जाता है। इसी तरह से अफगानिस्तान है और बांग्लादेश है। बांग्लादेश जब आजाद हुआ था उस समय शेख मुजीबर्रहमान वहां के नेता थे। लेकिन आज वह बांग्लादेश भी हमसे दुश्मनी कर रहा है। कहां आपकी विदेश नीति है और कहां डिप्लोमेसी की विफलता है, इस पर आपको सोचना चाहिए। हमारे देश के अपने पड़ोसी मुल्कों से अपनापन वाला व्यवहार होना चाहिए। हिन्दुस्तान को विश्व के दबे हुए और विकासशील मुल्कों के साथ दोस्ती करके उनका नेतृत्व अपने हाथ में लेकर उन देशों के साथ न्याय की बात विश्व मंच पर उठानी चाहिए। विश्व शांति का पक्ष हमारा बहुत पुराना है, यह भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय से चला आ रहा है। इसलिए इस

विश्व शांति के संदेश को हमें पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। हमारे देश में जय प्रकाश नारायण जी, डा. लोहिया आदि ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस पर आज हमारा भटकाव हो गया है। इसी कारण गड़बड़ी हो रही हैं और समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए इन सवालों को मैंने यहां उठाया है और विदेश मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारी विदेश नीति, कूटनीति सब ठीक होनी चाहिए। अगर यह होगा तब भारत दुनिया में नम्बर एक मुल्क कहलाएगा और अन्य देशों का भी इस पर भरोसा बढ़ेगा।

SHRI MADHU GOUD YASKHI (NIZAMABAD): Madam, the earlier speaker from the Opposition Party, Shri Pinaki Misra, leveled a serious allegation that UPA-I and UPA-II is lacking the leadership in Foreign Policy. I do agree with him! I would like to remind him the kind of leadership during the NDA regime that when the terrorists hijacked the Indian Airlines plane, the then Foreign Affairs Minister हाथ पकड़कर आतंकवादियों का, उन्हें अफगानिस्तान छोड़ कर आए थे।

We do not have that kind of leadership. The UPA Government is exhibiting the great leadership of the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji. Without signing the NPT or CTBT, we have got the Nuclear Deal through. We are building the nuclear power. The Prime Minister's visit to BRIC countries, to G-8 and G-20, Brazil, and South Africa has been a great success. There is no statesman like Dr. Manmohan Singhji.

When our Prime Minister speaks at the world forums, the whole world listens to him, all leaders listen to him. When the world economy was crumbling, under his leadership the Indian economy stood up. Our economy is still progressing with over seven per cent GDP growth. That is the kind of leadership the UPA Government is exhibiting and not the kind of leadership, the NDA had – compromising with the terrorists.

मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि कौन आपके फ्रेंड हैं , who is your friend? The Foreign Policy of the UPA Government is to promote furtherance of national interest but not political interests. अगर पड़ोसी के घर जल रहे हैं the UPA Government is trying to douse them. It is involved in the development of Afghanistan but not like the NDA; when the US was attacking Iraq, the NDA was ready to send Armed Forces to Iraq. The Foreign Policy of the UPA Government is to build Afghanistan, to build Pakistan and to build our other neighbouring countries including Sri Lanka. Our Foreign Policy was recently outlined by our own Foreign Secretary.

Our focus in Afghansitan is on their development. The greatest threat to peace and stability in our region emanates from the terrorists who are taking shelter in the borders of Afghanistan and Pakistan. The main focus of the recent international conference held in London last month, was on security, reintegration, development, governance, regional and international cooperation.

We are building roads power projects and hospitals in Afghanistan. We are also offering educational opportunities to the Afghan students. We have also started dialogue with Pakistan. The clear cut approach and the policy of the UPA Government is the national interest and not the political interests.

Madam, we have 168 Missions/Posts abroad. There is a global challenge for them. They are doing multiple tasks. We have the diplomats in these Missions/Posts. But we have less staff, particularly in connection with promotion of trade and labour related issues, more so in the Gulf region. There is a less staff. Counsel for Labour has no staff. These poor workers who have gone for employment in these regions are being exploited by those companies. I would, therefore, urge upon the hon. Minister to strengthen the staff to meet the new challenges faces by these Missions; and also increase the staff in these Missions. Most of the local staff in these Missions – I have seen it myself – are not having any medical facilities. They are not paid enough salaries to meet their ends. So, the Government should think of increasing salaries of local employees too.

Madam, on the potential of Indian Diaspora, we always talk about the involvement of Chinese Diaspora in China's economic development. But still, we have not been able to tap the potential of the Indian Diaspora, which they exhibited when the foreign currency reserves was facing problems. With India Resurgent Bonds, Indians came to the rescue of the Government. Even if you look at the remittance by the Indians, particularly in the Gulf and other countries, as per the statistics of 2005, it was over 27 billion dollars compared to FDI in that particular year, which was hardly 3.7 billion dollars. So, I would urge upon the hon. Minister to look upon not only the NRIs particularly those settled in the Gulf

regions but also set up a Fund to help those who are staying illegally, and who are being exploited by the companies.

18.00 hrs.

I would request the Ministry to strengthen these Labour Department Councils so that they come to their rescue. Most of the time, they face problems.

MADAM CHAIRMAN : Hon. Member, wait a minute.

Hon. Members, it is six o'clock. I have a list of nine more speakers to speak on this Demand for Grants. If the House agrees, the time of the House may be extended till the conclusion of this discussion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM CHAIRMAN: So, the time of the House is extended till the conclusion of this discussion.

SHRI MADHU GOUD YASKHI : Now, I would like to make some suggestions.

Particularly the neighbouring countries' projects which were initiated, most of these projects are stopping at Detailed Project Report level. So, steps should be taken to complete these projects instead of stopping them at that level. Also, regarding the policy on line of credit, a more transparent policy should be looked into.

Regarding Publicity Division, those publications have to be looked into. Also, they should have a think tank in the MEA. I myself was a member for the past five years in the Indian Council of World Affairs. The Sapru House has a huge infrastructure facility. To use those facilities and strengthen the ICWA, there is a need to have a think tank in the MEA itself.

The public diplomacy, which is initiated, is a great initiative by the Ministry, taking people from the various sectors to Afghanistan and other countries. It will definitely help in normalizing the relations.

I would like to stress upon functioning of the Regional Passport Office. The Tatkal programme, which is started by the Ministry, is a great programme. People,

who are in urgency, can get the passport. But it is taking 2-3 weeks' time. We have 30 RPOs but more offices should be opened up. The orientation programme initiated by the RPO in Hyderabad at various district levels has helped a lot.

MADAM CHAIRMAN: Madhu Goud Ji, please conclude.

SHRI MADHU GOUD YASKHI : I will take one minute and complete it.

These initiatives will help the people who are going abroad for studies and employment. So, steps should be taken to open up more RPOs.

Lastly, I would conclude by saying that thousands of Indians are stranded due to the Iceland volcano explosion. I urge upon the Ministry to use funds from the account of Disaster Management whereby they can come up to help those Indians who are stranded and struck up in different countries.

Madam, Chairpereson, with these words, I support the Demand for Grants of the Ministry of External Affairs.

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Madam, I heard the hon. Members from both sides. I heard Dr. Joshi Ji. I heard Members from the Government benches. I think the truth lies somewhere in between because we have stopped, I think, talking to Pakistan. Unfortunately, because the more we delay our talks with Pakistan, the State, which will be more hit, is the State of Jammu and Kashmir. You know it better.

18.03 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

If we go on talking about Bombay attack, even on that we will have to talk to Pakistan so that things are sorted out and sorted out once for all. Since we are not talking to Pakistan, even internal dimensions of Kashmir issue, we talked about quiet diplomacy but unfortunately, it has been given a quiet burial and even moderate Hurriyat people have said that there is nothing like quiet diplomacy which is harming the people of Jammu and Kashmir.

Madam Gandhi is sitting here. She gave us a wonderful gift last year. It was that the Srinagar Airport was declared as an international airport. Air India started a flight between Srinagar and Dubai and it was a very welcome thing. But unfortunately, for no reasons known to us, that international flight has been suspended and Srinagar Airport continues to be an international airport and no international flight operates from Srinagar Airport.

So far as I know, even places like Goa and Kerala, the chartered flights can land there but unfortunately even after declaring Srinagar Airport as the international airport, no international flight is operating from Srinagar Airport.

We could engage ourselves with Pakistan, because we are a liberal democratic secular country and democracy is flourishing here. We talked to Pakistan even when Pakistan was ruled by an Army dictator. There was an Army person who was ruling Pakistan and we started a dialogue which was wonderful. But now that there is a so-called democratic Government placed in Pakistan, which is ruling

Pakistan, we have stopped talking to them. Unfortunately, as I said, we are hit the worst.

Dr. Joshiji, all the road connectivity that we have had before 1947 has been shut down. We had Srinagar-Muzaffarabad road which was opened up, but unfortunately, the trade, the business is so slow. For those who want to see their relatives in the other part of Kashmir, getting visa and passport are so complicated a procedure that very few people have been able to take advantage of this opportunity. I would request you to make easier, to make simpler the complicated visa and passport procedures so that the people of the State of Jammu and Kashmir can really take advantage of the facility provided to them to go across and meet their relatives in that part of Kashmir.

We felt choked because the only link we have with the rest of the world and the rest of the country is Srinagar-Jammu Highway and all other roads like Srinagar-Muzaffarabad road, like Jammu-Sialkot road, like Kargil-Skardu road, stood closed down. As a result, our economic activities have come to a standstill. There was a time when Kashmir trade and business flourished because we had very good relations with Central Asia. There was a definite policy and we had very good relations and our economic activities were at its peak.

Even when we talk about China, we have to have a definite policy in place because our relations with China are also affecting the people of Jammu and Kashmir. If you recall, a few months ago, China said that Kashmiris do not need visa to travel to China and there was no reaction from the Government of India unfortunately. Imagine, if this thing had come from Pakistan, we would have almost annihilated Pakistan. China even tried and said that we cannot construct a road on our side of Jammu and Kashmir, which is in Leh. I do not know what happened to that road. I would request the External Affairs Minister to have a definite policy in place and take the entire House into confidence so that we know how good relations we have developed or we are trying to develop with Pakistan in particular and with China.

Before concluding I would talk about SAARC. We do not know whether SAARC is functioning at all or not. We have to make it effective so that we are on a very right path.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Mr. Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity.

We have been discussing about India's foreign policy and its success. I would like to say that those critics of India's foreign policy have miserably failed in analyzing the courage, strength and diplomacy of our country. If anybody feels that any country, whether it is a rich country or not, can swallow India like a small capsule, they are mistaken. India is becoming a global leader and the entire country can be proud of it. Of course, we must say good bye to our inferiority complex in this regard.

As far as our foreign policy is concerned, we can very well realize that the policies adopted by Panditji is still continuing unhampered. Of course, as I stated earlier, this country is progressing well and its international relations are really stable.

Within the short time allotted to me, I would just make an important point about the passport.

Sir, a friend of mine was saying about one point. The passport applications are increasing day by day. We know that in 2009 we have issued 50.28 lakh passports whereas in 1979-80 it was 8.51 lakh. It means there is an increase of 94 per cent. The demand for passport is increasing. The reason is also there. Countries like Saudi Arabia have liberalised the family visa conditions. In addition to employment, people are travelling for pilgrimage, tourism and things like that. Besides this, passport has become compulsory for Haj also. What I am suggesting is this. We are having 37 passport offices. There was a proposal previously that some 77 Passport Seva Kendras will be opened,. that is to do preliminary work for the passport. Unfortunately, that has not been implemented. I think the Cabinet has given clearance for that. I suggest that that also may be done properly. The shortage of staff is also adversely affecting the work in the passport offices. Proper care may be taken up in that regard also.

Finally, I want to talk about the alternative economic method; I mean the Finance and the banking system. Even though it is not closely connected with the Ministry of External Affairs, when we are discussing all the international collaborations on the economic front, I say that in addition to political diplomacy, economic diplomacy is also to be there. We have to realise one thing. When we hear about Islamic banking and things like that, there is no need to have any kind of allergy to that. Many countries in the world such as Britain, France, Hong Kong, Singapore, US, Thailand, Japan, Australia, China, Korea, Belgium and Sri Lanka are entering into this field in a very big way. We have to realise this.

By 2020 the Middle-East investment may go up to nine trillion dollars around the world. Similarly, we have to understand about America's development after 9/11. Some 800 billion dollars of Arab money has been flown from American banks. We have to realise what is happening.

Sir, what I am suggesting is that India should tap all these chances and we should not have any kind of different method to that. What I am suggesting is that we have to think loudly about that. I am of the opinion that India should give a red carpet reception for this Islamic Banking. We should have a different thinking in that. It is the alternative banking with ethics. It has no hooks. It is a banking system with ethics and which is value-based and it has no fabricated economic basis. I think that it will be the best model to be adopted.

Sir, I have one last point to make about the staff to be appointed in the Indian Embassies. My friend Shri Sampath was saying about that. In the Indian Embassies we have no Malayalee-speaking officers. You know that some 2.5

million Malayalee workers are there in the Gulf countries. Unfortunately, in the Embassies there are no Malayalee officers. As suggested by my friend, I also request that Malayalee officers should be appointed in the Indian Embassies.

With these few words, I conclude.

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Thank you Mr. Chairman, Sir. At the fag end of this discussion, I do not know how much I will be able to present here. I do not know whether I will be able to present even a single point here. Anyway, I know the constraints of the time also.

I have been hearing the speeches that have been put forward especially from the Opposition Benches. We can understand the representatives of the Opposition criticizing the Government, the Ministers and those in the Treasury Benches. But I am at a loss to understand that the Opposition Parties, in order to criticize the Treasury Benches, are trying to belittle the great country that is India. Unfortunately, they are saying that India is small, India has become an agent of the United States, India has got no power. Respected Shri Mulayam Singhji was asking as to who are our friends, meaning we have got no friends. Mulayam Singhji, very humbly I tell you. We have got no enemies and no country will dare to be India's enemy because that is the greatness of India.

Now, everybody is saying that we have become a stooge of the United States of America. When there was the Cold War, when there were two Blocs – the Communist Bloc and the Anglo-American Bloc – Pandit Jawaharlal Nehru took the decision that we should have a Non-Aligned policy.

Till now, under the leadership of Dr. Manmohan Singh and Shrimati Sonia Gandhi, the Government of India, the UPA Government is following the policy of Pandit Jawaharlal Nehru. This policy originated in the year 1925 when Indian National Congress formed a Foreign Affairs Committee. Since then, we have been following this policy.

The Communist Bloc was dispersed when the communism collapsed. In 1989, the Berlin Wall collapsed. In 1991, the Gorbachev issue came and the Soviet Union collapsed. Even then, India stood steadfast in this world with the vigorous strength which Pandit Jawarharlal Nehru had given to us.

We signed Indo-US Treaty. The US wanted us to sign the NPT. They wanted to put so many conditions also. But under the able leadership of Shri

Pranab Mukherjee and Dr. Manmohan Singh, we withstood all the pressure of America. Now everybody was saying that we have become a ...* of America. It was specially our Communist friends who were asking this. Why? It is because they thought that the minority community in this country was against George Bush. Then, we said that the term of George Bush was going to be over and we would never compromise the interests of this country. India has never compromised the interests of this country. I tell this august assembly that the greatest diplomatic feat that the last UPA Government had achieved was the Indo-US Treaty and the NSG clearance because without NSG clearance, we could never have gone for nuclear energy progress. I may tell this august House that in 2050, our energy gap would be of more than 400,000 MW. Now, before signing the treaty with US, we signed the treaty with France and then came in Russia.

We have got 19 nuclear reactors in this country. A canard is being spread that these nuclear reactors will burst and the whole country will go to hell. I may tell that no nuclear reactor will burst. Though small accidents have taken place, but never in the history of the world have nuclear reactors burst. They are built in such a way that they should sustain it. They are not meant for explosion. Nuclear bombs and nuclear devices are meant for explosions. Even that Nuclear Liability Bill is not being brought here. We cannot bring it here. There are 19 reactors. Suppose, a small accident happens, there is no way the civilians will get any benefit.

Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister of External Affairs to the fact that there are two million people from Kerala who are working outside India, especially in the Gulf. They face so many problems. These problems have to be addressed. Some of them are coming back to Kerala, to India. There are two crore Indians outside. Hon. Prime Minister had declared that adult franchise will be given to them and they will be allowed to cast their votes. Unfortunately, a member of the Election Commission recently told in

* Expunged as ordered by the Chair

Kerala that it would be very difficult. I congratulate the hon. Prime Minister and the UPA Government for the initiative they have taken to see that all our friends, who are working and toiling hard outside India, are given their due.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI M.I. SHANAVAS : There is one more aspect which I want to present before the Government.

Now, enumeration, the Census work is going on. In this Census Indians who are outside India are not included. I would request the Government to take steps to see that our brothers and sisters, who are working outside, are included in this Census.

With these words, I conclude and thank you.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : There was a time when the foreign policy of India was appreciated by all the nations of the world. The reason behind was the Non-Aligned Movement or NAM. Who had initiated this movement? It was the Indian National Congress which had mooted the proposal and initiated the movement. In 1954 in Colombo, the then Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru had announced the beginning of NAM. Later in various summits of Indonesis, Belgrade, it was decided that Non-Aligned countries would not be a part of the cold war and would not be a partner of any of the blocs – it was decided that they would not join hands either with capitalist America or Communist Russia. At that time India had pledged to fight in the interest of the common people, the ordinary world citizens; for the development and progress of the neutral world. As a result, India had a special and high status – everybody had appreciated her role in world politics.

But what has happened to our foreign policy today? Why have we fallen from grace? We must ponder over this. We are all aware that with changes in economic policies, foreign policies also transform. In 1993 when India adopted the policies of liberalization and free market, we began to side with the capitalist world, with the handful of developed countries. Since then we began to have less cordial relations with the developing states and today India no longer leads the world. Today Brazil's President has occupied a more significant position. The countries of the Middle East are no longer close to us because we are drifting apart and aligning with USA. Please have a relook at it. Our relations with the neibhbouring countries are souring gradually; Nepal, Bangladesh, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan no longer trust us whole – heartedly. We must assess this current scenario. Though the smaller SAARC countries still have respect for us but this is for the only reason that India is a bigger power – economically and culturally better off. Thus they are afraid of us; but this is not proper. We have to have

* English translation of the speech originally delivered in Bangla

warm relationships with all the developing countries and spearhead the progressive movement which Congress party had done in those days of Nehruji. Though in the eighties, there was a shift in ideology during Indira Gandhi's regime. Today there are certain lapses; there is a huge gap among all the developing countries. India is hobnobbing more and more with capitalist nations and is misinterpreting her relations with China. In the coming years, only China will come to our help. We have to work in tandem with the socialist countries of the world, not with the capitalist super power. If India does not have this viewpoint, it will be extremely difficult for our country to surge ahead successfully, to develop and progress.

India has signed the Nuclear Treaty. Many Hon. Members have mentioned that this treaty is very useful to us. They might be correct. But in case of nuclear accidents, who is going to compensate for the damage and devastation. The Nuclear Liability Bill is in the offing. If accidents occur, who is to pay for the damage? The nuclear reactor suppliers will pay only Rs.500 crores while the rest of the burden will have to be borne by the Government of India. Have we forgotten the Bhopal gas tragedy? We must recall what happened there after the accident.

So as we are moving towards the capitalist countries, we are going far from our genuine partners. Thus I want to say that we need to develop cordial relations with our neighbouring countries with whom we are to interact everyday. If we don't have better neighbours, our foreign policies can never be successful. We should take care of the nations whom we survice with. This point should not be overlooked. Hon. Minister must keep this in mind.

With these few words, I conclude my speech.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, the last six months have been very eventful, as far as India's foreign policy is concerned, which include the hon. Prime Minister's visit to Washington for Nuclear Security Summit, visit to Brazil for the BRIC Summit and the ISBA Summit, the visit of Prime Minister to the Kingdom of Saudi Arabia and the subsequent Riyadh Declaration of 1st March, 2010, Joint Statement of Ministers of ISBA on the status of Middle East, Joint Declaration between India and Russia to further strengthening their ties, and then BIMSTEC Convention on Combating International Terrorism and Drugs, to which the hon. External Affairs Minister went to Myanmar on December 17.

As there is paucity of time, I will just limit myself to three points. The first point is on passports. In this year's budget, there is a four per cent decrease in the passport budget. In our State, the Hyderabad Regional Passport Office has the distinction of issuing the largest number of passports in India. Last year, they issued three lakh passports, and this year it might go beyond four lakhs. The problem in Hyderabad Regional Passport Office is that there is a huge shortage of staff. That is why, people are worried. We are getting a bad name over there. Added to this thing is that countries like the Kingdom of Saudi Arabia, US, New Zealand, Australia and Kuwait are insisting on police clearance certificate which they have made mandatory, that too they are saying it should be country-specific. Now, this has added more burden on the passport office. I can say with full responsibility that in Hyderabad, Lucknow and Bengaluru, people are queuing up to get this police clearance certificate from three o'clock in the morning. I would like to know what the hon. Minister is doing. This has been going on from the last nearly two-and-a-half months. Why is it that things are not moving in his department? When people are queuing at three o'clock in the night, what are the regional passport offices doing? Why can a note verbale not be issued by the Ministry of External Affairs to all these foreign Embassies and Missions that we will issue one police clearance certificate which will be good enough for all

foreign countries and which would be valid for two years? That is not being done. I hope the hon. Minister will take into consideration my request to him.

Second point is that India always stood by the Palestinian cause. India has always stood with Arab countries. But what we see now is that when it comes to Israeli aggression, the barbarism of Zionism, India has always used soft words. Why has there been a sudden shift in our policy towards Palestinian people? This Government is a different Government than what P.V. Narasimha Rao stood for. That process was started there. Israel is building settlements in Jerusalem. Israel is doing suppression and violence in Gaza, and the language used by our External Affairs is "we urge Israel". Why do we not condemn Israel? Why do we not condemn the Zionist aggression? This is what we want to hear. We have stood by them.

Another point on this issue is that India has raised the relationship with Israel to strategic and secret level. Take the example, in 2006, we purchased UAVs. From 2006 till now, I say with all the responsibility, the UAVs are lying in cold storage why because the Israelis have not given us the cameras. No open bidding is done for the Israeli defence project. Why should this corruption be allowed?

Third point, the visit of the Prime Minister to the Kingdom of Saudi Arabia has been heralded as a new chapter in India-Saudi relations. The BJP people talk about saying what the change has been in NDA time and UPA time. In UPA time, we find King Abdullah saying very categorically that India need not worry about its energy needs or deficit; we will stand by India. That in itself is a great and huge assurance given by the Kingdom of Saudi Arabia. My request to the Minister is that even during the late Indira Gandhi's time, which was a historic visit, bilateral agreements were signed and kept in cold storage. I would request, through you, Sir, the Minister to form a nucleus group of various departments like Commerce, Education, etc., and let them work so that these agreements can be put into practice.

Last point is about this Haj Goodwill Delegation. For God's sake, stop this political patronage of unemployed politicians. You stop this thing; Rs. 6 crore or Rs. 7 crore that is being spent on this is a criminal waste. That money can be given to poor Muslim girls. Stop this thing; it is of no use at all. We have an Indian Ambassador; we have a Consul General. They can represent India. This Haj Goodwill Delegation comprising of 30 unfit, misfit Muslims who go there are taken care of by the Indian Embassy, whereas their job should be to take care of the poor Hajis.

Lastly, about this Haj subsidy, the demand has been raised from the BJP as to why Haj subsidy is being given. I have no problem, if all religious subsidies are taken away. Let it be taken away; we have no problem.

It will not stop Muslims of India performing Haj. When you talk about Haj subsidy, you do not talk about the Kumbh Mela subsidy. What sort of discrimination is this… (*Interruptions*)

DR. MURLI MANOHAR JOSHI (VARANASI): There is a tax on Kumbh Mela *Yatris.*

SHRI ASADUDDIN OWAISI : I also pay income-tax as an Indian. Do I not pay income-tax? I am not exempted, Shri Joshi. I pay tax, he also pays tax. What I am saying is that let us finish this subsidy. Why should we have subsidy? I have no problem at all. … (*Interruptions*) I am concluding, Sir. It is not even two minutes.

MR. CHAIRMAN : You have already taken five minutes.

SHRI ASADUDDIN OWAISI : Let me just conclude. I know you have got paucity of time. The point is about rebuilding of Afghanistan. The Outcome Budget of the External Affairs says that Rs.442 crore were given and till December, only Rs.100 crore were spent. Why are such things happening? With this, I thank you and I support the Demands.

MR. CHAIRMAN: Shri Thokchom Meinya to speak. As you requested, we are giving you two minutes.

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): I will lay the rest of the speech on the Table of the House, after I speak two minutes.

MR. CHAIRMAN: If you want to lay it, you lay it. Laying of part speech cannot be allowed. You can speak for two minutes otherwise you can lay it on the Table of the House.

DR. THOKCHOM MEINYA : Thank you very much, I will just highlight the points.

At the very outset, I would like to say that our foreign relation is important for us. India is doing no doubt very well. By putting like this, I am not going to dwell upon, in an elaborate way, the achievements of our foreign policy. At the moment, I do simply highlight some of the few things pertaining to North-East India from where I have come.

We are all aware that the international boundaries, the Indo-Myanmar boundary right from Arunachal Pradesh to Mizoram, we have a very peculiar situation going on there. One thing is that almost all the international boundary pillars have been removed or shifted to other side. And in that process, we are losing the 'no man's land' from our Indian territory. This is happening because the same type of people, having the same religion and speaking the same language, they have settled together. Even their children are married to one another. So, for the solution to this problem, we have to insist on certain humanitarian grounds because it is very peculiar. We are not fighting for it among others. We are having the same type of people staying, same language spoken, same religion is being practised from Arunachal Pradesh to Mizoram. And the same is true for Indo-Bangladesh border also. We speak same language and even the children are married to one another from either side.

The last point I would like to mention about the Look East Policy. I wish that this policy is still vigorously pursued. Why I say this is because I am coming from the East and I do not mind, if at all, I always look to the West. I seek the indulgence of the hon. Members, brothers and sisters here in the House, that please

try to look East when we look West. And let us try to look East in the Look East Policy, which is the best one and it will go all the way from India to the rest of the country. And in the Look East Policy, I propose that Japan should also be included.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, विदेश मंत्रालय की चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त करूंगा और जो चीजें आ गयी हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा।

मैं कहना चाहूंगा कि यह परसेप्शन हाउस दे रहा है कि इंडो-चाइना रिलेशन ठीक है और इस रिलेशन में भारत भारी है और चीन भारी नहीं है। मेरे हिसाब से यह परसेप्शन ठीक नहीं है। यह देश की विदेश नीति का मामला है। जो परसेप्शन मीडिया में आ रहा है, जो परसेप्शन जनता में आ रहा है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं जिसके बाद यह परसेप्शन क्या है, यह आप तय करें।

अरूणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री की यात्रा हुयी और चीन ने आपत्ति की। मैं कहना चाहता हूं कि यात्रा में आपत्ति हुयी, उस समय विदेश मंत्रालय ने यह प्रतिक्रिया दी कि हमें कोई रियेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरूणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। जब मीडिया ने इसको हाइलाइट किया कि चीन ऐसा कैसे कह सकता है, तब दो घंटे बाद विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया आयी कि हम इसमें आपत्ति प्रकट कर रहे हैं।

प्रतिक्रिया देने में दो घंटे क्यों लगाए गए, मेरी समझ में नहीं आया। तुरंत रीएक्शन आना चाहिए, जैसे कुछ और सदस्यों ने भी कहा।

एक बात और कहना चाहता हूं। मैं किसी काम से अरुणाचल प्रदेश गया था और वहां के चीफ सैक्रेटरी से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार मैं किसी डेलीगेशन में चीन जाने वाला था। जब मेरे वीज़ा की बात आई तो चीन ने यह कहा कि आप तो हमारे आदमी हैं, आपको वीज़ा की क्या जरूरत है। भारत सरकार ने कोई रीएक्शन ही नहीं दिया। हालांकि वह डेलीगेशन चीन नहीं गया, लेकिन जब चीन ऐसा कहता है कि आप हमारे आदमी हैं, आपको वीज़ा की जरूरत नहीं है तो रीएक्शन आना चाहिए। मैं इस बात को सरकार से जानना चाहता हूं और हाउस को भी विश्वास में लेता हूँ से भी कहता हूं कि रीएक्शन आना चाहिए। चीन ने कहा कि हमारे यहां कोई भी कश्मीरी आए, वीजा की जरूरत नहीं है। साथियो, क्या यह परसैप्शन ठीक है? इसमें भारत भारी है या चीन भारी है। यहां नेहरू जो को भी कोट किया गया। मैं भी नेहरू जी की एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। पंडित नेहरू ने 1947 में संविधान सभा में कहा था - चाहे हम कोई भी नीति अपनाएं, विदेश नीति के संचालन की कला इस बात में है कि हम यह मालूम कर सकें कि देश के लिए सबसे अधिक लाभदायक क्या होगा। इंडो-चाइना रिलेशन में भी हमें यह तय करना होगा कि देश के लिए लाभकारी क्या है। इंडिया-आस्ट्रेलिया रिलेशन - भारतीयों पर कई हमले हो गए। आस्ट्रेलिया

सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी था। उस स्टडी में क्या पाया गया कि ये घटनाएं सही हैं या गलत। माननीय मंत्री जी से देश जानना चाहता है कि आस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी ने क्या स्टडी की और क्या पाया। भारतीयों पर हमले हुए या नहीं और यदि हुए तो भारतीयों की सुरक्षा आप किस तरह करेंगे? हाउस यह जानना चाहता है।

मैं अफगानिस्तान के मसले पर एक बात कहना चाहता हूं। वहां तीन घटनाएं हुईं। भारतीयों पर पहला हमला जुलाई, 2000 में हुआ जिसमें साठ लोग मारे गए। मरने वालों में एक भारतीय राजनयिक और एक ब्रिगेडियर भी शामिल था। दूसरा हमला सन् 2009 में हुआ। भारतीय दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया गया। तीसरा हमला सन् 2010 में हुआ। भारतीय चिकित्सा दल को अपना अभियान स्थगित करना पड़ा। बीआरओ (बार्डर रोड आर्गनाइजेशन) वहां एक रोड बना रहा था।...(व्यवधान) आज बीआरओ के लोग अफगानिस्तान जाना नहीं चाहते। बीआरओ बहुत अच्छी रोड बना रहा था। उसे या तो इंसैंटिव दीजिए या सुरक्षा दीजिए चिकित्सा दल भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा अफगानिस्तान के लिए एक कंस्ट्रक्टिव सजैशन है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वहां डैवलपमैंट में ही काम करना चाहते हैं। अमरीका एंटी-टेररिस्ट एक्टीविटीज़ में सम्मिलित है। हम किसके साथ सम्मिलित हैं? अमरीका के साथ सम्मिलित हैं या अफगानिस्तान के साथ सम्मिलित हैं। दुविधा नहीं होनी चाहिए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम।...(व्यवधान)

हमारे बहुत लोग अरब कंट्रीज में रहते हैं। मैं जिस बीकानेर क्षेत्र से आता हूं, वहां के लोग भी रहते हैं। अरब कंट्री में इरान, इराक, कुवैत आदि देश सम्मिलित हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि वहां किसी मजदूर की कैजुअल्टी हो जाती है तो डैड बॉडी प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया बहुत जटिल है। 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं। विदेश मंत्रालय को इस प्रक्रिया को सरल करना चाहिए और कोई ऐसा मकेनिज़्म बनाना चाहिए कि डैड बॉडी चार-पांच दिन में प्राप्त हो जाए। ...(व्यवधान) शनिवार और रविवार को विदेश मंत्रालय बंद होता है। डेड बॉडी प्राप्त करने के मामलों में विदेश मंत्रालय का कोई व्यक्ति शनिवार व रविवार को भी काम करे ऐसी व्यवस्था हो...(व्यवधान) 17 भारतीयों को यूएई की अदालत में मौत की सजा सुनाई गई।...(व्यवधान) एक पाकिस्तानी की मौत पर इतने आदमियों को सजा और भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पंजाब व हरियाणा के लोगों ने हल्ला किया तो सरकार से प्रतिक्रिया आई जबकि ऐसी प्रतिक्रिया स्वतः आनी चाहिए ।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record now.

(Interruptions) ... *

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे विदेश मंत्रालय की निर्माणाधीन अनुदान पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी यहां तमाम सदस्यों ने चर्चा की। इस विश्व में दो तरह के देश हैं - विकासशील देश और विकसित देश। हम विकासशील देश हैं लेकिन यहां चर्चा हुई कि हमें विदेश नीति, कूटनीति को मजबूत करना है। हमारी विदेश नीति, कूटनीति ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारी चाणाक्य नीति होती है। आपको उस प्रकार से बनाना पड़ेगा।

इसी सदन में आस्ट्रेलिया पर चर्चा हुई। हमने जीरोऑवर में इस मामले को उठाया था। आये-दिन समाचार पत्रों में देखने को मिलता है कि वहां जो भी भारतीय छात्र हैं या जो भारतीय वहां व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। हमको उनसे वार्ता करके भारतीयों की रक्षा करनी चाहिए। यह बात आपको जोरदार तरीके से उठानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि सोमालिया में आये-दिन पेपरों में निकलता है कि वहां पर जो भी पानी वाले जहाज आते हैं, हमारे देश के बहुत से लोग विश्व के अन्य देशों में काम करते हैं, इसलिए वे उन जहाजों पर भी रहते हैं। हमारे क्षेत्र के दो लोग वहां गये थे, जो फंसे हुए थे। उनके घरों का बुरा हाल था। सोमालिया में डाकू जहाज में अटैक करते हैं और लोगों को बंधक बना लेते हैं। पड़ोसी देशों के साथ मिलकर उनका भी हमें सफाया करना पड़ेगा।

महोदय, अभी अजनाला जी ने एक बात रखी कि 17 भारतीय लोगों को दुबई में फांसी की सजा सुनायी गयी है। उसके लिए आपको दूतावास में ऐम्बेसडर से बात करनी पड़ेगी और जोरदार तरीकों से भारतीयों की रक्षा के लिए आपको कानूनी सलाह लेकर उनकी सुरक्षा और रक्षा पैरवी करनी होगी। इसी प्रकार मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल में बीपी कोइराला मेडिकल कालेज के नाम से एक मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित है। हमारे यहां के छात्र वहां पढ़ते हैं। अगर वे वहां से पढ़कर आते हैं, तो हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन विदेश से जो आते हैं, उनकी हम स्क्रीनिंग नहीं करते। यह दोहरा मापदंड चलने वाला नहीं है। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा।

महोदय, हम श्री सोमनाथ चटर्जी के साथ ग्रीस गये थे। वहां पर हम लोगों से भारतीय मिले। वे हमसे बोले कि अगर हमारे माता-पिता मरते हैं, तो हमें अपने देश जाना पड़ता है। इसके लिए हमें दूतावास में पैसे देकर वीजा और पासपोर्ट बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए हमे दूतावासों की भी समीक्षा करने की जरूरत है। इसी प्रकार से बंगला देश और पाकिस्तान से तमाम लोग यहां पर आते हैं, लेकिन

* Not recorded

हमारे पास इंटेलीजेंस नहीं है और न ही कोई एजेंसी है। वे लोग वापस अपने देश नहीं जाते। हमारे देश में बंगलादेश और पाकिस्तान से भारी संख्या में जो लोग आये हैं, वे छिपकर यहां पर रहते हैं। उनका आपके पास कोई हिसाब नहीं है।

महोदय, अभी हज के बारे में ओवेसी जी ने कहा। जितने भी लोग हज यात्रा में जाते हैं खासकर जो महिलाएं हैं, उनको आपको पूरी सब्सिडी देनी चाहिए। आप देखिये कि प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सब्सिडी देकर हम उन हाजियों की सुरक्षा- संरक्षा करें, क्योंकि उनकी आस्था और निष्ठा मक्का-मदीना से जुड़ी हुई है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बल देते हुए, समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*__श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):__ महोदय, भारत की विदेश नीति का आधार गुट निरपेक्ष रहा है। आज भी दुनिया में भारत की विदेश नीति का सर्वत्र समर्थन मिल रहा है । दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली से प्रारंभ हुआ । आज पूरे विश्व में प्रजातंत्र को अंगीकार किया है । भारत शुरू से गणतांत्रिक प्रणाली से अपनी व्यवस्था चलाने का प्रयास किया है और आज आजादी के बाद भी भारत पंडित नेहरू के द्वारा प्रतिपादित गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आज डा0 मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कांग्रेस यूपीए सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है । देश में कांग्रेस के बजाये अन्य दलों की भी सरकार सत्ता में आयी लेकिन गुटनिरपेक्ष सिद्धांत सभी केन्द्रीय सरकारों ने अंगीकार किया । भारत की यही गुट निरपेक्ष सिद्धांत ही ताकत है । इसी निति की देन है कि दुनिया के विकसित देश अमेरिका भी भारत का सम्मान कर रहा है । तथा भारत सरकार के द्वारा आतंकवाद के विरूद्ध उठायी गयी कार्य योजना का समर्थन पूरा विश्व कर रहा है । भारत ने अपने पड़ोसी मुल्को से बेहतर रिश्ते बनाने की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । पड़ोस में बढ़ती हुयी आतंकवाद की घटनाओं के बावजूद उनकी अस्थिरता का जवाब सरकारों से वार्ता जारी रखना जिससे उनके मनोबल पर अंकुश लगाया जा सके । पड़ोस में सीमापार से बढ़ते हुये आतंकवाद की घटनाओं में हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान सरकार को कटघरे में खड़ा किया है । तथा पूरी दुनिया से दबाव बनाने के कामयाब हुये है कि पाकिस्तान सरकार अपने सीमा से पल रहे आतंकवादियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करे । मुम्बई के 26/11 की घटनाओं के बाद भी, पाकिस्तान सरकार को तथ्यात्मक सबूत पेश किये जिसे पूरी दुनिया ने सहमति जतायी । भारत के पड़ोस नेपाल में पिछले दिनों घटित राजनैतिक परिवर्तन में हमने अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ किया है । नेपाल के विकास में भारत का सहयोग जारी है । नेपाल में चीन एवं पाकिस्तान की बढ़ती हुयी घटनाओं पर भारत ने नजर पैनी रखी है । क्योंकि भारत नेपाल की सीमा लगभग 1000 किलोमीटर खुली हुयी है । और इस रास्ते जो मुल्क हमें अस्थिर करना चाहते है । वह जाली मुद्रा एवं अवैध हथियारों को भारत में गैरकानूनी ढंग से भेजने का प्रयास कर रहे है । लेकिन नेपाल की वर्तमान सरकार से इधर भारत की मैत्री और मजबूत हुयी है । इसलिए भारत सीमा पार पड़ोसी मुल्कों से जारी आतंकवाद गतिविधियों को नियंत्रण करने में प्रभावी कार्ययोजना बना रही है । पाकिस्तान भी आतंकवाद के खिलाफ विश्व मानचित्र पर कार्यवाही करने का आश्वासन देने के लिए बाध्य हो रहा है । अब स्थिति यहां तक पैदा हो गयी है कि पाकिस्तान में भी लोकतांत्रिक सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती पैदा हो गयी है । यहां तक कि वहां की सरकार को भी खतरा पैदा हो गया है । पाकिस्तान

* Speech was laid on the Table

के भी हित में है कि वह अपने मुल्क में आंतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करे । इसलिए 26/11 की मुम्बई की आतंकवाद घटना के बाद पुनः भारत ने पाकिस्तान से सचिव स्तर पर वार्ता करने की कार्यवाही शुरू की है । जिससे हमारा अपने पड़ोसी मुल्को से रिश्ता मजबूत होगा तथा स्थिति सामान्य बहाल होगी । बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेखहसीना पिछले दिनो भारत के दौरे पर आयी जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश के विकास में रूचि ली है उससे भी रिश्ता मजबूत हुआ है । अंत मे मैं भरत के विदेश मंत्रालय के बजट का समर्थन करता हूं।

SHRI S.M. KRISHNA : Mr. Chairman, I would like to thank all the hon. Members who have participated in this discussion on the functioning of the Ministry of External Affairs. The foreign policy of a country has three pillars. One is to safeguard the enlightened interest of our country; secondly, to extend the areas of friendship with other countries, both in our neighbourhood or the immediate neighbourhood or in an over-reaching neighbourhood. And the third one is to protect the sovereignty of the country.

India like through Pandit Jawaharlal Nehru's time, we have fiercely pursued an independent foreign policy. When the Cold War was at its peak, I remember, the great leader, Shrimati Indira Gandhi, when asked by the Press Corps as to which way she tilted, whether you are tilting to the left or to the right she said, we stand erect; we don't tilt to the left or the right.

We led, along with other like-minded nations, the Non-Aligned Movement in the world. I remember when I was studying in the US, John Foster Dulles, who was then the Secretary of State in the US, dubbed India's foreign policy of non-alignment as something which is to be rejected totally. But as time passed by, countries began to understand, after evaluating the pros and cons of pursuing an independent foreign policy.

There have been a number of speakers who have made very valuable contributions; and there have been speeches which have been critical of the way the External Affairs Ministry has been functioning, in terms of its policy parameters. I take those criticisms very seriously and perhaps try to reflect as to whether they have any justification in the light of our past experience, in the light of what we see things are happening in this world, whether there is any need for us to go in for a course correction, midway through our policy.

Let me refer to certain important points which have been touched about in this debate. My esteemed friend, Shri Murli Manohar Joshi opened the debate. He referred to the need for an integrated approach to foreign policy, which is closely aligned with our security and developmental interests. Nobody can take exception

to this perception. We totally agree with this concept, that the foreign policy must have the security of the country as the core; only when security is ensured, we can think of developmental interests.

I would like to assure Shri Murli Manohar Joshi that our foreign policy is dynamically integrated with our security and developmental interests. Our goals are, by no means, hazy; they are indeed very clear and well-defined; and we wish to safeguard and to ensure our security and pursue the agenda of development that we have taken upon ourselves.

Terrorism is one of the most crucial questions that we, as a country, have been able to fight. Terror is always the one which is not in the interest of the country. But we cannot choose, when terror is unleashed from across the country. All that we can do is to fight that terror. I recall the statement made by the Prime Minister on this very floor – perhaps we can choose our friends, but we cannot choose our neighbours.

Willy-nilly Pakistan happens to be our neighbour but nonetheless in the recent past, efforts have been made by India to open up with Pakistan so that we will be in a position to bring them to talk about terror and then convince them that once the question of terror is addressed by Pakistan, then certainly certain other things will automatically follow. The talks were going on till that crucial attack on Mumbai. India certainly could not have continued with the talks, composite dialogue. So we had to suspend the composite dialogue. Then we had to take other recourse in order to convey the righteous indignation of the people of this country. It was duly conveyed to Pakistan and very recently we again took another initiative on our own, not at prodding of some other country but on our own and that was to invite the Foreign Secretary of Pakistan to come to India so that we could have some talks. Then, the idea of inviting the Foreign Secretary of Pakistan was to convey our serious concerns about terror that is being unleashed from across the border. While we conveyed whatever was needed to be conveyed to the Foreign Secretary of Pakistan, we have agreed with the Foreign Secretary

that we should keep our contacts so that at a future date there could possibly be a return visit of our Foreign Secretary to Pakistan.

Good relations with our neighbours is one of the vital components of our foreign policy. Peace and development in our neighbourhood is essential for our own progress within the country. We have a very constructive and positive dialogue with our neighbours – Bhutan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives and Afghanistan. With Pakistan, as I just mentioned our core concern is the mitigation and removal of terrorism. We want Pakistan to do much more on this front and we have communicated this in our communication with Pakistan as during the recent Foreign Secretary level talks.

A few Members have made a reference to our policy in Afghanistan. India and Afghanistan have a strong relationship based on historical and cultural links. India is actively engaged in assisting the Government of Afghanistan in the reconstruction and development of their country as a means to bringing about stability in Afghanistan. As neighbour of Afghanistan, India cannot remain immune from the developments there. Instability and extremism in the region impacts India's security and development.

Conversely, a peaceful, stable, democratic and prosperous Afghanistan sends a powerful signal to the entire region and beyond. India will, therefore, continue its efforts in assisting the Government and people of Afghanistan towards restoration of stability, reconstruction and development in that country.

Our Government attaches the highest priority to relationships with Nepal. This is evident from the fact that my predecessor Shri Pranab Mukherjee visited Nepal in November, 2008 and I myself visited Nepal in January, 2010. Both of us met with President Dr. Ram Burman Yadav and Prime Minister Mr. Madhav Kumar Nepal visited India in August, 2009 during which we announced an assistance package of about Rs. 2000 crore, which is being implemented. This includes border roads, Integrated Check Posts and two rail links. To discuss security issues, the Home Secretaries of India and Nepal met in Kathmandu in

December, 2009 and Home Minister of Nepal visited India in January, 2010. Besides this, the Defence Minister, the Foreign Minister, the Deputy Prime Minister and Minister of Physical Works and Planning of Nepal, Chief of Army Staff of Nepal have visited India. In addition, Foreign Secretary, Commerce Secretary, Civil Aviation Secretary and Water Resources Secretary have had fruitful meetings. Dr. Ram Burman Yadav, the President of Nepal paid a State visit to India recently in February 2010. Contrary to what has been conveyed, besides meeting with hon. President, Vice President and Prime Minister of India, the Finance Minister, the Home Minister and I myself had the privilege of calling on him. So, I was really surprised when Shri Mulayam Singh Yadav made the comment that we have not been taking Nepal seriously. On the other hand, I would like to say that our engagement with Nepal has been intense and, perhaps, more than with any other neighbour.

Sir, now I come to our relations with China. China is our largest neighbour. There are complex issues in our relationship with China, especially the outstanding boundary question. We believe that dialogue and negotiation are the best ways to resolve outstanding issues with China. Peace and tranquillity are being maintained in the border area with China. We have been open and candid in conveying our concerns to China about such issues as `stapled visas'. But the existence of such problems only underscores the need for us to resolve them not from confrontation but through dialogue and communication. The trade and economic content of our relationship has grown by leaps and bounds in recent years. The mechanism of high level political contact and dialogue has helped to deepen mutual understanding. Co-operation on multilateral issues as on the issue of climate change has also been mutually beneficial.

19.00 hrs.

Our defence and security dialogue has also progressed in recent years. I have just completed, a fortnight ago, a useful visit to China to coincide with the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and China. I had constructive discussions with my counter part, Chinese Foreign Minister Yang and I also met the Chinese Premier Wen. I believe that the policy we have followed in regard to the development of relations with China – a policy whose foundation were laid in 1988 during the historic visit of the late Shri Rajiv Gandhi as Prime Minister to China and which successive Governments have built upon – has worked well for India.

A question was raised by Shri Murli Manohar Joshi about our relationship with Russia. We have a strong, stable and time-tested strategic partnership with Russia which we have strengthened and deepened in the recent past. Our Prime Minister had an excellent meeting with President Medvedev in Brazil last week bilaterally and in the framework of the BRIC Group. Prime Minister Putin came to India in March and we signed several important agreements including a framework on civilian nuclear cooperation. With today's Russia, we continue to deepen relations in strategic sectors like defence, nuclear, space, oil and gas and science and technology. Our policy of multipolar engagement enables us to have meaningful and beneficial relationships with all major powers including Russia and the US.

As regards our relations with the US, as two large democracies, India and the United States have strengthened their strategic dialogue in recent years. The conclusion of the historic Indo-US Civil Nuclear Deal was a significant milestone in the process. There are a number of pillars to our dialogue with the United States including defence and strategic ties, trade and economic ties, educational ties, our energy dialogue and cooperation in such areas as science and technology, climate change and agriculture. President Obama has been invited to visit India later this year. We have been frank and candid in the expression of our concerns

to the United States about assistance given to Pakistan by the United States given the history of such assistance being used against India.

In the context of our counter-terrorism cooperation with the US, we have developed extensive contacts and exchanges with the US agencies concerned. The US administration has told us that they will be sensitive to India's interests when transacting relations with our region. They are also positive about granting direct access to David Coleman Headley in response to our request.

A number of Members have mentioned about our policy on Iran. India and Iran shares the civilisational links that stretch back to centuries. In recent times our historical relations have been imparted a strong economic content. Iran is one of the largest suppliers of our crude oil requirements and it is an important partner in the region, particularly in forging enhanced economic links and greater connectivity with countries in Central Asia and beyond. On the nuclear issue, India's consistent position has been that Iran has the right to peaceful uses of nuclear energy, but at the same time there are also obligations under the NPT. We support the central role of the International Atomic Energy Agency in this regard. In addition, we do not believe in the efficacy of sanctions as they tend to target ordinary people, which will cause them great hardship. We are also of the view that differences should be resolved peacefully and through the process of dialogue.

A number of references have been made to the passport offices. The number of passport seekers in this country has been going up. Despite extensive computerisation and opening of new passport offices, a need was felt for a change in the existing system due to rapidly growing volumes of passport seekers. For instance, between 1999 and 2009, the number of passport seekers more than doubled and this number is expected to grow at an average rate of ten per cent every year.

In order to address this challenge, the Ministry of External Affairs has launched the Passport Sewa Kendras. The project envisages the creation of 77 Passport Sewa Kendras across the country, the creation of call centres operating

24X7 in 17 languages, and the centralised nation-wide computerised system for issuing of passports. The project is almost complete with the establishment of the data centres, disaster recovery centres, central passport printing facility, and network operation centres. Passport Sewa Kendras at seven pilot locations in Bengaluru, Mangalore, Hubli, Chandigarh, Ambala and Ludhiana are going to be established. After five cycles of testing of the application software that has been conducted by the third party audit agency in Bengaluru, it was found that the software was suitable to go for trial run. On March 19, 2010, applications received from the district passport cells were processed in real environment under the PSK software. Since then about 1,000 passports have been issued under the new system. On April 16, 2010 on trial basis, processing of applications live at Passport Sewa Kendra in Bengaluru has also begun. After conducting trials in live environment, it is proposed to open all the seven PSKs for public. After successful pilot phase and its certification that project is scheduled to be rolled out at the remaining seventy remaining PSKs throughout the country.

Some reference was made to the Public Diplomacy Division. After listening to the debate, I would humbly submit that we need a more dispassionate discourse on foreign policy within our own country that reflects our self-confidence and strength. To foster this atmosphere, the Public Diplomacy Division has taken several initiatives and those are lectures in Universities like Benaras, Lucknow, Goa, Hyderabad, Sikkim and Mumbai on India's foreign policy; seminars in Patna on India-Nepal; in Shillong on the North-East and in Kochi on Gulf, etc. to create a more informed discussion and better understanding of the key issues.

Sir, there have been a number of other issues which have been raised but as I find that it is already ten minutes past Seven of the Clock, I would like to keep in touch with the hon. Members with reference to specific points which they have raised. To them, I will communicate our response.

SHRI S.D. SHARIQ (BARAMULLA): Sir, the time of the House may be extended.

MR. CHAIRMAN : The time has already been extended till the Minister's reply is over and the Demand for Grant is passed.

SHRI S.M. KRISHNA: Mr. Chairman, Sir, a reference was made about the Hindi Chairs. I would like to convey to this august House that we have Hindi Chairs in 12 centres abroad; Sanskrit Chair in Thailand, Mongolia and France. All the 28 Indian cultural centres abroad also teach Hindi and the Indian culture.

Sir, these are some of the demands made by the Members. I have utilized this occasion to make the position clear. I will again assure the august House that all the constructive suggestions will be taken note of and then, in the course of the coming years, we will try to incorporate those in our policy framework.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demand for Grant relating to the Ministry of External Affairs to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand No.31 relating to the Ministry of External Affairs."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 21st April, 2010 at 11 a.m.

19.13 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 21, 2010/Vaisakha 1, 1932 (Saka).